



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 359]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 6, 2008/आश्विन 14, 1930

No. 359]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 6, 2008/ASHVINA 14, 1930

वाणिज्य एवं वनों मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 2008

अंतिम जांच परिसर

विषय : जर्मनी तथा कोरिया गणराज्य के मूल के/से निर्यातित एक्रिलोनाइटाइल ब्यूटाडीन रबर (एनबीआर) के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा (2)।

सं. 15/6/2007-डीजीएडी—1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम कहा गया है) एवं सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम (जिसे एतदपश्चात नियम भी कहा गया है), 1995 की ध्यान में रखते हुए,

क. पृष्ठभूमि

2. यतः, उपर्युक्त नियमावली को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात प्राधिकारी कहा गया है) ने मेसर्स अपार इण्डस्ट्रियल लिमिटेड, मुम्बई, की भारत में घरेलू उत्पादक हैं, द्वारा प्रस्तुत आवेदन के भारत में घरेलू उत्पादक हैं, द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर दिनांक 4 अक्टूबर, 2001 की जांच शुरुआत अधिसूचना द्वारा कोरिया गणराज्य एवं जर्मनी (जिन्हें एतदपश्चात संबद्ध देश कहा गया है) से भारत में एक्रिलोनाइटाइल ब्यूटाडीन रबर (एनबीआर) के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की थी।

3. और, यतः, दिनांक 21 सितंबर, 2002 की अधिसूचना सं. 50/1/2001 द्वारा प्राधिकारी का निष्कर्ष था कि कोरिया गणराज्य एवं जर्मनी से एनबीआर पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त करने से पाटन एवं क्षति जारी रहेगी और उसकी पुनरावृत्ति होगी; और संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की थी। संबद्ध वस्तुओं पर दिनांक 10 अक्टूबर, 2002 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 111/2002-सीमाशुल्क द्वारा अधिसूचना की तारीख से आगे 5 वर्ष की अवधि हेतु निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था (इसे दिनांक 1 सितम्बर, 2005 की अधिसूचना सं. 78/2005-सीमाशुल्क एवं दिनांक 31 जनवरी, 2007 की अधिसूचना सं. 11/2007-सीमाशुल्क द्वारा अधिक्रमित किया गया था)।

- 4 यतः मेसर्स अपार इण्डस्ट्रीज लि०, मुंबई के विधिवत प्रलेखित आवेदन के आधार पर प्राधिकारी ने, यह जांच करने के लिए कि क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त करने से पाटन एवं क्षति जारी रहेगी अथवा उसकी पुनरावृत्ति होगी, संबद्ध देशों से उद्गमित संबद्ध उत्पाद के आयात पर उक्त अधिनियम की धारा 9 क (5) के अंतर्गत दिनांक 8 अक्टूबर, 2007 की अधिसूचना द्वारा पाटनरोधी शुल्क की दूसरी निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत की थी।
- 5 और यतः केंद्र सरकार ने दिनांक 9 अक्टूबर, 2007 की अधिसूचना सं. 109/2007 - सीमाशुल्क द्वारा निश्चयात्मक शुल्क धारा 9 क(5) के अंतर्गत दिनांक 9 अक्टूबर, 2008 तक एक वर्ष की अवधि हेतु बढ़ा दिया था।

ख प्रक्रिया

- 6 इस जांच के संदर्भ में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया:-
 - I. समीक्षा की शुरुआत के पश्चात प्राधिकारी ने अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के लिए नियम 6(4) के अंतर्गत प्रश्नावली तथा जांच शुरुआत अधिसूचना की प्रतियां संबद्ध देशों के सभी ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों तथा भारत में घरेलू उद्योग को भिजवाई थीं।
 - II. नियम 6(2) के अनुसरण में संबद्ध देशों के नई दिल्ली स्थित दूतावासों/उच्चायोगों/प्रतिनिधियों को जांच शुरुआत के बारे में सूचित किया गया था और उनसे अपने-अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित अवधि के भीतर प्रश्नावली के उत्तर भिजवाने की सलाह देने का अनुरोध किया गया था।
 - III. नियम 6(4) के अनुसरण में आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध करते हुए भारत में संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात आयातकों व उपभोक्ताओं को प्रश्नावलियां भिजवाई गई थीं,
 - IV. जांच दिनांक 01.04.2006 से लेकर 31.03.2007 तक की अवधि (जांच अवधि) के लिए की गई। तथापि क्षति की जांच वर्ष 2003-04 से जांच अवधि (शामिल) तक की गई।
 - V. वार्षिक आसूचना एवं वार्षिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से पिछले तीन वर्षों तथा जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के आयातों का ब्योरा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया,

VI. कोरिया गणराज्य के निम्नलिखित दो निर्यातकों से जांच शुरूआत अधिसूचना का उत्तर प्राप्त हुआ :-

- क) कोरिया कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स क. लि.(जिसे एतदपश्चात् केकेपीसी कहा गया है),
- ख) एलजीकेम लि.(जिसे एतदपश्चात् एलजीसी या एल जी कहा गया है)

जर्मनी के किसी निर्यातक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ :

VII. अखिल भारतीय रबड उद्योग एसोसिएशन (जिसे एतदपश्चात् एआइआरआईए कहा गया है) एवं ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ फुटवेयर मैनुफैक्चरर्स ने भी हितबद्ध पक्षकारों के रूप में अपने-अपने उत्तर प्रस्तुत किए:

VIII. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा व्यक्त एवं प्रस्तुत टिप्पणियों पर, जिस सीमा तक वे वर्तमान जांच से सुसंगत पाए गए, विचार किया है:

IX. प्राधिकारी ने क्षति की जांच करने और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर इष्टतम उत्पादन लागत और भारत में संबद्ध वस्तुओं के निर्माण व बिक्री की लागत की गणना करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का सत्यापन किया और यह अभिनिश्चित करने कि क्या घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क पर्याप्त होगा: आवेदक द्वारा प्रदत्त सूचना का सत्यापन किया:

X. हितबद्ध पक्षों को मौखिक रूप से सुनने के लिए प्राधिकारी द्वारा दिनांक 17.06.2008 को एक सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया गया था, जिसमें घरेलू उद्योग के प्रतिनिधि, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के निर्यातक एवं अन्य हितबद्ध पक्ष उपस्थित थे। सार्वजनिक सुनवाई में उपस्थित पक्षों से मौखिक रूप से व्यक्त विचारों को लिखित में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। हितबद्ध पक्षों से प्राप्त लिखित निवेदनों पर प्राधिकारी ने इस जांच परिणाम में विचार किया गया है :

XI. इस मामले के अनिवार्य तथ्यों से सभी हितबद्ध पक्षों को गोपनीय तथा सामान्य प्रकटीकरण के माध्यम से अवगत कराया गया। प्रकटीकरण विवरण में हितबद्ध पक्षों द्वारा की गई टिप्पणियों पर, जिस सीमा तक वे सुसंगत थीं अथवा साक्ष्य द्वारा समर्थित थीं, प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है :

XII. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय पाठ सार्वजनिक फाइल के रूप में रखा गया और उसे हितबद्ध पक्षों को अवलोकनार्थ उपलब्ध

कराया गया। इस अधिसूचना में ***एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीयता के आधार पर प्रस्तुत सूचना प्रदर्शित करती है, जिसे नियमावली के अंतर्गत गुणदोषों के आधार पर प्राधिकारी ने गोपनीय माना है।

ग. विचाराधीन उत्पाद एवं "समान" वस्तु

- 7 मूल जांच में शामिल उत्पाद एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडीन रबड़ (एनबीआर) था जो उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के अध्याय 40 तथा आईटीसी एचएस वर्गीकरण के शीर्ष सं. 40025900 के अंतर्गत आता है। एनबीआर का प्रयोग रबड़ की विभिन्न वस्तुओं जैसे ऑयल सील्स, होज, आटोमोटिव उत्पादों, गोस्केट्स, चावल की चोकर हटाने के रोल, प्रिंटरों, कपड़े, ऑयलफील्ड उत्पादों आदि के विनिर्माण में किया जाता है, जिनमें तेल, घिसाई तथा उष्मा से प्रतिरोध जरूरी होता है। एनबीआर के लिए जरूरी प्रमुख कच्चा माल एक्रिलोनाइट्राइल तथा ब्यूटाडीन है। एनबीआर के विभिन्न ग्रेडों को मूनी श्यानता एवं एक्रिलोनाइट्राइल की उपस्थिति के आधार पर परिभाषित किया जाता है। यद्यपि इसके अनेक ग्रेड होते हैं, तथापि प्राधिकारी ने मूल जांच में यह उल्लेख किया था कि किसी भी ग्रेड की जांच के दायरे से बाहर रखना उचित नहीं होगा। चूंकि यह निर्णायक जांच समीक्षा है, अतः इस जांच का दायरा मूल जांच के पहले से अभिज्ञात उत्पाद तक ही सीमित है। तथापि वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं हैं। वर्तमान जांच में किसी भी हितबद्ध पक्ष ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के मुद्दे पर कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं का प्रयोग संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के स्थान पर परस्पर किया जाता है। अतः प्राधिकारी का अभिमत है कि नियमावली के अर्थ के भीतर दोनों "समान वस्तुएं" हैं।

घ. घरेलू उद्योग की स्थिति

- 8 निर्णायक समीक्षा की शुरुआत घरेलू उद्योग की ओर से एकमात्र घरेलू उत्पाद मेसर्स अपार इण्डस्ट्रीज लि., मुम्बई द्वारा विधिवत साक्ष्ययुक्त अनुरोध के आधार पर की गई है। समीक्षा हेतु आवेदन करते समय उत्पादन सुविधाओं का स्वामित्व अपार इण्डस्ट्रीज के पास था। फरवरी 2008 में मेसर्स एलियोकेम इंडिया प्रा.लि. (जिन्हें एतद्पश्चात् ईआईपीएल कहा गया है) ने उत्पादन सुविधाएं खरीदकर अपार इण्डस्ट्रीज की रबड़ प्लांट पॉलीमर यूनिट का अधिग्रहण कर लिया और उत्पादन के प्रबंधन एवं उसमें उत्पादित एनबीआर की खरीद का दायित्व संभाल लिया।

- क) **जोय शुरूआत के बारे में**
9. **घरेलू उद्योग ने बाधा किया है कि अधिग्रहण के प्रारंभिक प्रस्तावों के अंतर्गत अपार इण्डस्ट्रीज के स्वामित्व की उत्पादन सुविधा का अधिग्रहण करवा 1988 से इपीआईएल द्वारा कर लिए जाने के बावजूद नियमावली के अर्थ के भीतर वही घरेलू उद्योग हैं। केकेपीसी का मत है कि अधिग्रहण पर प्राधिकारी द्वारा विस्तृत निष्पत्ति की जा रही है और ऐसा कभी नहीं होता है कि यह सार्वजनिक एनबीआर को नुकसान पहुंचाए।**
10. **अधिकांश अलावा यह कि एनबीआर स्वयंसेवा के अलावा मुख्य निष्कर्ष है अपार इण्डस्ट्रीज द्वारा निर्णायक समीक्षा में क्षति के बारे में कि यह गलत सूचना पर आधारित है। यह कह दिया है अतः इपीआईएल को मुख्य निष्कर्ष का खोला, उच्च विधिकरण रिपोर्ट, एनबीआई को प्रस्तुत दस्तावेज, निजी खरीद कार्रवाई तथा अधिग्रहण से संबंधित अन्य दस्तावेज, अधिकारी को जान देते प्रस्तुत किए जाने चाहिए। घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि अधिग्रहण कम हिलान अधिग्रही कंपनी की व्यावसायिक योजनाओं पर आधारित होते हैं और पाटनरोधी जांच को जांच अधिकारी के दौरान सम्पत्तिगत सूचना से संबंधित है जो इसका कोई संबंध नहीं है। यदि एनबीआर प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो अपार इण्डस्ट्रीज द्वारा खोली गई यूनिटों की बिक्री नहीं की जाती।**
10. **केकेपीसी ने आगे यह भी कहा है कि अपार इण्डस्ट्रीज के एनबीआर भाग के क्षति संबंधी मानदण्ड ईआईपीएल पर लागू नहीं होंगे क्योंकि यह समीक्षा की जांच अवधि के दौरान अस्तित्व में ही नहीं था। चूंकि नई सत्ता पुरानी सत्ता की परिसंपत्तियों का प्रयोग करते हुए अस्तित्व में आई अतः पुरानी सत्ता के क्षति मानदण्ड नई सत्ता के लिए अपनाए नहीं जा सकते। अतः वर्तमान समीक्षा जांच को समाप्त किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, चूंकि अपार का आवेदन, जिस पर यह समीक्षा शुरू की गई थी, परिसंपत्तियों की बिक्री के कारण निष्फल हो गया है और अस्तित्वहीन आवेदन के आधार पर समीक्षा को जारी नहीं रखा जा सकता। एआईआईएल का विचार था कि समीक्षा यांचिका मुख्यतः अपार इण्डस्ट्रीज द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जो अब सामान्य नहीं है। अतः समीक्षा की कार्यवाही समाप्त करके शुल्क वापस ले लिया जाए। घरेलू उद्योग ने उत्तर दिया है कि नियमावली के अंतर्गत क्षति की विश्लेषण संबंधित सर्वेक्षण के क्रम में किया जाता है न कि संपूर्ण कंपनी अधिग्रहण क्षति अधिग्रहण के लिए। चूंकि ईआईपीएल द्वारा अपार इण्डस्ट्रीज को लीज यूनिट के अधिग्रहण की अनुमति में सभी परिसंपत्तियां, देयताएं, अधिकार, सविदाएं तथा रिहाई भी ईआईपीएल द्वारा अपनाए गए हैं अतः एनबीआर से संबंधित क्षति मानदण्ड भी उस पर लागू होंगे। इसके अलावा जांच एक बार शुरू किए जाने पर उसे केवल पाटनरोधी नियमावली के नियम 14**

के अंतर्गत ही समाप्त किया जा सकता है। यदि प्राधिकारी को घरेलू उद्योग से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त होता है अथवा पाटन एवं क्षति के साक्ष्य के अभाव से संतुष्ट हों अथवा पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के 2% से कम हो अथवा संबद्ध देशों से अलग-अलग लेखाबद्ध पाटित आयातों की मात्रा उस उत्पाद के आयात के 3% से कम हो।

(ख) गोपनीयता के बारे में

- 11 घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि दोनों कोरियाई निर्यातकों ने अपनी-अपनी वार्षिक रिपोर्टों के केवल चुनिंदा उद्धरण उपलब्ध कराए हैं और कतिपय परिशिष्ट एवं सूचक आधार उपलब्ध नहीं कराए हैं। इसके प्रत्युत्तर में केकेपीसी तथा एलजीसी दोनों का तर्क है कि घरेलू उद्योग सबसे पहले अपनी याचिका का समुचित अगोपनीय पाठ उन्हें टिप्पणियों हेतु उपलब्ध कराएं। चूंकि इस उद्योग ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया था अतः वह इस मुद्दे को उठा नहीं सके थे। घरेलू उद्योग द्वारा उल्लिखित परिशिष्ट कंपनी की लागत सूचना से संबंधित है, जिसके बारे में स्वयं घरेलू उद्योग ने अपनी लागत सूचना संबंधी अगोपनीय पाठ प्रस्तुत नहीं किया है। सभी नियम तथा प्रक्रियाएं जांच से संबंधित सभी पक्षों पर एक समान तरीके से लागू होनी चाहिए; न कि केवल निर्यातक पर। केकेपीसी ने कहा है उन्होंने वार्षिक खातों के बारे में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध सभी सूचना प्रदान कर दी है और वित्तीय विवरणों का केवल वही ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया है जो सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है।

(ग) शुल्क के निर्धारण के संबंध में

- 12 घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि केकेपीसी पर एक उत्पादक-निर्यातक के रूप में और उत्पादक के रूप में केकेपीसी पर किसी अन्य निर्यातक के साथ समान दर पर शुल्क लगाया जाता है जो सही नहीं है क्योंकि केकेपीसी के साथ किसी भी अन्य निर्यातक पर शुल्क शेष दर से लगाया जाना चाहिए। तथापि केकेपीसी में तर्क दिया है कि (i) पाटन मार्जिन की गणना कारखाना द्वार स्तर पर की गई थी और भारत से किए गए सभी सौदों पर भी विचार किया गया था, चाहे वे प्रत्यक्ष रहे हों अथवा किसी अन्य पक्ष के मार्फत, ताकि अमेरिका के वाणिज्य विभाग द्वारा अपनाई गई पद्धति के अनुसार केकेपीसी हेतु निर्धारित दर इसके सभी सौदों पर लागू हो। (ii) चूंकि केकेपीसी को बिक्री के समय यह ज्ञात था कि ये वस्तुएं भारत को निर्यात हेतु आश्रयित हैं क्योंकि वे सीधे भारत जाती हैं और व्यापारी को केवल बीजक उसके पक्ष में दिया जाता है, अतः बिक्री कीमतें भारत को निर्यात कीमत दर्शाती हैं। अतः केकेपीसी की दरें ही लागू की जानी चाहिए, चाहे व्यापारी कोई भी हो।

घ) आयात संबंधी आंकड़ों के बारे में

- 13 केकेपीसी चाहता है कि डीजीआई एंड एस के सीधेदार आयात आंकड़े सार्वजनिक फाइल में रखे जाएं। इसके उत्तर में घरेलू उद्योग ने कहा है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है, यदि प्राधिकारी ये आंकड़े सार्वजनिक प्रदर्शनार्थ रखना चाहें और डीजीआई एंड एस को भी कोई आपत्ति न हो, परंतु निर्यातक के पास ऐसे अनुरोध का कोई कारण नहीं है क्योंकि निर्यात कीमत के बारे में उसके पास उसकी अपनी सूचना उपलब्ध है। प्राधिकारी ने निर्यातक का अनुरोध डीजीसीआई एंड एस को सूचनार्थ भिजवाने की इच्छा व्यक्त की थी परंतु केकेपीसी से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।

13.1 प्रकटन विवरण के बाद केकेपीसी ने यह बताया है कि घरेलू उद्योग द्वारा कोई आपत्ति न किए जाने के बादवजूद डीजीसीआईएस के इन आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया गया है कि केकेपीसी को यह जरूरत है कि प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़े सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध किए जाने चाहिए जो निर्णय का आधार हैं। तथापि प्राधिकारी ने निर्णय लेने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया है बल्कि उन्हें जांच के बाद डीजीसीआईएस से प्राप्त किया है और सम्स्त आंकड़ों को भात्रात्मक प्रभाव के तहत सूचित किया गया है।

ङ पिछली जांच कार्रवाई में उत्तर प्रस्तुत न करना

- 14 घरेलू उद्योग का कहना है कि एलजीसी पिछली जांच कार्रवाई के दौरान उत्तर प्रस्तुत न करने के कारणों का खौरा दें। यह पूछने के घरेलू उद्योग के अधिकार का प्रतिवाद करते हुए एलजीसी ने घोषित किया कि एनबीआर का उत्पादन जनवरी 2005 में एलजी डायमंड पेट्रोकेमिकल्स लि. के अधिग्रहण और तत्पश्चात जनवरी 2006 में इसके विलय के बाद ही शुरू हुआ था। अधिग्रहण से पूर्व एनबीआर न तो एलजीसी के स्वामित्व में था, न इसके किसी संबद्ध फर्म के।

च) गीण उत्पादों पर प्रभाव के बारे में

- 15 एआईआरआईए ने निवेदन किया है कि एनबीआर से विनिर्मित वस्तुओं का प्रयोग आम जनता द्वारा किया जाता है और विनिर्माण मुख्यतः एसएसआई यूनिटों द्वारा किया जाता है। भारतीय रबड़ उद्योग में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कुल रोजगार लगभग 2 मिलियन का है। 2 मिलियन कामगारों और आम जनता की कीमत पर मात्र एक विदेशी कंपनी के हितों के संरक्षण के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाना न्याय

की विडम्बना होगी और इससे आम जनता के लिए आशयित उत्पाद की कीमत में वृद्धि होगी और यह मुद्रास्फीति को रोकने की सरकार की घोषित नीति के विरुद्ध होगा। इसके अलावा रबड़ उत्पादों का निर्यात सीमांत लागत के आधार पर किया जाता है अतः निर्यात कीमत के निर्धारण को बनाए रखने के लिए इस उद्योग के अलावा एक व्यवहार्य घरेलू बाजार उपलब्ध होना चाहिए। तेल आधारित सभी उत्पादों की कीमतें अधिक होने के कारण यह उद्योग निविष्टि लागत में वृद्धि से पहले ही जूझ रहा है और पाटनरोधी शुल्क लगाने से निर्यात की संभावना पंगु हो जाएगी। इसके अलावा भारतीय विनिर्माता रबड़ उद्योग हेतु अपेक्षित सभी ग्रेड के नाइट्राइल रबड़ का विनिर्माण नहीं करते, जिसकी आवश्यकता रबड़ आटो संघटकों के विनिर्माण में होती है, अतः प्रमुख कच्चे माल पर शुल्क लगा देने से इस क्षेत्र में वृद्धि की संभावना धूमिल हो जाएगी और परिणामस्वरूप निविष्टि लागत में वृद्धि होगी।

(घ) व्यापार करारों के बारे में

16. एआईआरआईए ने कहा है कि भारत एशिया प्रशांत व्यापार करार(एपीटीए) को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है जिसमें जहां एक ओर दक्षिण कोरिया सहित इन देशों के साथ व्यापार पर अधिमानी टैरिफ का अनुरोध किया गया है और दूसरी ओर प्राप्त इसी देश से एनबीआर के आयातों पर अतिरिक्त शुल्क लगा रहा है, जबकि यह मद एपीटीए में शामिल है।

प्रकटन विवरण के पश्चात टिप्पणियां

(क) नाम में परिवर्तन के बारे में

17. केकेपीसी ने प्राधिकारी से यह अनुरोध किया है कि वह उनकी कंपनी का सही नाम कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के रूप में नोट करके और व्यवहारिक कठिनाइयों से बचने के लिए अंतिम जांच परिणामों में इसी नाम का उपयोग करें। तथा प्राधिकारी ने यह नोट किया कि उसने जून, 2008 में कंपनी से नई कंपनी के निगमन प्रणाम पत्र, परिवर्तन से पूर्व और पश्चात प्रचालन संरचना तथा शेयरधारिता की पद्धति की एक प्रति उपलब्ध राने के लिए कहा था ताकि परिवर्तन की जांच की जा सके। चूंकि इन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया था इसलिए प्राधिकारी निर्यातक द्वारा प्रस्तुत उत्तर में उल्लिखित नाम को बनाए रखने के लिए बाध्य हुए हैं।

(ख) अन्य पहलू

18. ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ रबड़ फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स की टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दिया गया है क्योंकि ये टिप्पणियां विवरण में निहित तथ्यों के अनुरूप नहीं थीं।

क 2 प्राधिकारी द्वारा जांच

19. प्राधिकारी ने इस समीक्षा जांच की शुरुआत के संबंध में और एनबीआर उत्पादन सुविधा के स्वामित्व में परिवर्तन से संबंधित दस्तावेजों के बारे में हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए निवेदनों की जांचावनी से जांच की है। चूंकि अपार इण्डस्ट्रीज पॉलीमर यूनिट की सभी परिसंपत्तियों एवं हेतुओं का अधिग्रहण ईआईपीएल द्वारा कर लिया गया है, अतः प्राधिकारी का अभिमत है कि ईआईपीएल वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग है। इसके अलावा हितबद्ध पक्षों द्वारा, जांच के दौरान प्रस्तुत सभी तर्कों एवं किए गए निवेदनों की भी, जांच में उनके सुसंगत होने की सीमा तक प्राधिकारी ने जांच की है और इस जांच परिणाम में उनका विरलेषण यथास्थान किया है।

घ पाटन का निर्धारण

20. पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित धारा 9 क(5) में प्रावधान है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की समय-समय पर समीक्षा करेंगे और यदि वह उन्हें प्राप्त सूचना से संतुष्ट है कि ऐसा शुल्क लगाए रखने का कोई औचित्य नहीं है तो वह केंद्रीय सरकार को इसे वापस लेने की सिफारिश करेंगे। अतः प्राधिकारी के सम्मुख जांच योग्य मुद्दे निम्नानुसार हैं—

● यदि निरवधारक शुल्क हटा दिया जाता है अथवा समाप्त कर दिया जाता है तो क्या पाटन के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना है,

● यदि निरवधारक शुल्क हटा दिया जाता है अथवा समाप्त कर दिया जाता है तो क्या घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने अथवा इसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। अतः जांच के दौरान प्राधिकारी ने निम्नलिखित पैराग्राफों में किया गया है।

घ. 1 हितबद्ध पक्षों के विचार

क) उत्पादन लागत के बारे में

21. श्री ए. जे. जे. ने निवेदन किया है कि निर्यातक, केकेपीसी ने ब्यूटाडाइन का अस्तेछाईत मात्रा में उत्पादन वा खरीद की भी। ब्यूटाडाइन की आवश्यकतानुसार 50% की खरीद की गई और शेष का आबद्ध उत्पादन किया गया। आरआईएल मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार आबद्ध ब्यूटाडीन का अंतरण मूल्य उत्पादन लागत पर निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे बाजार मूल्य पर किया जाना चाहिए ताकि ब्यूटाडीन का लाभ घरघर्ती उद्योगों को मिलने से बचाया जाए। परंतु केकेपीसी ने आरआईएल मामले के निर्णय को कच्चे माल की कीमत पर लागू करने का प्रतिवाद इस आधार पर किया है कि (i) यह निर्णय क्षति रहित कीमत (एनआईपी) के निर्धारण पर लागू होता है न कि सामान्य मूल्य

पर और यह कि पाटनरोधी नियमावली में यह प्रावधान है कि सामान्य मूल्य में लागत का निर्धारण निर्यातक/उत्पादक के रिकार्ड के आधार पर किया जाना चाहिए, यदि वह निर्यातक देशों में सामान्यतया आधारित लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हो। इसके अलावा कच्चे माल का मूल्य निर्धारण सतत औसत के आधार पर किया गया और रिकार्ड कोरिया के जीएपीपी के अनुसार रखे गए थे। एलजीसी ने यह भी कहा है कि पिछली जांचों में डीजीएडी ने आबद्ध रूप से उत्पादित कच्चे माल के मामले में अंतरण मूल्य को उत्पादन लागत के रूप में अपनाया था क्योंकि नियमावली में उचित बाजार मूल्य का कोई उल्लेख नहीं किया गया है और निर्यातकों की लागत के संदर्भ में घरेलू उद्योग का निर्वाचन लागू नहीं किया जा सकता।

22. घरेलू उद्योग का मत है कि केकेपीसी ने उत्पादन लागत को कम बताने और सामान्य मूल्य को प्रभावित करने के उद्देश्य से उत्पाद की ब्याज लागत का गलत दावा प्रस्तुत किया है और यह कि ब्याज से हुई आय को ब्याज लागत से घटाया नहीं जा सकता। केकेपीसी ने ऐसे सेंट-ऑफ करने का खण्डन किया है।
23. घरेलू उद्योग ने आरोप लगाया है कि केकेपीसी ने अंतर्देशीय मालभाड़े का दावा अलग-अलग बिक्री सौदों से अभिज्ञात किए बिना किया और पैकिंग लागत किए गए वास्तविक व्यय पर आधारित नहीं थी। केकेपीसी का मत है कि अंतर्देशीय मालभाड़े का दावा वास्तविक मालभाड़ा व्यय पर आधारित है और पैकिंग लागत की गणना, वास्तविक लागत के आधार पर की गई है।
24. घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि (क) सभी प्रकार के बच्चे माल की लागत, खपत मानदण्डों, उपयोगिता लागत, परिवर्तन लागत, ब्याज लागत के रूप में केकेपीसी की उत्पादन लागत की गहराई से जांच की जानी चाहिए, (ख) कि घरेलू बिक्री व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के दौरान होनी चाहिए, (ग) कीमत समायोजन, अलग-अलग सौदों और उत्पादन लागत से संबद्ध होने चाहिए और पैकिंग के बारे में पिछले विवाद को देखते हुए बिक्री कीमत का निर्धारण नियत पैकिंग लागत पर आधारित होना चाहिए, (घ) कि लाभ केंद्र दृष्टिकोण की परिणति उत्पादन लागत को कम बताने में हो सकती है। केकेपीसी ने इन तर्कों को आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया है और कहा है कि इनका सत्यापन निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किया जा सकता है।
25. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि एलजीसी ने ब्याज और एसजीए लागत का दावा वास्तविक तथा टर्नओवर के आधार पर किया है जबकि इसका निर्धारण केवल टर्नओवर आधार पर किया जाना चाहिए था। एलजीसी ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि उनकी एसएपी प्रणाली में सबसे पहले उत्पाद से सीधे तौर पर जुड़ी लागतों को अभिज्ञात कर लिया जाता है और जो लागतें उत्पाद से

जुड़ी नहीं होती उसका संविभाजन टर्नओवर आधार पर किया जाता है, जो उत्पाद लगत गणना के आधारभूत सिद्धांतों के अनुरूप है।

ख) समायोजन के बारे में

26. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि आरआईएल मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार दोनों कोरियाई निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य एक समान होना चाहिए, परंतु केकेपीसी का तर्क है कि कोरिया के लिए भारत औसत समान मूल्य निकालने के बाद निर्यात कीमत में आवश्यक समायोजन किए जाने चाहिए ताकि इसे तुलनीय बनाया जा सके। इस पर घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि कारखाना-द्वारा स्तर पर कोरिया में भारत औसत सामान्य मूल्य की तुलना अलग-अलग निर्यातकों की वास्तविक निर्यात कीमत से करना उचित तुलना है और केकेपीसी द्वारा मूल्य की तुलना को प्रभावित करने वाले सभी कारकों को अभिज्ञान किया जाना और तुलना उचित अथवा अनुचित होने का दावा कथने के लिए उन्हें अपने खर्चों में समायोजनों को मात्रात्मक रूप में व्यक्त करने की आवश्यकता है, जिसका सत्यापन प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।
27. घरेलू उद्योग ने कहा है कि निर्यातक के पिछले इतिहास को देखते हुए उसके समायोजन का दावा अपनाए से पूर्व उसका सत्यापन किया जाए। केकेपीसी ने इन समायोजनों का सत्यापन कराने की पेशकश की।
28. घरेलू उद्योग ने उल्लेख किया है कि प्रश्नावली के उत्तर में (i) शुल्क प्रति अदायगी के दावे का सत्यापन किया जाना चाहिए, (ii) एनबीआर में सामान्य व्यय प्रभावित किया गया है, (iii) ओबद्ध कच्चे माल का ब्योरा अलग से दिया जाना चाहिए, (iv) प्री एफओबी समायोजन अत्यधिक है जबकि निर्यातों से संबंधित समायोजन कम प्रतीत होते हैं। केकेपीसी ने इन तर्कों को आधारहीन बताया है और घोषित किया है कि प्रदान की गई सभी सूचना सही है, और यह कि भारतीय डीईपीबी स्कीम तथा अग्रिम लाईसेंस स्कीम का स्वरूप व प्रचालन प्रक्रिया भारत अथवा कोरिया की शुल्क प्रति अदायगी स्कीमों से भिन्न है और अन्य देशों में, की गई प्रति अदायगी के दावे का समायोजन करने की अनुमति है। एलजीसी ने इस तर्क का समर्थन किया है और मत व्यक्त किया है कि ऐसे समायोजन की अनुमति देना डीजीएडी द्वारा अपनाई गई पद्धति है, जब यह कच्चे माल के आयात व उत्पाद के निर्यात से जुड़ा हुआ हो।
29. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि कोरिया के निर्यातक पाटित कीमतों पर भारत को निर्यात कर रहे हैं। केकेपीसी ने इस दावे का प्रतिवाद किया है और कहा है कि उनके खर्चों के सत्यापन से सिद्ध हो जाएगा कि कोई पाटन नहीं किया गया है और पाटन की कोई संभावना भी नहीं है। तथापि घरेलू उद्योग का कहना है कि की गई सभी जाँचों में केकेपीसी ने दावा किया था कि कोई पाटन नहीं किया गया

है परंतु प्राधिकारी द्वारा पाटन न्यूनतम से अधिक पाया गया था। इसके अलावा, शुल्क लगाए जाने के बावजूद केकेपीसी भारत को आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है।

घ.2 कोरिया गणराज्य

30. समीक्षा जांच की शुरुआत के बाद कोरिया गणराज्य के दो उत्पादक-निर्यातकों अर्थात् कोरिया कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स एवं एलजी-केम ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए थे। नियमावली के अनुसरण में, इन सहयोगी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत लागत संबंधी आंकड़ों की जांच की गई थी और जंझ रिपोर्ट निर्यातकों को उनकी टिप्पणियों हेतु भिजवा दी गई थी। निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर इन निर्यातकों हेतु पाटन मार्जिन की गणना की गई है।
31. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने मेसर्स आरआईएल बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी एवं अन्य से संबंधित 2001 की सिविल अपील सं. 1294 में कहा था कि सामान्य मूल्य निर्यातक विशिष्ट नहीं होता बल्कि निर्यातक देश विशिष्ट होता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू बाजार में सहयोगी निर्यातकों की बिक्री की स्थितियां भिन्न होने के कारण निर्यातक देश में भारित औसत सामान्य मूल्य अत्यंत-विकृत परिणाम प्रस्तुत करता है। तथापि ऊपर उल्लिखित मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में संबद्ध देशों के लिए संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य का निर्धारण सर्वप्रथम अलग-अलग सहयोगी निर्यातक के लिए किया गया और फिर अलग-अलग सामान्य मूल्यों के आधार पर समस्त निर्यातक देश के लिए विद्याराधीन उत्पाद हेतु एक भारित औसत सामान्य मूल्य की गणना की गई।

घ.2.1 कोरिया कुम्हो-पेट्रोकेमिकल्स कं.(केकेपीसी), कोरिया गणराज्य सामान्य मूल्य

32. केकेपीसी एक सीमित देयता वाली कंपनी है, जो***ग्रुप की सदस्य है और इसकी स्थापना ***में कोरिया के वाणिज्यिक कानून के अंतर्गत की गई थी। यह कंपनी पेट्रोकेमिकल उत्पादों जैसे सिन्थेटिक रबड़ और लेटेक्स के विनिर्माण एवं बिक्री में संलग्न है। केकेपीसी का विलय***में हो गया था और इसने ***रासायनिक व्यवसाय क्षेत्र को अधिग्रहित कर लिया था। केकेपीसी का स्टॉक कोरिया के स्टॉक एक्सचेंज में 1988 से सूचीबद्ध है। इसका निगमित कार्यालय सियोल में है और उत्सान स्थित इसके कारखाने में एनबीआर का उत्पादन किया जाता है।
33. इसकी उत्पादन प्रक्रिया में दो प्रकार के प्राथमिक कच्चे माल अर्थात् एक्रिलोनाइट्राइल एवं ब्यूटाडीन की अभिक्रिया से एक तरल पॉलीमर उत्पन्न होता है, जिसे कोएग्युलेट करके, सुखाकर इसे एनबीआर बेल के रूप में पैक कर दिया जाता है। ब्यूटाडीन का उत्पादन "इन आऊस" और खरीद स्थानीय स्तर पर तथा

2000 के आसपास करके की जाती है। जबकि एकीकृत बाजार की खरीद-विक्री के लिए यह की जाती है।

34. केकेपीसी के समायोजन के दाये सहित लागत और उसके बिक्री संबंधी सौदा का स्थापन प्रस्तुत आंकड़ों से किया गया। खाती का रखरखाव कोरिया वॉन में कैलेण्डर वर्ष के अनुसार किया जाता है जो कोरियाई लेखांकन पद्धति के अनुरूप है। एनबीआर हेतु केकेपीसी द्वारा प्रक्रिया लागत लेखांकन पद्धति अपनाई जाती है।

परिवर्तन लागत वास्तविक लागत पर आधारित होती है और वास्तविक विनिर्माण लागत की गणना हेतु इसे कच्चे माल की लागत में जोड़ दिया जाता है। विनिर्माण लागत में भुटि, बिक्री पर किए गए विचार, टर्नओवर अंतर, परिसंपत्ति तथा प्रशासनिक व्यय आदि व्यय के जोड़ और नुकसान/संयोजन लागत को पुनः लागत का समायोजन किया गया है। इन समायोजनों के अभाव में लागत असंगत होती थी।

लागत के बारे में प्रकटन विवरण पश्चात टिप्पणियाँ

34.1 केकेपीसी ने कंपनी 35 एकड़ के संबंध में विनिर्माण संबंधी कार्यवाही शुरू की थी। किंतु उन्होंने यह धारा प्रभावित की प्राधिकारी ने कंपनी के कुल व्यय का आकलन कारोबार के आसपास के संबंधित कारोबार के लिए किया है। लाभ संबंधी आंकड़ों के अस्वीकारण के कारणों के अभाव में केकेपीसी अपनाई गई कार्यप्रणाली के बारे में कारोबार टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं किंतु उसने परिवर्तनों को अयांछनीय माना है; कि घरेलू एनबीआर की बिक्री के लिए एसजीए की इकाई लागत और वित्तीय व्यय का अंतर बेची गई कुल मात्रा द्वारा विभाजित कर निकालना गलत है और प्राधिकारी को एनबीआर के लिए कुल कारोबार के आधार पर घरेलू बिक्री हेतु निर्धारित रेशि के आकलन की निस्तरीय उम्तिवा का प्राप्ति करना प्राप्ति इसका अभाव घरेलू बाजार में प्रवेश के कारोबार के आधार पर एनबीआर के विभिन्न गेडों के लिए पुनः किया जाना चाहिए और उत्पन्न बेची गई मात्रा के अनुसार गेड-वार आकलन का विभाजन कर इकाई लागत निकाली जानी चाहिए। तथापि, प्राधिकारी को कारखाना स्तर तक प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार केकेपीसी द्वारा किए गए विनिर्माण व्यय और एसजीए व्यय की गणना की और इसे व्यय को संबद्ध यस्तु पर समान रूप से प्रयोज्य बनाया जाने की घोषणा घरेलू बाजार निर्माण बिक्री के लिए नियत हो। चूंकि प्रचलित कारखाना स्तर पर व्यय पर की गणना किया गया है, इसलिए प्राधिकारी अपनाई गई कार्य प्रणाली को सही मानते हैं।

34.2 घरेलू उद्योग ने अपने अनुरोध में यह दोहराया है कि आबद्ध बुलॉडिन पर बाजार कीमत पर विचार किया जाना चाहिए। कोरिया से एकीकृत बाजार की आयात-निर्यात कीमतों की तुलना केकेपीसी द्वारा सूचित कीमत के साथ करनी चाहिए, विगत में निर्यात द्वारा दया की गई अन्य कच्ची सामग्री की लागत सकल रूप में कम बताई गई है। उन्होंने यह बताया

है कि प्रकटन विवरण में केकेपीसी की सूचना की यथार्थता पर न तो टिप्पणी की गई है और न ही केकेपीसी के दावों पर खपत संबंधी कारक लागू होते हैं। तथापि, प्राधिकारी ने उनके अनुरोधों पर विचार किया है। तथापि किसी प्रथम दृष्टतया और उसके विपरीत किसी मामला विशिष्ट साक्ष्य के अभाव में केकेपीसी का दावा अस्वीकार नहीं किया गया है। जहां तक खपत कारक का संबंध है, इसे निर्यातक के दावे के अनुसार एनबीआर के निर्दिष्ट ग्रेड हेतु कच्ची सामग्री के लिए समायोजित किया गया है और उसे यथोचित नहीं पाया गया है।

34.3 परिवर्तन लागत "वास्तविक" पर आधारित होने का हवाला देते हुए घरेलू उद्योग ने यह माना है कि चूंकि केकेपीसी द्वारा एक ही स्थान पर अनेक उत्पादों का उत्पादन किया जाता है इसलिए परिवर्तन लागत की हिस्सेदारी होती है और यह कि केकेपीसी "वास्तविक" लागत को यथोचित रूप से उपलब्ध नहीं करा सका है तथापि, प्राधिकारी ने निर्यातकों के इस उत्तर की जांच की है कि उसने वास्तविक उत्पादन प्रक्रिया के अनुरूप या अप्रत्यक्ष लागत केन्द्रों के अनुसार विभिन्न लागत केन्द्रों और विभागों में लागत को संचित किया है जिससे बहुविध उत्पादन प्रक्रियाओं को समर्थन मिलता है। अप्रत्यक्ष लागत केन्द्रों में व्यय की गई लागत का आबंटन प्रक्रिया लागत केन्द्रों में किया गया है और संचित लागतों का आबंटन विशेष प्रक्रिया के उत्पादों में किया गया है। केकेपीसी ने प्रति माह कच्ची सामग्री की वास्तविक लागत की गणना की है जिससे एनबीआर के उत्पादन में प्रयोग किया गया है। इसके अलावा, परिवर्तन लागत को लागत प्रणाली में वास्तविक आधार पर अलग से दर्ज किया गया है। नई सामग्री और पृथक् संघटक की परिवर्तन लागत को जोड़ने के बाद केकेपीसी ने विभिन्न उत्पादों की विनिर्माण की वास्तविक लागत की गणना की है।

34.4 घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों का उत्तर देते हुए प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ब्याज आय को उत्पादन लागत को निकालने और संबद्ध वस्तु की बिक्री का आकलन करने हेतु ब्याज लागत या अन्यथा में से कम नहीं किया गया है, यह कि कारखाना स्तर तक समस्त एसजीए व्यय पर विचार किया गया है और उसका आबंटन बिक्री लागत के विचारार्थ कारोबार के आधार पर किया गया है, यह कि पैकिंग लागत पर उत्पादन एवं बिक्री लागत निकालने के लिए विचार नहीं किया गया है क्योंकि इन्हें घरेलू बिक्री एवं निर्यात बिक्री की कारखाना निवल बिक्री कीमत निकालने हेतु समायोजन के रूप में दर्शाना अपेक्षित है और बिक्री लागत पर 5% लाभ (ब्याज को छोड़कर) उचित लाभ माना गया है।

35. जांच अवधि के दौरान केकेपीसी द्वारा एनबीआर की ***बी. टन की उल्लेखनीय घरेलू बिक्री की गई, जिसमें समग्र तथा ग्रेडवार दोनों रूपों में पर्याप्तता के परीक्षण की पूर्ति की गई। व्यापार की सामान्य स्थिति का परीक्षण यह दर्शाता है कि कुल लाभदायक सौदे 80-20 के परीक्षण पर खरे नहीं उतरते। अतः प्राधिकारी द्वारा सामान्य मूल्य की संरचना उत्पादन लागत जमा लाभ की समुचित मार्जिन के आधार पर की गई। निर्यातक ने अंतर्देशीय परिवहन, पैकिंग तथा क्रेडिट व्यय हेतु समायोजनों का दावा किया है, परंतु इन समायोजनों पर ध्यान

नहीं दिया गया क्योंकि सामान्य मूल्य का निर्धारण कारखाना-द्वारा दर पर किया गया है। केकेपीसी हेतु संरचित सामान्य मूल्य ***डॉलर प्रति मी.टन बनता है।

35.1 प्रकटन विवरण के प्रकाश अपनी टिप्पणियों में घरेलू उद्योग ने यह उल्लेख किया है कि कोरियाई उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण उचित नहीं होता है और इसकी समीक्षा की जरूरत है क्योंकि सेस्टेट द्वारा पर्यटन परिवर्तन के मार्गजुल पूर्वर्ती जांच में पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक रहा था और यद्यपि, पूर्ववर्ती जांच की सुझावों में वर्तमान जांच अवधि में कच्ची सामग्री कीमत में वृद्धि हुई थी, तथापि, निर्यात कीमत में आपुनपातिक वृद्धि नहीं हुई थी। अतः पाटन मार्जिन में वृद्धि होनी चाहिए।

36. तदनुसार प्राधिकारी ने गणनाओं का पुनरावलोकन किया और भारत को निर्यातित ग्रेडों की केवल लाभकारी घरेलू सौदों को हिसाब में लेते हुए सामान्य मूल्य की पुनः संगणना की।

	घरेलू बिक्री (मी.टन)
कुल	***
भारत को निर्यातित ग्रेड	***
निर्यातित ग्रेडों के लाभकारी सौदे	***
(i) कुल का %	***%
(ii) निर्यातित ग्रेड का %	***%

इन सौदों की औसत बिक्री कीमत *** अम.डॉ./मी. ट. बनती है। अंतरराष्ट्रीय भाड़े, ऋण लागत और पैकिंग प्रभारों के लिए दाया की गई घरेलू बिक्री पर समायोजनों की दायानुसार अनुमति दी गई है। समायोजनों को छोड़कर भारत औसत कारखाना सामान्य मूल्य निम्नानुसार *** अम.डॉ./मी.ट. बनता है।

लाभकारी सौदे	घरेलू बिक्री	इकाई बिक्री कीमत	समायोजन	कारखाना सामान्य मूल्य
	मी.ट.	डॉ. प्रति मी.ट.	डॉ. प्रति मी.ट.	डॉ. प्रति मी.ट.
	***	***	***	***

निर्यात कीमत

37. जांच अवधि के दौरान केकेपीसी द्वारा भारत को 7 एनबीआर ग्रेड का ***मी.टन का निर्यात किया गया था, जिसमें से प्रमुख-बिक्री केएनबी 35एल की थी। निर्यातक ने घरेलू बाजार में भी इन ग्रेडों की उल्लेखनीय मात्रा में बिक्री की थी। अतः पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ करार के अनुसार इन ग्रेडों को "समान वस्तु" शब्द के अर्थ के भीतर समान वस्तु के रूप में स्वीकार किया गया है।

सभी प्रकार की बिक्री निम्नलिखित मात्रा में की गई:-

एनबीआर बिक्री (%)	2005	2006	पीजीआई
क) घरेलू	28	22	20
ख) भारत का निर्यात	15	14	14
ग) अन्य देश	59	64	66
कुल	100	100	100

38. भारत को किए गए निर्यात सीधे ग्राहक को अथवा कमीशन एजेंट को किए गए अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक ट्रेडिंग कंपनी-मेसर्स देवू इंटरनेशनल के मार्फत किए गए और प्रत्येक ग्राहक के लिए कीमत पर विचार-विमर्श किया गया। ट्रक के माध्यम से अंतर्देशीय परिवहन प्रकार की गणना ग्राहक को बेची गई सभी ग्रेडों की मात्रा के कुल प्रकार के आधार पर की गई। इस उत्पाद की पैकिंग 35 किग्रा. पीबी की बोरियों में अथवा 1.05 मी.टन के बक्सों में की जाती है और इसकी लागत की गणना पैकिंग सामग्री की ईकाई लागत और उसकी परिवर्तन कारक के आधार पर की जाती है। भारत को प्रदत्त क्रेडिट की शर्तों में स्थानीय एलसी, मौके पर एलसी, 30 दिन की एलसी, 60 दिन की एलसी तथा 90 दिन की एलसी के रूप में जारी लेटर ऑफ क्रेडिट शामिल है। एलसी 90 अधिकतम होती है। इसके अलावा देवू इंटरनेशनल, जो एक असंबद्ध व्यापारिक कंपनी है, के माध्यम से अप्रत्यक्ष बिक्री भारत को किए गए कुल निर्यात की ***% थी और निवल निर्यात दरें अपेक्षाकृत कम थी, क्योंकि विदेशी बीमें जैसे कतिपय समायोजन तथा ऋण व्यय नहीं किए गए।

39. भारत को किए गए निर्यातों की वास्तविक सीआईएफ कीमत के आधार पर, समुद्री मालभाड़े तथा बीमा, अंतर्देशीय मालभाड़े, कमीशन, सीमाशुल्क शुल्क क्रेडिट लागत तथा पैकिंग, जिसका कंपनी द्वारा दावा किया गया है, के समायोजन के बाद कारखाना-द्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत की गणना की गई है। औसत निवल कारखाना-द्वार निर्यात कीमत ***डॉलर प्रति मी.टन निर्धारित की गई है।

बिक्री	निर्यात कीमत	समायोजन	कारखाना-द्वार निर्यात कीमत
(मी.टन में)	\$ प्रति मी.टन	\$ प्रति मी.टन	\$ प्रति मी.टन
***	***	***	***

ख.2.2 एलजी केप (एलजीसी), कोरिया गणराज्य

सामान्य मूल्य

40. एलजीसी एक कार्पोरेशन है, जो ***ग्रुप का सदस्य है, जिसकी स्थापना***से अलग होने के बाद कोरिया के याणिज्यिक कानून के अंतर्गत अप्रैल 2001 में की गई थी। जनवरी 2006 में इसका विलय एलजी डाएसन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड में कर दिया गया, जो जनवरी 2005 में हुंडई पेट्रोकेमिकल कं.लि. से अलग हुई थी। एलजीसी स्टॉक एक्सचेंज में 2001 से सूचीबद्ध है। यह पेट्रो रसायनों एवं अन्य औद्योगिक सामग्री के व्यवसाय में संलग्न है। एलजीसी का मुख्य कार्पोरेट कार्यालय सिओल में है और एनबीआर का उत्पादन डाएसन संयंत्र में किया जाता है।

41. एलजीसी का लागत सत्यापन, उनके विभिन्न समायोजनों के दावे सहित घरेलू बिक्री सौदों का सत्यापन प्रस्तुत आंकड़ों से किया गया। प्राधिकारी ने नोट किया कि कच्चे माल की लागत की गणना में त्रुटि थी क्योंकि विभिन्न ग्रेडों की वास्तविक खपत, खपत मानदण्डों से भी कम थी। अतः प्राधिकारी द्वारा खपत मानदण्डों के अनुसार कच्चे माल की लागत का समायोजन किया गया और कंपनी द्वारा इंगित परिवर्तन लागत को स्वीकार करके टर्नओवर आधार पर सामान्य, प्रशासनिक तथा ब्याज व्यय का पुनः आवंटन किया गया। तदनुसार एलजीसी की औसत उत्पादन लागत***डॉलर प्रति मी.टन बनती है।

लागत के बारे में प्रकटन विवरण पश्चात् टिप्पणियाँ

41.1 एलजीसी ने दो प्रमुख कच्ची सामग्रियों के संबंध में कुछेक पारंपरिक खपत मानदण्डों को अपनाते हुए उनकी सूचना के अस्वीकारण/उपांतरण पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है और उन्होंने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का खुला उल्लंघन करते हुए और डीजीएडी की पूर्ववर्ती नज़ीर के विपरीत एनबीआर की अपनी उत्पादन लागत पुनः संगठित की है। उन्होंने बताया है कि यह स्पष्ट नहीं था कि क्या डीजीएडी का प्रस्ताव एलजीसी के लिए मानक लागत या व्यय की गई वास्तविक लागत निकालने का प्रस्ताव है और यह कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 (1) के अनुसार डीजीएडी सहयोगी उत्पादक/निर्यातक द्वारा रखे गए रिकार्ड के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए किए जाने की सीमा में ही पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों का उपयोग कर सकता है। इसके अलावा, डीजीएडी ने पाटनरोधी करार के उपबंधों का उल्लंघन किया है जिसमें सामान्य मूल्य निकालने के लिए वास्तविक लागत की गणना करने न कि पारंपरिक अनुमान के आधार पर मानक कीमत की गणना करने का प्रावधान है और यह कि डीजीएडी ने कच्ची सामग्री की संशोधित लागत की गणना में अपनाए गए खपत मानकों हेतु आधार या तर्क नहीं दिया है।

41.2 तथापि, पूर्व में दी गई सूचना के अनुसार प्राधिकारी ने यह दोहराया है कि अपनाए गए खपत मानक पारंपरिक नहीं हैं अपितु उपलब्ध तथ्यों के आधार पर

सार्वभौमिक रूप से अत्यंत समायोजित हैं। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1(1) तथा डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.1.11, दोनों में 66 उत्पादक या निर्यातक द्वारा रखे गए रिकार्ड ... यदि ऐसे रिकार्ड से विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री से संबंध लागत का यथोचित पता चलता हो, के आधार पर" सामान्य मूल्य के संदर्भ में लागत निर्धारण का प्रावधान है। यदि नहीं, तो प्राधिकारी यथोचित उत्पादन या बिक्री लागत निकालने के लिए कम बताए गए खपत मानक या कीमत से उत्पन्न निविष्टि लागत में किसी विकृति में सुधार करने में न्यायोचित था। एल जी सी के मामले में प्राधिकारी ने प्रमुख कच्ची सामग्री (ए सी एन तथा बी डी) की खपत को प्रथम दृष्टया कम बताया गया पाया है क्योंकि

- (i) एसीएन की वास्तविक खपत एक को छोड़कर एनबीआर के सभी ग्रेडों के लिए निर्धारित अंतर्वस्तु से कम थी जैसा कि एलजीसी के ग्रेडवार अंतर्वस्तु से संबंधित विवरण से देखा जा सकता है;
 - (ii) जब एलजीसी और केकेपीसी दोनों द्वारा समान ग्रेडों का उत्पादन किया जाता है तो केकेपीसी की तुलना में एलजीसी के सूचित खपत स्तर एसीजीएन के मामले में लगभग *** तक और बी डी के मामले में *** तक कम है;
 - (iii) यद्यपि बी डी अंतर्वस्तु के लिए कोई निर्धारित स्तर नहीं है तथापि, केकेपीसी तथा घरेलू उद्योग के खपत स्तरों तथा एसआईओएन मानकों से यह देखा जाता है कि एक किग्रा. एनबीआर के लिए ए सी एन निर्धारित मानकों के अनुरूप होगा शेष बी डी होगा ताकि दोनों निविष्टियों के लिए कुल खपत उत्पादन से 2-3% अधिक रहेगी। अतः प्राधिकारी ने यह माना है कि कम बताई गई खपत से उत्पादित एनबीआर की कच्ची सामग्री की लागत विकृत हुई है और (क) जहां कोई ग्रेडवार ए सीएन स्तर का अनुमान लगाते हुए जबकि बी डी की खपत में ए सी एन की खपत के अनुरूप आनुपातिक वृद्धि की गई है जिसके परिणामस्वरूप एसीएन और बी डी की खपत में लगभग ***% की वृद्धि हुई है जबकि बी डी को ***% तक कम बताया गया है (ख) जहां तुलनीय ग्रेड उपलब्ध थे, वहां केकेपीसी द्वारा उत्पादित समान ग्रेडों के आधार पर कच्ची सामग्री की वास्तविक खपत अपनाते हुए सार्वभौमिक समायोजन किए हैं।
- 41.3 एलजीसी ने यह भी दावा किया है कि उनकी प्रणाली प्रत्येक उत्पाद समूह स्तर के लिए आंकड़े संसाधित कर सकती है। संबंधित उत्पाद के लिए प्रत्यक्षतः अभिज्ञात किए जा सकने वाले समस्त व्यय उत्पाद संबंधी व्यय के रूप में दर्ज किए गए हैं। जबकि अन्य सामान्य ऊपरी व्यय कारोबार आधार पर उत्पाद के आनुपातिक है। प्राधिकारी ने प्रस्तुत आंकड़ों की जांच की और यह पाया कि सामान्य और प्रशासनिक ऊपरी व्यय के लिए आबंटन का आधार वास्तविक तथा कारोबार था। यह नोट किया गया कि एलजीसी एक बहुउत्पाद कंपनी है और संबंध उत्पाद का बिक्री कारोबार कंपनी के कुल कारोबार का मात्र ***% है। आम तौर पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति

रहित कीमत के निर्धारण में भी सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय का आबंटन साधारणतः कारोबार आधार पर किया जाता है। बनाने और बेचने की लागत निकालने के लिए प्राधिकारी ने यही नियम अपनाया है।

41.4 एल जी सी ने यह माना है कि व्याज संबंधी व्यय एसजीए में शामिल किए गए हैं और प्रकार-वार लागत निर्धारण में वित्तीय व्यय के संबंध में यह सूचना पहले ही दी जा चुकी है कि एसजीए व्यय की गणना करने में त्रुटि हुई है और डीजीएडी की गणना में वित्तीय व्यय को दोबारा गिन लिया गया है। तथापि प्राधिकारी ने व्याज संबंधी व्यय तथा एसजीए लागत पर अलग से विचार किया है और व्याज संबंधी व्यय को एसजीए लागत में शामिल नहीं किया है। एसजीए व्यय की पुनः संगणना में कोई त्रुटि नहीं हुई है और वित्तीय व्यय की दोबारा गणना नहीं की गई है बल्कि उसे एसजीए व्यय से अलग दर्शाया गया है।

42. प्रकटन विवरण के पश्चात् एलजीसी ने आश्चर्य व्यक्त किया है कि

- मौके पर सत्यापन की योजना के बावजूद प्राधिकारी ने दौरा किए बिना टेबल अध्ययन आधार पर जांच करने का निर्णय लिया।
- पूर्ण सहयोग के बावजूद एलजीसी के यह दर्शाने का अवसर प्रदान नहीं किया गया कि उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना तथ्यों पर आधारित है न कि गलत अनुमानों पर।
- दिगत में डीजीएडी ने पूर्ण सहयोगी निर्यातक की सूचना का सत्यापन किया था परंतु एलजीसी के मामले में खपत मानकों में संशोधन के बारे में पहले कोई सूचना नहीं दी गई थी।

तथापि, प्राधिकारी के पास यह विशेषाधिकार होता है कि वह निर्यातक द्वारा प्रदत्त आंकड़ों/सूचना का मौके पर सत्यापन करे या टेबल सत्यापन करे और सहयोगी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना की सत्यता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करे। इसके अलावा, प्राधिकारी ने पुनः संगठित लागत पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए एल जी सी को अवसर प्रदान किया था और इस बात से इंकार कि जाता है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का कोई उल्लंघन हुआ है।

43. जांच अवधि के दौरान एलजीसी ने एनबीआर की विभिन्न ग्रेडों की ***मी.टन की उल्लेखनीय घरेलू बिक्री की थी। इस प्रकार निर्धारित उत्पादन लागत के आधार पर घरेलू बिक्री सौदों पर किए गए व्यापार की सामान्य स्थिति के परीक्षण से ज्ञात होता है कि ***% घरेलू बिक्री, उत्पादन लागत से कम थी। अतः प्राधिकारी द्वारा उत्पादन लागत और लाभ की समुचित मार्जिन के आधार पर सामान्य मूल्य संरचित किया गया।

	घरेलू बिक्री
	एम.टी.
कुल	***
भारत को निर्यातित ग्रेड	****
निर्यातित ग्रेडों के लाभप्रद सौदे	***
(i) कुल का %	***
(ii) निर्यातित ग्रेडों का %	***

*: अपमानक वस्तुओं को छोड़कर

43.1 प्रकटन विवरण के बाद घरेलू उद्योग ने यह पूछा है कि क्या सामान्य मूल्य या निर्यात कीमत या दोनों का निर्धारण करने के लिए ऑफ ग्रेड एनबीआर को अलग रखा गया है और क्या इस प्रकार उसे बाहर रखने की मांग निर्यातकों ने की थी और उसके कारण क्या हैं।

44. प्राधिकारी ने भारत को निर्यातित ग्रेडों के केवल लाभकारी घरेलू सौदों को ध्यान में रखते हुए पाटन मार्जिन की पुनः गणना की है। इन सौदों की औसत बिक्री कीमत *** अम.डॉ./मी.टन बनती है। अंतर्देशीय भाड़े, ऋण लागत तथा पैकिंग प्रभारों के लिए घरेलू बिक्री पर दावा किए गए समायोजनों की अनुमति दी गई है। समायोजनों के बाद मारित औसत कारखाना सामान्य मूल्य निम्नानुसार *** अम.डॉ. प्रति मी.टन बनता है :

लाभकारी सौदे	घरेलू बिक्री	इकाई बिक्री कीमत	समायोजन	कारखाना सामान्य मूल्य
	मी.ट.	डालर प्रति मी.ट.	डालर प्रति मी.ट.	डालर प्रति मी.ट.
	***	***	***	***

निर्यात कीमत

45. जांच अवधि के दौरान एलजीसी द्वारा भारत को एनबीआर की 4 ग्रेडों की *** मी.टन मात्रा का निर्यात किया गया था, जिसमें से अधिकतम बिक्री एनबीबी 6240 एल की की गई थी। निर्यातक ने इन ग्रेडों की बिक्री अपने घरेलू बाजार में भी की थी। अतः करार के अनुसार पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ "समान वस्तु" शब्द के अर्थ के भीतर इन ग्रेडों को समान वस्तु के रूप में स्वीकार किया गया है।

सभी बाजारों में मात्रावार बिक्री निम्नानुसार थी :-

एनबीआर बिक्री (%)	2005	2006	जांच अवधि
कोयरेलू	24	23	21
ख)भारत को निर्यात	1	1	1
ग)अन्य देश	75	76	78
कुल	100	100	100

46. भारत को किए गए निर्यातों की वास्तविक सीआईएफ कीमत के आधार पर समुद्री मालभाड़े तथा बीमा, अंतर्देशीय मालभाड़े, कमीशन, क्रेडिट लागत और पैकिंग, जिसका कंपनी द्वारा दावा किया गया है, के समायोजन के बाद कारखाना-द्वार स्तर पर निर्यात कीमत***अम.डॉलर प्रति मी.टन निर्धारित की गई है।

बिक्री	निर्यात कीमत	समायोजन	कारखाना-द्वार निर्यात कीमत
(मी.टन में)	डॉलर प्रति मी.टन	डॉलर प्रति मी.टन	डॉलर प्रति मी.टन
***	***	***	***

घ.2.3 कोरिया गणराज्य हेतु सामान्य मूल्य

47. प्राधिकारी ने नोट किया कि यद्यपि केकेपीसी तथा एलसी द्वारा एनबीआर की विभिन्न ग्रेडों का निर्यात किया जा रहा है, तथापि यह निर्णायक समीक्षा होने के कारण उत्पाद का दायरा मूल जांच की परिभाषा तथा सीमित है, जिसमें सभी ग्रेडों को एक उत्पाद माना गया था। अतः दोनों कंपनियों के लिए एक औसत सामान्य मूल्य की गणना की गई और सिविल अपील सं.1294/2001 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में देश विशिष्ट सामान्य मूल्य ज्ञात किया गया। निर्यातकों के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए सामान्य मूल्य की तुलना अलग-अलग निर्यातकों की निर्यात कीमत से की गई।

निर्धारित सामान्य मूल्य *** डॉलर प्रति मी.टन है।

\$ प्रति मी.टन में	केकेपीसी	एलजीसी	भारत औसत
सामान्य मूल्य	***	***	***

च.2.4 कोरिया गणराज्य के अन्य सभी निर्यातक

सामान्य मूल्य

48. चूंकि इस समीक्षा जांच में कोरिया गणराज्य के किसी अन्य निर्यातक ने प्राधिकारी के समक्ष कोई निवेदन प्रस्तुत नहीं किया अतः सिविल अपील सं. 1294/2001 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में प्राधिकारी ने कोरिया के अन्य सभी निर्यातकों के लिए ***अम.डॉलर प्रति मी.टन का भारित औसत सामान्य मूल्य प्रयुक्त किया है।

निर्यात कीमत

49. निवल निर्यात कीमत का निर्धारण कोरिया व सहयोगी निर्यातक के न्यूनतम निर्यात सौदा मूल्य के आधार पर किया गया है, जिसमें परिवहन, समुद्री मालभाड़े, कमीशन आदि का उचित समायोजन भी किया गया है। निवल निर्यात कीमत *** अम.डॉ. प्रति मी.टन बनती है।

च.3 जर्मनी

च.3.1 जर्मनी हेतु सामान्य मूल्य

50. चूंकि जर्मनी के किसी निर्यातक ने समीक्षा जांच शुरुआत का कोई उत्तर नहीं दिया, अतः प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6.8 के अनुसरण में जर्मनी में संबद्ध वस्तुओं के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया है। संरचित सामान्य मूल्य भारत में घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, परिवर्तन लागत तथा बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय पर आधारित है; प्रमुख कच्चे माल की कीमतें उनकी जर्मनी से शेष विश्व को की गई निर्यात कीमतों पर और घरेलू उद्योग के लिए कच्चे माल और प्रक्रिया में प्रयुक्त रसायनों की वास्तविक खरीद कीमत पर आधारित है, जिसमें लाभ की समुचित मार्जिन भी शामिल है। तदनुसार जर्मनी के सभी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य ***अम. डॉलर प्रति मी.टन निर्धारित किया गया है।

च.3.2 जर्मनी हेतु निर्यात कीमत

51. जर्मनी से निर्यात कीमत का निर्धारण डीजीसीआईएंडएस द्वारा तथ्यों की उपलब्धता के आधार पर जांच अवधि के दौरान समुद्री मालभाड़े, बीमें, अंतर्देशीय मालभाड़े तथा कमीशन हेतु अनुमत समायोजनों के बाद भारित औसत-निर्यात-कीमत के आधार पर किया गया है। तदनुसार जर्मनी के सभी निर्यातकों के लिए निवल कारखाना-द्वारा निर्यात कीमत ***अम.डॉलर प्रति मी.टन निर्धारित की गई है।

च.4 पाटन मार्जिन

52. प्राधिकारी ने भारित औसत-सामान्य मूल्य और कारखाना-द्वारा निर्यात कीमत की तुलना

करके पाटन मार्जिन की गणना की है। संबंध देशों के लिए पाटन-मार्जिन निम्नानुसार है :

घ 4.1 कोरिया हेतु पाटन मार्जिन

53. सहयोगी निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण भारत-औसत सामान्य मूल्य और कारखाना-द्वार निर्यात कीमत के बीच अंतर के रूप में किया गया है। अन्य के संदर्भ में पाटन मार्जिन का निर्धारण भारत औसत सामान्य मूल्य और समायोजन के बाद सहयोगी निर्यातक की न्यूनतम निर्यात कीमत के अंतर के रूप में किया गया है।

घ.4.2 जर्मनी हेतु पाटन मार्जिन

54. प्राधिकारी ने संरचित सामान्य मूल्य और डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों के अनुसार उक्त उत्पाद के लिए निर्धारित भारत औसत निर्यात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य और कारखाना-द्वार स्तर पर निर्यात कीमत की तुलना करके पाटन मार्जिन की गणना की है।

घ.5 पाटन-मार्जिन: सारांश

कोरिया गणराज्य	सामान्य मूल्य अम.डॉलर/मीटन	निर्यात कीमत अम.डॉलर/मीटन	पाटन मार्जिन अम.डॉलर/मीटन	पाटन मार्जिन का %
केकेपीसी		***	***	1.69
एलजीसी	***	***	***	0.05
अन्य सभी		***	***	13.42
जर्मनी	***	***	***	-11.01

55. कोरिया गणराज्य के अन्य निर्यातकों को छोड़कर जांच अवधि के दौरान पाटन मार्जिन नगण्य अथवा नकारात्मक हैं। तथापि प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्णायक समीक्षा में वर्तमान पाटन मार्जिन वास्तविक तथ्य नहीं है और जांच अवधि के दौरान कोई पाटन न होने पर भी इसकी पुनरावृत्ति की संभावना की जांच की जानी अपेक्षित है।

प्रकटन विवरण के बाद टिप्पणियां

56. के.के.पी.सी. ने बताया है कि

- उनकी अलग-अलग निर्यात कीमत के साथ भारत औसत सामान्य मूल्य की तुलना संगत विधिक प्रावधान के असंगत है;
- उन्होंने रिलायंस संबंधी निर्णय का प्राधिकारी द्वारा भ्रांतिपूर्ण अर्थनिरूपण और उससे

उत्पन्न विकृति को सुधारने के लिए नियमों में उपलब्ध निवारण का उल्लेख किया है:

- प्राधिकारी को निर्यातक/उत्पादक द्वारा व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में उत्पादन एवं बिक्री से संबंधित वास्तविक आंकड़ों के आधार पर या घरेलू बाजार में उत्पादन एवं बिक्री में निर्यातक द्वारा व्यय की गई और प्राप्त की गई वास्तविक राशि के अनुसार उपलब्ध सभी साक्ष्यों पर विचार करते हुए न्यायालयीय निर्णय के साथ सांघिक उपबंधों (भारतीय पाटनरोधी कानून के) की सुसंगत व्याख्या करनी होती है। जांचाधीन अन्य उत्पादों या निर्यातकों द्वारा व्यय की गई और वसूली गई वास्तविक राशि के भारित औसत पर असहयोग की स्थिति में ही विचार किया जा सकता है;
- पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1.6(i) में कीमत तुलनीयता पर प्रभाव डालने वाले अंतरों के लिए उचित छूट के साथ सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की उचित तुलना का प्रावधान है जिसे तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि अलग-अलग निर्यातकों के लिए अलग-अलग सामान्य मूल्य की गणना न की जाए;
- न्यायालयीय निर्णय के तहत प्राधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह समूचे देश के एक ही सामान्य मूल्य का निर्धारण करे और ऐसा करने में प्राधिकारी ने त्रुटि की है;
- पाटन मार्जिन निकालने के लिए उचित तुलना के नियम का पालन किया गया है। डब्ल्यू टी ओ के एक पैनल ने यह निर्णय दिया है कि उचित तुलना का सिद्धांत तभी लागू होता है जब सामान्य मूल्य के साथ निर्यात कीमत की तुलना की जाए। समायोजन उसी समय भी किए जा सकते हैं भले ही सामान्य मूल्य के निर्धारण की कार्यप्रणाली कुछ भी हो;
- धारा 9(क)(1) में "किसी देश से उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यातित कोई वस्तु" में "कोई" शब्द के उपयोग का तात्पर्य यह है कि सामान्य मूल्य उस वस्तु का होना चाहिए जिसके लिए पाटन मार्जिन निर्धारित किया जा रहा है न कि भारित औसत सामान्य मूल्य। भारित औसत सामान्य मूल्य की गणना तभी की जा सकती है जब उत्पादकों की उत्पादन लागत एक समान हो; अन्यथा निर्यात कीमत में उचित समायोजन करते हुए उत्पादन लागत में अंतरों को ध्यान में रखा जा सकता है। इस प्रकार प्राधिकारी द्वारा निकाली गई कारखाना निर्यात कीमत का समायोजन केकेपीसी के लिए सामान्य मूल्य और कोरिया गण. के लिए निर्धारित भारित औसत सामान्य मूल्य के बीच के अंतर के बराबर की राशि तक करना होगा;
- प्राधिकारी को निर्यात के सामान्य मूल्य, जो उसकी लागत, एसजीए तथा लाभ का कार्य है, के आधार पर "वास्तविक" पाटन मार्जिन का निर्धारण करना होता है। कुछेक अन्य प्रतिस्पर्धी कंपनियों की लागत का उपयोग करना "वास्तविक" लागत के

अर्थ में नहीं आता है और प्राधिकारी ने एकल भारित औसत सामान्य मूल्य निकालने में त्रुटि की है।

➤ संगठित भारित औसत सामान्य मूल्य से केकेपीसी का नकारात्मक पाटन मार्जिन एलजीसी की तुलना में सकारात्मक पाटन मार्जिन में तब्दील हो गया है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 18(2) में इस आशय का एक परंतुक निहित है कि भारित औसत पाटन मार्जिन निकालते समय प्राधिकारी नकारात्मक या न्यूनतम पाटन मार्जिन की अनदेखी करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गैर-नमूना वाली कंपनियों को न्यूनतम दरों का लाभ प्राप्त न हो और यह सिद्धांत के केपीसी तथा एलजीसी के लिए भारित औसत निकालने में एक मार्गदर्शक होना चाहिए जब केकेपीसी का ऋणात्मक पाटन मार्जिन है।

57. एलजीसी ने बताया है कि उन्हें प्रकटन विवरण पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है क्योंकि कच्ची सामग्री और एसजीए से संबंधित लागत समायोजन लागू करने पर भी उनका पाटन मार्जिन नकारात्मक था। परंतु वे चाहेंगे कि प्राधिकारी उनकी लागत संबंधी सूचना स्वीकार करें।

58. प्राधिकारी ने भारत को निर्यातित ग्रेडों में दोनों उत्पादक निर्यातकों के केवल लाभकारी सीदों को लेते हुए पाटन मार्जिन की गणना की है। दोनों निर्यातकों का सकारात्मक यद्यपि न्यूनतम पाटन मार्जिन है।

उ. क्षति निर्धारण

59. नियमावली के अनुबंध II में अपेक्षा की गई है कि क्षति के निर्धारण में निम्नलिखित दो बातों की वस्तुनिष्ठ जांच की जाएगी : (क) पाटित आयातों की मात्रा और घरेलू बाजार में समान वस्तु की कीमत पर पाटित आयातों का प्रभाव और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव। अनुबंध-II (ii) तथा (iv) में निम्नलिखित प्रावधान हैं :-

(ii) "पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय प्राधिकारी विचार करेंगे कि क्या-पाटित आयातों में, निरपेक्ष रूप में अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत के सापेक्ष उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का प्रश्न है, निर्दिष्ट प्राधिकारी विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के कारण उल्लेखनीय कीमत कटौती हुई है अथवा ऐसे पाटित आयातों के प्रभाव का उद्देश्य कीमतों में उल्लेखनीय स्तर तक मंदी लाना अथवा कीमत वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा उल्लेखनीय सीमा तक हुई होती।"

(iv) संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी सुसंगत

आर्थिक कारकों एवं सूचकों की जांच शामिल होगी, जो उस उद्योग की स्थिति को प्रभावित करते हैं, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश से आय अथवा क्षमता उपभोग में प्राकृतिक अथवा संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन की मार्जिन की सीमा; नकद प्रवाह, मालसूची रोजगार, मजदूरी, वृद्धि पूंजी जुटाने की क्षमता, निवेश पर वास्तविक एवं संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल है।"

छ.1 हितबद्ध पक्षों के विचार

60. घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि संबद्ध वस्तुओं पर पहले ही पाटनरोधी शुल्क लगा है, अतः घरेलू उद्योग की क्षति से संबंधित विभिन्न आर्थिक मानदण्डों का क्षति दर्शाना जरूरी नहीं है। इसके बावजूद उनका दावा है कि पाटित आयातों की मात्रा और कीमत प्रभाव उल्लेखनीय है, कि मांग में वृद्धि के अनुरूप उत्पादन और क्षमता में वृद्धि से केवल मालसूची में वृद्धि हुई है क्षमता उपयोग में गिरावट आई है और परिणामतः जांच अवधि के दौरान उत्पादन में कटौती करनी पड़ी है; कि वर्तमान निर्यात पाटित कीमतों पर हो रहे हैं और यह कि कोई भी उपभोक्ता एनबीआर का आयात नहीं करेगा यदि यह घरेलू उत्पादक से कमतर कीमत पर उपलब्ध हो। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में उनकी परिवर्तन लागत में यद्यपि गिरावट आई है, परंतु स्रोतों से पाटन बढ़ाने और नए स्रोतों से पाटन शुरू होने के कारण क्षति हुई है।

61. निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है। केकेपीसी ने सार्वजनिक सुनवाई में इस मुद्दे को उठाए जाने के बावजूद याचिका तथा प्रपत्र IV क में दिए गए आयात आंकड़ों में त्रुटियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने पिछले आठ वर्षों में निर्यात की मात्रा कुल आयातों की 30% से कम बताई है, जबकि एलजीसी ने घोषित किया है कि वे न तो पाटन कर रहे हैं और न ही कीमत कटौती। केकेपीसी ने यह भी दावा किया है कि घरेलू उद्योग ने स्वयं स्वीकार किया है कि यद्यपि मांग में केवल 7% की वृद्धि हुई, तथापि क्षमता में वृद्धि 20% से अधिक हुई और क्षमता में अनुपात से अधिक वृद्धि के कारण स्थायी लागत अत्यधिक बढ़ी हुई है, क्षति रहित कीमत अत्यधिक है और तुलन पत्र में कथित नुकसान हुआ है। 1-10% की कीमत कटौती का कारण है व्यापार के स्तर में भिन्नता आना। 10 वर्ष तक संरक्षणवादी उपायों के बावजूद यह दावा करना कि घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है, गलत है और उनके आंकड़ों को सावधानी से जांच करना जरूरी है। इसके अलावा घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण क्षति विश्लेषण दोषपूर्ण है और अन्य स्रोतों अर्थात् ईयू (जर्मनी को छोड़कर), ब्राजील, मैक्सिको के आयातों पर शुल्क 2005 से और चीन ताइपेई के आयातों पर 2000 से लगाया गया है। जैसा कि घरेलू उद्योग ने स्वयं स्वीकार किया है, क्षति अन्य देशों से आयातों के कारण हुई न कि संबद्ध देशों से।

62. कैकेपीसी ने घरेलू उद्योग पर विभिन्न जांचों में लाभ से संबंधित विभिन्न प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत करने का आरोप लगाया है अर्थात् कोरिया गणराज्य से आयातों से संबंधित मध्याह्नि समीक्षा के अंतिम जांच परिणाम दिनांक 6.6.2005, ईयू मेक्सिको तथा ब्राजील दिनांक 5.10.2005 तथा चीन ताइपेई दिनांक 27.02.2006 और इस तथ्य के मद्देनजर आंकड़ों की जांच की जानी अपेक्षित है।
63. एआईआरआईए ने निवेदन किया है कि वर्ष 2006-07 के वित्तीय परिणाम के अनुसार अपार इण्डस्ट्रीज लाभान्वित होने वाली कंपनी है और इसने आटोमोबाइल उद्योग की वृद्धि से जुड़ी मांग में वृद्धि और लाभप्रदता की मार्जिन में सुधार के मद्देनजर एनबीआर का व्यवसाय सकारात्मक होने का आकलन किया है। इसके अलावा एक फ्रेंच कंपनी द्वारा अपार इण्डस्ट्रीज के पॉलीमर डिवाइजन के अधिग्रहण का निहितार्थ है कंपनी के लाभप्रद होने की संभावना। कंपनी ने पाटनरोधी शुल्क के संरक्षण का लाभ उठाया है और एकाधिकार की स्थिति का लाभ उठाते हुए एनबीआर की घरेलू कीमत में बार-बार वृद्धि की है। उसने चीन को भारत में आयात कीमत से भी कम दर पर एनबीआर का निर्यात किया और पाटनरोधी शुल्क जारी रखने के किसी भी तर्क को पूरी तरह निष्प्रभावी कर दिया। इसके अलावा 15000 मी.टन की लाइसेंस क्षमता की तुलना में वार्षिक उत्पादन केवल 8000 मी.टन के लगभग था अतः वह 20,000 मी.टन से अधिक की मांग को पूरा नहीं कर सकी। उद्योग को सरकार से संरक्षण प्राप्त किए बिना वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा।
64. एलजी ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को नुकसान इसके स्थान के कारण हुआ है और कच्चे माल के कारखाने तक परिवहन पर अत्यधिक व्यय करना पड़ा है और यह कि यह एक गैर किफायती क्षमता के अंतर्गत प्रचालित है और न दोनों कारकों की परिणति आयातित उत्पाद की तुलना में लागत में बढ़ोतरी में होगी। इसके अलावा, दस वर्ष तक पाटनरोधी शुल्क लगे रहने के बावजूद घरेलू उद्योग अपने कार्य निष्पादन में सुधार नहीं कर सका है।

ब.2 प्राधिकारी द्वारा जांच

65. प्राधिकारी ने विभिन्न पक्षों द्वारा अपने निवेदनों में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर विचार किया है और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने के मुद्दे की जांच प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत तर्कों के आलोक में की गई है। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह पहले से लगाए गए उपाय की निर्णायक समीक्षा है और उन्होंने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II (iii) की शर्तों के अनुसरण में संबंधित देशों से एक साथ किए गए पाटन के कारण क्षति के संघीय आकलन के मुद्दे की भी जांच की है और उनका यह अभिमत है कि इस मामले में संघीय आकलन हेतु उक्त नियमावली में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी कर ली गई हैं।
66. प्राधिकारी ने यह देखा है कि मूल शुल्क संदर्भ कीमत आधार पर लगाया गया था और

निर्णायक समीक्षा में निर्धारित शुल्क हेतु बदला गया था। घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई क्षति और पाटित आयातों तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की जांच की गई है। यह नोट किया गया था कि संबद्ध देशों के अलावा, अनेक अन्य देशों से भारतीय बाजारों में संबद्ध वस्तुएं साथ-साथ प्रवेश कर रही हैं। इन देशों में शामिल हैं, यूरोपीय संघ (जर्मनी को छोड़कर) ब्राजील, मेक्सिको और चीनी ताइपेई, जिन्हें पहले ही पाटित आयात माना जाता है। अतः ऐसे सभी स्रोतों से पाटित आयातों को घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के प्रयोजनार्थ संघयित किया गया है।

(क) पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

67. डीजीसीआईएंडएस से लिए गए सौदावार आंकड़े दर्शाते हैं कि संबद्ध उत्पाद के आयातों का सीमाशुल्क वर्गीकरण 40025900 के अंतर्गत उल्लेख है। चूंकि उत्पाद का विवरण केवल सांकेतिक है इसलिए उनके वर्गीकरण पर विचार न करते हुए संबद्ध वस्तुओं के सभी आयात मात्रा, मूल्य और औसत आयात कीमत के निर्धारण के प्रयोजनार्थ शामिल किए गए हैं। चूंकि कोरिया के निर्यातकों ने भारत को अपने निर्यातों संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराए हैं, जो डीजीसीआईएस के आंकड़ों की तुलना में मात्रा और मूल्य के अनुसार अधिक हैं, इसलिए इन आंकड़ों को जांच अवधि हेतु स्वीकार किया गया है। कोरिया से निर्यातों के ब्यौरे जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड एटलस में दर्शाए गए हैं, को भी नीचे इंगित किया गया है। एनबीआर के निर्यातकों से संबंधित जर्मनी के आंकड़े डब्ल्यूटीए में उपलब्ध नहीं हैं और इसके बजाए संगत अवधि में भारत को ईयू के निर्यातों की एक तस्वीर केवल प्रवृत्ति के अध्ययन हेतु दर्शायी गई है।
68. आगे के विश्लेषण में डीजीसीआईएंडएस के सौदावार आंकड़ों का उपयोग जांच अवधि को छोड़कर आयातों की मात्रा और घरेलू मांग के आकलन में किया गया है। जांच अवधि के लिए निर्यातक के आंकड़े प्रयोग किए गए हैं। संबद्ध देशों से पाटित आयातों और अन्य देशों से आयातों की मात्रा के प्रभावों की निम्नानुसार जांच की गई है:

i) आयात संबंधी आंकड़े: आयातों की मात्रा

मात्रा मी.टन में

देश	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
जर्मनी	50	56	43	154
कोरिया गणराज्य	2051	2931	2944	3744
संबद्ध देश	2100	2987	2988	3898
ब्राजील	365	713	380	334
ईयू (जर्मनी को छोड़कर)	2230	2849	1114	2178
चीनी ताइपेई	88	343	120	128
अन्य देशों से पाटन	2684	3905	1814	2640
कुल पाटित आयात	4784	6892	4802	6538
जो पाटन नहीं कर रहे हैं	802	797	878	1889
कुल	5587	7689	5680	8427

प्रतिशत हिसा

देश	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
जर्मनी	0.69	0.73	0.78	1.82
कोरिया गणराज्य	36.70	38.12	53.73	44.43
संबद्ध देश	37.80	38.84	54.52	46.28
ब्राजील	6.54	9.28	8.94	3.86
ईवू (जर्मनी को छोड़कर)	39.92	37.05	20.34	25.84
चीनी ताइपेई	1.58	4.48	2.19	1.52
अन्य देशों से घाटन	48.04	50.79	29.46	31.32
कुल घाटित आयात	85.64	89.63	83.98	77.58
जो घाटन नहीं कर रहे हैं	14.35	10.37	16.02	22.42
कुल	100	100	100	100

आयातों की मात्रा की प्रवृत्ति

देश	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
जर्मनी	100	112	87	308
कोरिया गणराज्य	100	143	144	183
संबद्ध देश	100	142	142	186
ब्राजील	100	195	104	91
ईवू (जर्मनी को छोड़कर)	100	128	50	98
चीनी ताइपेई	100	388	138	145
अन्य देशों से घाटन	100	146	60	98
कुल घाटित आयात	100	144	96	137
जो घाटन नहीं कर रहे हैं	100	99	109	235
कुल	100	138	98	151

69. प्राधिकारी ने नोट किया कि जर्मनी से एनबीआर के आयात क्षति अवधि के शुरुआती वर्षों की तुलना में जांच अवधि के दौरान काफी बढ़ गए हैं जबकि कोरिया से एनबीआर के आयात, जो हमेशा से अधिक रहे हैं, जांच अवधि के दौरान और अधिक बढ़ गए हैं। इस प्रकार संबद्ध देशों से कुल आयात 2100-मी.टन. से बढ़कर लगभग 3900 मी.टन हो गए हैं। अन्य यूरोपीय संघ के देशों ब्राजील, मेक्सिको और चीनी ताइपेई से एनबीआर के आयात को पृथक रूप से तालिकाबद्ध किया गया है। परंतु क्षति अवधि में मेक्सिको से कोई आयात नहीं हुए थे। यद्यपि इन घाटित आयातों में उत्तर-बढ़ाव की प्रवृत्ति दर्ज हुई है, तथापि ये क्षति अवधि के दौरान लगभग 2600-2700 मी.टन के स्तर पर अपेक्षाकृत स्थिर रहे हैं। संघर्षी घाटित आयातों में इस प्रकार लगभग 400 मी.टन से 6500 मी.टन तक की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत को एनबीआर के अन्य देशों से होने वाले निर्यातों की मात्रा भी जांच अवधि में घोषित उछाल के साथ बढ़ी है।

70. गणनाओं से यह भी पता चलता है कि जर्मनी से भारत को एनबीआर के निर्यात क्षति

अवधि के प्रत्येक वर्ष में न्यूनतम सीमा से कम रहे हैं जबकि कोरिया से एनबीआर के निर्यात वर्ष 2003-04 में उत्पाद के कुल आयातों के 38% से बढ़कर 2005-06 में 54% हो गए हैं और 2006-07 में घटकर 44% रह गए हैं। तथापि, संचयी रूप से संबद्ध देशों से पाटित आयात क्षति अवधि के दौरान कुल आयातों का 37.5% से बढ़कर 46% हो गए हैं। पाटन में शामिल अन्य देशों से होने वाले आयातों का हिस्सा 2003-04 में 48% से घटकर 2006-07 में 31% रह गया है जबकि गैर-पाटन देशों से आयात 2003-04 में 14% से बढ़कर 2006-07 में 22% हो गए हैं। इस प्रकार अन्य देशों से पाटन के हिस्से में कमी की पूर्ति संबद्ध देशों और पाटन नहीं करने वाले देशों के बड़े हुए हिस्से द्वारा कर दी गई है। संचयी आयातों का समग्र हिस्सा आधार वर्ष में 86% से घटकर जांच अवधि में 78% रह गया है।

71. आयात मात्राओं की प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि जर्मनी के आयातों में आधार वर्ष में 100 से जांच अवधि में 300 तक की अधिकतम वृद्धि हुई है, परंतु आयातों का आधारभूत आंकड़ा केवल 50 मी.ट. था। कोरियाई आयात आधार वर्ष में 100 से बढ़कर जांच अवधि में 180 हो गए हैं जबकि इनका आधार लगभग 2000 मी.टन था। संचयी रूप से संबद्ध देशों से होने वाले आयात 85 के गुणज के रूप में बढ़े हैं और कुल पाटित आयात आधार वर्ष की तुलना में 37 के गुणज के रूप में बढ़े हैं। ब्राजील और अन्य ईयू देशों, दोनों से होने वाले आयातों की प्रवृत्ति में क्षति अवधि के दौरान गिरावट प्रदर्शित हुई है जबकि चीनी ताइपेई तथा पाटन नहीं करने वाले देशों से आयातों में मात्रा की दृष्टि से वृद्धि हुई है। समग्र आयातों में आधार वर्ष से 50% तक की वृद्धि हुई है।

72. प्रति जांच के लिए प्राधिकारी ने वर्ल्ड ट्रेड एटलस (डब्ल्यूटीए) से आंकड़ों की जांच की है।

डब्ल्यू टी ए के आंकड़ों के अनुसार ई यू और कोरिया गणराज्य से एनबीआर के निर्यात

	2003	2004	2005	2006	2007
ईयू-25 एनबीआर भारत को निर्यात					
मात्रा (मी.ट.)	652	1034	982	712	999
लाख रुपए	338.83	698.96	559.33	440.41	718.07
दर रु./मी.ट. में	51968	67597	56958	61855	71879
दक्षिण कोरिया-निर्यात					
मात्रा मी.ट.)	3778	3822	6209	6518	9736
लाख रुपए	1780.36	2232.70	4655.94	5004.76	7375.78
दर रु./मी.ट. में	47124	58410	74986	76789	75758

कोरिया गणराज्य और यूरोपीय संघ (चूंकि एनबीआर के जर्मनी के निर्यात अलग से उपलब्ध नहीं हैं) से डब्ल्यू टी ए में दर्ज निर्यात संबंधी आंकड़ों से यह पता चलता है कि डब्ल्यू टी ए में दिए गए कोरिया के निर्यात निर्यातकों द्वारा बताए गए आंकड़ों के

काफी निकट है ।

कोरियाई एनबीआर व्यापार के संबंध में डीजीसीआईएस और डब्ल्यूटीए के आंकड़ों में अंतर

	2003	2004	2005	2006
मात्रा (मी.ट.)				
डीजीसीआईएस *	2051	2931	2944	3744
डब्ल्यूटीए	3778	3822	6209	6518
अंतर	-1727	-892	-3265	-2773
दर/मी.ट.				
डीजीसीआईएस *	53841	70468	85769	90066
डब्ल्यूटीए	47124	58410	74986	76789
अंतर	6717	12058	10783	13277

*: वित्तीय वर्ष आधार पर

73. आंकड़ों के दो सेटों अर्थात् डीजीसीआईएस और डब्ल्यू टी ए में दी गई मात्राओं में अंतर दो तालिकाओं में देखा जा सकता है । यद्यपि समयावधियाँ अलग-अलग हैं । डब्ल्यूटीए के आंकड़े कलेंडर वर्ष आधार पर हैं जबकि डीजीसीआईएस के आंकड़े वित्तीय वर्ष के आधार पर । ईयू के निर्यात आंकड़े भारत को निर्यातों की मात्रा की प्रवृत्ति का एक संकेत देते हैं । यद्यपि, 5 वर्ष की अवधि में उनमें उत्तर-चढ़ाव की प्रवृत्ति रही है, तथापि क्षति अवधि के दौरान उनमें गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है । दूसरी ओर कोरियाई आयातों के मामले में विशेष रूप से 2005 में प्रवृत्ति मुख्यतः वृद्धि की रही है । प्राधिकारी ने नोट किया है कि कोरिया गणराज्य से अपेक्षाकृत अधिक निर्यात मात्राओं को सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं किया गया है जिनसे वास्तविक आयातित मात्राओं के पर्याप्त अल्प बीजकीकरण की संभावना का संकेत मिलता है । प्रकरण पश्चात् केकेपीसी ने टिप्पणी की है कि मात्रा की गलत सूचना देने का तात्पर्य यह होगा कि डीजीसीआईएस ने आंकड़ों का ढंग से संग्रहण नहीं किया है या उसने कुछेक खेपों की गणना नहीं की है । डब्ल्यूटीए आंकड़ों के अनुसार प्रति मी.टन दर डीजीसीआईएस के आंकड़ों से कम है ।

आयातों का मूल्य

(लाख रुपए में)

देश	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
जर्मनी	44.14	33.08	41.78	187.37
कोरिया गणराज्य	1104.03	2065.21	2525.2	3372.45
संबद्ध देश	1148.17	2098.29	2566.97	3559.82
ब्राजील	212.04	491.91	326.14	299.88
ईयू (जर्मनी को छोड़कर)	1639.88	2190.53	1323.91	2219.49
चीनी ताइपेई	50.91	264.83	119.12	136.88
अन्य पाटन	1902.83	2947.26	1769.16	2656.25
कुल पाटित आयात	3051.00	5045.55	4336.13	6216.07
जो पाटन नहीं कर रहे हैं	929.33	893.5	1122.77	2275.04

कुल	3980.32	5939.05	5458.91	8491.12
-----	---------	---------	---------	---------

74. जर्मनी के आयातों की इकाई दर में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति रही है लेकिन क्षति अवधि के अंतिम दो वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। गैर-पाटन देशों से इकाई दर की तुलना में जांच अवधि को छोड़कर सभी वर्षों में कम दर देखी गई है। कोरिया के मामले में इकाई कीमत गैर-पाटन देशों से इकाई कीमत की तुलना में लगातार कम रही है जबकि ब्राजील के मामले में यह 2004-05 और जांच अवधि में कोरिया की दर से कम रही है। यद्यपि इनकी मात्रा कोरिया की मात्राओं का 10वां हिस्सा भी नहीं रही है।

दर प्रति मी.टन (रुपए)

देश	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
जर्मनी	88475	59283	96401	121962
कोरिया गणराज्य	53841	70468	85769	90066
संबद्ध देश	54663	70259	85923	91323
ब्राजील	58066	68947	85817	89768
ईयू (जर्मनी को छोड़कर)	73531	76891	118808	101916
चीनी ताइपेई	57636	77181	99267	107189
अन्य पाटन	70904	75465	109588	100633
कुल पाटित आयात	83774	73209	94225	95082
जो पाटन नहीं कर रहे हैं	115806	112114	127883	120410
कुल	71248	77242	99618	100761

75. संबद्ध वस्तुओं की घरेलू खपत/मांग की गणना करने के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री मात्राओं को भारत में होने वाले कुल आयातों में जोड़ा गया है।

मांग का आकलन

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	जांच अवधि II
संबद्ध देश	2100	2987	2988	3898	7367
सूचीबद्ध	100	142	142	186	351
अन्य पाटन	2684	3905	1614	2640	2640
सूचीबद्ध	100	146	60	98	
कुल पाटित आयात	4784	6892	4602	6538	10007
सूचीबद्ध	100	144	96	137	209
जो पाटन नहीं कर रहे हैं	802	797	878	1889	1889
सूचीबद्ध	100	99	109	235	
कुल	5587	7689	5480	8427	11896
सूचीबद्ध	100	138	98	151	213
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	****	****	****	****	****
सूचीबद्ध	100	120	108	107	
आवद्ध खपत	****	****	****	****	****
सूचीबद्ध	100	122	166	181	
मांग	****	****	****	****	****

सूचीबद्ध	100	128	106	131	159
घरेलू उत्पादन	***	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	122	116	124	

जांच अवधि II: निर्यातकों द्वारा बताए गए आंकड़े

मांग में काजार हिस्सा

निम्नलिखित का % हिस्सा (सूचीबद्ध)	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	जांच अवधि II
संबद्ध देश	100	111	134	142	221
अन्य पाटन	100	114	57	76	62
कुल पाटित आयात	100	112	91	105	132
जो पाटन नहीं कर रहे हैं	100	77	103	180	145
कुल	100	107	92	116	134
घरेलू उद्योग की बिक्रिया	100	94	101	82	67
आबद्ध खपत	100	95	156	138	114
% रूप में पाटित आयात					
घरेलू उद्योग की बिक्रिया	100	120	89	128	198
घरेलू उत्पादन	100	118	83	110	169
संबद्ध देशों के आयात का %					
घरेलू उद्योग बिक्री	100	118	132	174	329
घरेलू उत्पादन	100	116	123	150	283

जांच अवधि II: निर्यातकों द्वारा बताए गए आंकड़े

76. प्राधिकारी का यह अवलोकन है कि निर्यातकों के आंकड़ों पर आधारित मांग में संबद्ध देशों से होने वाले एनबीआर के आयातों का हिस्सा डीजीसीआईएंड एस के आंकड़ों से 13% अधिक था। संघयी पाटित आयातों का मांग में हिस्सा 51% था। उत्पाद के कुल आयातों में क्षति अवधि में 45% से 61% की वृद्धि हुई है। जबकि इसके साथ ही घरेलू उद्योग का हिस्सा इसी अवधि के दौरान 49% से घटकर 33% रह गया है। आबद्ध खपत का हिस्सा काफी स्थिर रहा है। घरेलू उद्योग की बिक्रियों के लिए संघयी पाटित आयातों के हिस्से की गणना में क्षति अवधि में प्रतिशत 79% से बढ़कर 154% हो गया है और घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में यह 69% से बढ़कर 116% हो गया है। प्रकटन विवरण के बाद केकेपीसी ने यह माना है कि जांच के अधीन न आने वाले देशों से हुए आयातों को वर्तमान संबद्ध देश के साथ जोड़ा नहीं जा सकता और प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह वर्तमान जांचाधीन देशों से हुए आयातों के प्रभाव का ही निर्धारण करें न कि अन्य का। विधिवत ध्यान देने के बाद यह पाया गया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री और उत्पादन की तुलना में संबद्ध देश से आयातों का हिस्सा क्षति अवधि के दौरान प्रथम मामले में 34% से बढ़कर 114% और दूसरे मामले में 30% से बढ़कर 85% हो गया है। पाटित आयातों का

मात्रात्मक प्रभाव काफी अधिक रहा है ।

ख. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

77. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत कटौती की जा रही है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में पर्याप्त मात्रा में कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा अत्यधिक मात्रा में बढ़ गई होती ।

78. इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की भारित औसत उत्पादन लागत भारित औसत निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) और क्षति रहित कीमत की तुलना संबद्ध देशों से होने वाले आयातों की पहुंच कीमत के साथ इस बात की जांच करने के लिए की गई है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत कटौती या कम कीमत पर बिक्री की जा रही है अथवा क्या ऐसे आयातों द्वारा कीमतों में कमी की गई है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोका गया है जो अन्यथा अत्यधिक मात्रा में बढ़ गई होती । आयातों के पहुंच मूल्य की गणना 1% प्रहस्तन प्रभार और संबद्ध देशों से आयात कीमतों के डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों में बताए गए मूल्य पर लागू मूल सीमाशुल्क को जोड़कर की गई है ।

79. कीमत कटौती का निर्धारण पाटित आयातों के पहुंच मूल्य के साथ घरेलू उद्योग की भारित औसत कारखानागत निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना करके किया गया है जिसमें प्रस्तावित रिबेटों, छूटों, कमीशनो और संदत्त उत्पाद शुल्क को बाहर रखा गया है । कम कीमत पर बिक्री संबंधी विश्लेषण के लिए पाटित आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना संबद्ध देशों की क्षतिरहित कीमत जिसे तर्कसंगत लाभ मार्जिन के साथ उद्योग की सत्यापित लागत और एसजीए खर्चों पर विचार करते हुए निर्धारित किया गया था, के साथ की गई है । कीमत न्यूनकारी और हासकारी प्रभावों की जांच करने के लिए घरेलू उद्योग के एनएसआर की प्रवृत्ति की तुलना बिक्री लागतों के साथ की गई है ।

कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री

(रु./मी.टन में)

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	POI II
सीमाशुल्क %	25	20	15	12.5	12.5
पहुंच मूल्य					
जर्मनी	111699	71851	111969	138579	
कोरिया	67974	85407	99621	102338	99647
संबद्ध देश	69012	85154	99800	103768	100459
पाटन करने वाले सभी देश	73308	83564	99677	101999	
एनएसआर	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	***	***	***	***	***
जर्मनी	***	***	***	***	***

कोरिया	***	***	***	***	***
संबद्ध देश	***	***	***	***	***
पाटन करने वाले सभी देश	***	***	***	***	***
कीमत कटौती %					
जर्मनी	(25-30)%	20-25%	(5-13)%	(25-30)%	
कोरिया	12-17%	3-8%	1-5%	1-5%	6-10%
संबद्ध देश	10-15%	2-7%	1-3%	1-5%	3-8%
पाटन करने वाले सभी देश	5-10%	5-10%	1-3%	3-8%	
एन्गोलाईपी				***	***
कम कीमत पर बिक्री					
जर्मनी				***	***
कोरिया				***	***
संबद्ध देश				***	***
पाटन करने वाले सभी देश				***	
कम कीमत पर बिक्री%					
जर्मनी				(18-23)%	
कोरिया				2-8%	8-13%
संबद्ध देश				3-8%	5-10%
पाटन करने वाले सभी देश				5-10%	

80. संबद्ध देशों और कुल पाटित आयातों के मामले में सकारात्मक कीमत कटौती रही है तथापि, कीमत कटौती के प्रतिशत में लगभग 8% की कमी आई है जब हम केवल संबद्ध देशों के आयातों पर विचार करते हैं और संघर्षी आयातों के लिए यह 3% है। प्रांथ अवधि में संबंधित कम कीमत पर बिक्री का प्रतिशत संबद्ध देशों और संघर्षी आयातों के लिए 9% और 7% था।

81. कीमत न्यूनीकरण की मीजदगी तब होती है जब उद्योग की कीमतें पूर्ववर्ती अवधि के स्तर से कम होती हैं जबकि कीमत मंदीकरण उस समय होता है जब पाटन के कारण कीमत वृद्धि रुक जाती है जो अन्यथा बढ़ गई होती। निम्निका कारण लागत व्ययों को छोड़कर लागत में हुई वृद्धि होता है। निम्नांकित तालिका से यह स्पष्ट है कि कीमत मंदीकरण हुआ है क्योंकि घरेलू उद्योग अपनी कीमत को लागत के अनुपात में बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है। जो वृद्धि क्षति अस्थिर के उत्तराई में अपेक्षाकृत अधिक निविष्टि कीमतों के कारण हुई है। कोई कीमत न्यूनीकरण नहीं हुआ है।

कीमत मंदीकरण

घरेलू बिक्रियों संबंधी मापदंड		2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
बिक्री की लागत	रु./मी.टन	****	****	****	****
प्रयुक्ति	सूचीबद्ध	100	108	126	142
बिक्री कीमत	रु./मी.टन	****	****	****	****

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	128	138
-----------	----------	-----	-----	-----	-----

प्रकटन विवरण के बाद टिप्पणियाँ

82. केकेपीसी ने समूचे क्षति विश्लेषण के निरर्थक माना है क्योंकि कीमत कटौती कम कीमत पर बिक्री तथा कीमत हास का निर्धारण प्रत्येक देश के लिए अलग करने के बजाए संबद्ध देशों से वस्तुओं की कुल मात्रा के लिए किया गया है। तथापि, संघयी निर्धारण हेतु पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II (III) के अनुसार शर्तें पूरी हो गई हैं और केकेपीसी का तर्क गलत है। इसके अलावा, देश-वार विश्लेषण भी किया गया है।

83. घरेलू उद्योग ने कोरियायी निर्यात आंकड़ों के अनुसार आयातों एवं निर्यातों की मात्रा और मूल्य में भारी अंतर का उल्लेख किया है और उसने प्राधिकारी द्वारा निर्धारित आयातों की भारित औसत पहुंच कीमत तथा आयातों की पहुंच कीमत की गणना को समझने में असमर्थता व्यक्त की है। यहां यह उल्लेखनीय है कि मांग का निर्धारण करने और मात्रा एवं कीमत प्रभाव की गणना करने के लिए प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत आयात मात्रा और मूल्य निर्यातक के आंकड़ों पर आधारित हैं और ये घरेलू उद्योग द्वारा अपनी याचिका में दर्शाए गए आंकड़ों से काफी अधिक हैं।

छ.3 क्षति संबंधी अन्य मापदंडों की जांच

84. प्राधिकारी ने अन्य अनिवार्य आर्थिक कारकों की जांच की है और उन संकेतकों की भी जांच की है जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, ये निम्नानुसार हैं:

घरेलू उद्योग के अन्य वास्तविक मापदंड

क्षमता उपयोग और उत्पादन

मापदंड		2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
क्षमता	मी.टन	8500	9300	9300	10575
	प्रवृत्ति	100	109	109	124
आउटपुट/उत्पादन	मी.टन	****	****	****	****
	प्रवृत्ति	100	122	116	124
क्षमता उपयोग	%	****	****	****	****
	प्रवृत्ति	100	112	106	99

85. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन संबंधी आंकड़ों से यह खुलासा होता है कि मौजूदा क्षमता के निर्बाधीकरण और उपकरण लगाने के कारण क्षमता में काफी वृद्धि की गई है। क्षमता में वृद्धि की तर्ज पर क्षति अवधि के दौरान उत्पादन में वृद्धि

हुई है। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि क्षमता में वृद्धि मांग में वृद्धि के अनुरूप की गई थी परंतु वे अपनी उच्च मांग के बावजूद अपनी बिक्री में वृद्धि न कर पाने के मद्देनजर उत्पादन में समानुपाती वृद्धि करने में असमर्थ रहे थे। परिणामस्वरूप कंपनी का क्षमता उपयोग क्षति अवधि के दौरान कमोबेश स्थिर रहा था। तथापि, अंतरिम अवधि में क्षमता में वृद्धि के बावजूद उपयोग प्रतिशत में सुधार हुआ था परंतु पूर्ववर्ती 3 लेखांकन वर्षों की तुलना में जांच अवधि के दौरान इसमें मामूली गिरावट आई थी।

रोजगार और उत्पादकता

मापदंड		2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
उत्पादन	मी. ट.	****	****	****	****
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	112	78
उत्पादकता/कर्मचारी	मी. ट.	****	****	****	****
मजदूरी	लाख/रुपए	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	117	114
मजदूरी/उत्पादन की इकाई	लाख/रुपए	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	92	103	92

86. क्षति अवधि के दौरान प्रति कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि हुई है परंतु यह वृद्धि पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में जांच अवधि में अधिक हुई है। तथापि, उन्नत उत्पादकता के परिणामस्वरूप कंपनी को लाभ नहीं हुआ है तथापि, समग्र रूप से संबंधित उत्पादकता कम प्रतीत होती है इसके अलावा, रोजगार के स्तर में मामूली गिरावट आई है परंतु वेतन और मजदूरी के खाते में व्यय उत्पादन में वृद्धि के कारण 14 के गुणक में बढ़ा है। तथापि, प्रति इकाई उत्पादन की मजदूरी लागत में 8% की कमी आई है।

मालसूची

मापदंड	इकाई	2003-04	2004-05	2005-06	जांच अवधि
औसत स्टॉक	मी. ट.	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	144	221
दैनिक बिक्रियों की संख्या के अनुसार औसत स्टॉक	सं.	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	134	207

87. घरेलू उद्योग के पास तैयार उत्पादों के औसत स्टॉक में क्षति अवधि के दौरान और विशेष रूप से जांच अवधि में वृद्धि प्रदर्शित हुई है।

द्वितीय मापदंड

घरेलू उद्योग का लाभ/हानि

कुल घरेलू बिक्रियां		2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
बिक्री मूल्य	रु./लाख	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	137	138	148
बिक्रियों की लागत	रु./लाख	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	130	136	152
लाभ/(हानि)	रु./लाख	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	59	(71)	(268)
ब्याज	रु./लाख	****	****	****	****
ब्याज और कर से पहले लाभ	रु./लाख	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	209	180	95

लाभ/(हानि) प्रति मी.टन					
बिक्री की लागत	रु./मी.टन	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	126	142
बिक्री कीमत	रु./मी.टन	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	128	138
लाभ/(हानि)	रु./मी.टन	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	49	(66)	(251)
ब्याज	रु./मी.टन	****	****	****	****
ब्याज और कर से पहले लाभ	रु./मी.टन	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	174	149	89

88. इन तालिकाओं की जांच से यह पता चलता है कि यद्यपि घरेलू उद्योग को घरेलू उत्पादन और बिक्रियों में वृद्धि के कारण विचाराधीन उत्पाद के उसके घरेलू प्रचालनों से मिलने वाली बिक्री आय में वृद्धि हुई है तथापि, 2004-05 को छोड़कर उसे घरेलू प्रचालन में घाटा होना जारी रहा है क्योंकि बिक्री लागतों में वृद्धि के अनुपात में निवल बिक्री प्राप्ति में वृद्धि नहीं हुई है। यद्यपि बिक्री की लागत में 42% तक की वृद्धि हुई है, तथापि निवल बिक्री प्राप्ति में केवल 38% की बिक्री हुई है। ब्याज और कर से पहले लाभ यद्यपि सकारात्मक है परंतु क्षति अवधि के दौरान इसमें कमी आई है।

निवेशों पर आय और पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

विवरण	इकाई	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
भ्राज और कर से पहले लाभ	रु./लाख	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	208	160	95
लगाई गई पूंजी (एमएफए)	रु./लाख	****	****	****	****
लगाई गई पूंजी पर आय	%	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	177	131	62

89. आधार वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में जांच अवधि में लगाई गई पूंजी पर आय में गिरावट आई है और इसके परिणामस्वरूप पूंजी निवेश जुटाने की कंपनी की क्षमता में भी गिरावट आई है। तथापि, इस बात का स्मरण किया जा सकता है कि जांच अवधि में कंपनी ने उपकरण लगाकर अपनी क्षमता में वृद्धि की थी।

नकद प्रवाह

		2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
विक्रिया-घरेलू	सी.ट.	****	****	****	****
लाभ/ (हानि)	रु./लाख	****	****	****	****
मूल्यहास	रु./लाख	****	****	****	****
नकद लाभ	रु./लाख	****	****	****	****
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	939	249	(728)

90. पिछले तीन वर्षों की तुलना में जांच अवधि के दौरान नकद लाभों में भारी गिरावट आई है।

वृद्धि

91. आर्थिक मापदंडों की जांच से यह नोट किया जाता है कि क्षमता में वृद्धि के फलस्वरूप कंपनी के उत्पादन और बिक्री मात्रा में सुधार हुआ है। क्षति अवधि के दौरान बिक्री कीमत तथा विक्रियों की लागत, दोनों में वृद्धि प्रदर्शित हुई है, परंतु बिक्री कीमत में वृद्धि लागत में वृद्धि से कम रही है और इसके परिणामस्वरूप कीमत में कमी आई है। जांच अवधि के दौरान लाभ, नकद प्रवाह और निवेश पर आय में नकारात्मक वृद्धि हुई है।

vi). पाटन की मात्रा

92. घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने की क्षमता के रूप में पाटित आयातों की मात्रा के संकेतक के तौर पर पाटन की मात्रा पैरा 48 में दर्शायी गई है ।

vii). घरेलू कीमतों पर प्रभाव डालने वाले कारक

93. लागत संरचना में परिवर्तन, यदि कोई हो, घरेलू उद्योग में प्रतिस्पर्धा और प्रतिस्पर्धी प्रतिस्थापनों की कीमतों की पाटित आयातों से इतर कारकों के विश्लेषण हेतु जांच की गई है जिनसे घरेलू बाजार में कीमतें प्रभावित हो सकती हैं । प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से आयातित सामग्री का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है जिससे भारतीय बाजार में कीमत कटौती हो रही है । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि इस उत्पाद का कोई व्यवहार्य प्रतिस्थापन नहीं है और पूर्ववर्ती अपार इंडस्ट्रीज भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक था और इसलिए घरेलू प्रतिस्पर्धा का कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ।

94. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि एक-दूसरे से और घरेलू उद्योग से साथ-साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले अनेक स्रोतों से पाटित आयात घरेलू बाजार को प्रभावित कर रहे हैं जिनके लिए क्षति का संचयी विश्लेषण किया गया है । यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू बाजार में उत्पाद की अच्छी मांग है ।

95. एक्रिलोनीट्राइट और ब्यूटाडीन एनबीआर के उत्पादन हेतु दो प्रमुख मोनोमर हैं । विश्व भर में इन दोनों की कीमतें बढ़ी हैं जिनके परिणामस्वरूप क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है । तथापि, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत लागत में वृद्धि के अनुरूप नहीं बढ़ी थी ।

छ. 4 अन्य ज्ञात कारक और कारणात्मक संबंध

96. निर्यातक ने यह तर्क दिया है कि चूंकि आयात पहले से शुल्क लागू किए गए अनेक देशों से हो रहे हैं इसलिए इन आयातों के प्रभाव की जांच की जानी चाहिए और इनसे हुई क्षति के लिए कोरिया से आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए । प्राधिकारी ने क्षति संबंधी विश्लेषण के प्रयोजनार्थ सभी पाटित आयातों के मात्रा और कीमत संबंधी प्रभावों की संचयी जांच की है क्योंकि पाटित आयात अनेक स्रोतों से एक साथ भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहे हैं तथा करार के अनुसार जिम्मेदार नहीं ठहराने संबंधी कारक निम्नानुसार हैं :

i) अन्य स्रोतों से आयातों की मात्रा और कीमतें

97. जाच अवधि के दौरान संबद्ध देशों को छोड़कर चीनी ताइपेई, यूरोपीय संघ (जर्मनी को छोड़कर), ब्राजील और मैक्सिको जिनके विरुद्ध पहले से पाटरोधी शुल्क लागू है, समेत अनेक अन्य देशों से आयात हुए हैं । आंकड़े इन देशों से भी पाटन दर्शाते हैं अतः सभी पाटन स्रोतों से आयातों की घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव के विश्लेषण हेतु संचयी रूप से जांच की गई है ।

ii) मांग में संकुचन और/या खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन

98. विद्यार्थीन उत्पाद की कुल घरेलू मांग में आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान लगभग 60% की जबरदस्त वृद्धि प्रदर्शित हुई है। घरेलू बाजार में उत्पाद की खपत की प्रवृत्ति में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है जिसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति के जिम्मेदार ठहराया जा सकता हो।

iii) व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

99. संबद्ध वस्तु मुक्त रूप से आयात योग्य है और घरेलू बाजार में कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं मौजूद नहीं हैं क्योंकि केवल एक घरेलू उत्पादक मौजूद है। संबद्ध वस्तुओं के आयात अनेक देशों से होते हैं जो घरेलू उत्पादक के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। आयातों के एक बड़े हिस्से को पाटित आयात निर्धारित किया गया है। अतः प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उत्पादक संबद्ध देशों समेत अनेक देशों से अनुचित प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है और इसलिए घरेलू उद्योग को हुई वर्तमान क्षति के लिए व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं या विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच उचित प्रतिस्पर्धा को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

iv) प्रौद्योगिकी में विकास और निर्यात निष्पादन

100. प्रौद्योगिकी में विकास या घरेलू उद्योग के उत्पादन की अक्षम पद्धति को घरेलू उद्योग की क्षति का कारण नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास संबद्ध उत्पाद का काफी कम निर्यात कारोबार है। यद्यपि, इसमें जांच अवधि के दौरान निरंतर वृद्धि प्रदर्शित हुई है। निर्यात का मामूली निष्पादन घरेलू उद्योग के निष्पादन पर कोई खास प्रभाव नहीं डालता है।

v) घरेलू उद्योग की उत्पादकता

101. श्रमिक उत्पादन के अनुसार घरेलू उद्योग की उत्पादकता में पर्याप्त सुधार हुआ है और इस प्रकार यह घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने के लिए जिम्मेदार कारक नहीं हो सकता है।

छ.5 क्षति की मात्रा और क्षति मार्जिन

102. प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षतिरहित कीमत की तुलना क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु निर्यातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है। संबद्ध देशों से निर्यातों की भारित औसत पहुंच कीमत और क्षति मार्जिनों को काफी अधिक पाया गया है।

(रू./मी.टन में)

क्षति रहित कीमत		पहुंच मूल्य	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन %
****	जर्मनी	***	***	(15-25)%
	कोरिया			
	केकेपीसी	***	***	8-13%
	एलजीसी	***	***	5-10%
	अन्य	***	***	20-25%
	कुल	***	***	8-13%

ज. पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति की संभावना

103. अधिनियम की धारा 9 क में निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए निर्णायक समीक्षा में यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क को हटाने से पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की आशंका है ।

ज.1 हितबद्ध पक्षकारों के विचार

104. घरेलू उद्योग ने यह बताया है कि किसी निर्णायक समीक्षा जांच में पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना तीसरे देश के बाजारों में निर्यातकों द्वारा पाटन के साक्ष्य, संबद्ध देशों से जारी पाटन, पूर्ववर्ती जांचों में निर्धारण पाटित मार्जिनों, विदेशी उत्पादकों द्वारा मुक्त रूप से निपटान योग्य वर्तमान अधिशेष और संभावित क्षमता विस्तार किए जाने, निर्यातों की वास्तविक और संभावित मात्रा पर विचार करते हुए निर्धारित की जा सकती है । पाटन की संभावना के विश्लेषण हेतु विभिन्न संकेतकों और सेस्टेट (CESTAT) के निर्णयों को सूचीबद्ध किया गया है । महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि क्या कोरिया से अन्य तीसरे देशों को निर्यात कीमत सामान्य मूल्य से कम थी क्योंकि यदि ऐसा होता है तो निर्यातक यदि पाटनरोधी शुल्क हटाए जाते हैं तो भारत में उन मात्राओं को स्थानांतरित करेगा । केकेपीसी ने यह तर्क दिया है कि तीसरे देश की निर्यात कीमत एक संकेतक नहीं हो सकती है क्योंकि हर बाजार अलग होता है और इनकी केवल एफओबी कीमतों कीमतों के आधार पर तुलना नहीं की जा सकती है । इसके अलावा ऐसा विश्लेषण प्रत्येक तीसरे देश के लिए किया जाना अपेक्षित है और न कि तीसरे देश के निर्यातों के भारित औसत के आधार पर । अलग-अलग सहयोगी निर्यातक/उत्पादक के लिए पुनरावृत्ति संबंधी अलग-अलग विश्लेषण किया जाना चाहिए और यह समग्र रूप से निर्यातक देश के लिए नहीं होना चाहिए ।

एलजीसी ने यह माना है कि उन्होंने भारत के लगभग समान कीमतों पर अन्य देशों को संबद्ध सामग्री का निर्यात किया है।

105. केकेपीसी ने यह भी माना है कि पाटनरोधी शुल्क के बावजूद भारतीय उपभोक्ता उनके उत्पाद को खरीदना चाहते हैं ताकि यदि शुल्क को हटाया भी जाता है तो निर्यात कीमत में गिरावट की कोई संभावना न हो। घरेलू उद्योग ने इसे त्रुटिपूर्ण बताया है क्योंकि शुल्क के कारण वर्तमान निर्यातों की मात्रा प्रतिबंधित हुई है और यदि शुल्क को हटाया जाता है तो यह पर्याप्त रूप से बढ़ जाएगी क्योंकि कोरियाई उत्पाद सस्ते हो जाएंगे। अतः यदि (क) घरेलू उद्योग आनुपातिक रूप से अपनी कीमतें घटाता है या (ख) केकेपीसी कीमत में अंतर के कारण अपनी निर्यात बिक्री मात्राओं को बढ़ाता है। ये दोनों विकल्प घरेलू उद्योग की क्षति में वृद्धि कर देंगे।
106. केकेपीसी ने यह घोषित किया है कि उनका क्षमता उपयोग 90% से अधिक है और इसलिए बेसी क्षमता का प्रश्न नहीं उठता है। घरेलू उद्योग ने इंटरनेशनल इस्टीमेट्स ऑफ सिंथेटिक रबड़ प्रोडक्ट्स (आईआईएसआरपी) द्वारा प्रकाशित सूचना का हवाला दिया है जिसमें यह बताया गया है कि 2005 में 50,000 मी.टन से कोरिया की संयुक्त क्षमता बढ़कर 80,000 मी.टन हो गई है। केकेपीसी ने क्षमता में 30,000 मी.टन से 50,000 मी.ट. की वृद्धि की है जो उद्योग द्वारा कंपनी की वैश्विक बाजार पर कब्जा करने की उत्सुकता के रूप में दर्शाया गया है। वैश्विक स्थापित क्षमता के वर्तमान मांग से अधिक होने के बावजूद केकेपीसी ने क्षमता में वृद्धि की है और तीसरे देशों को काफी निर्यात भी किए थे जो यदि शुल्क हटाया जाता है तो भारतीय बाजार में अपनी जगह बना लेंगे। परंतु केकेपीसी ने यह बताया है कि जांच अवधि के दौरान और पूर्ववर्ती दो वर्षों में उनकी क्षमता में कोई वृद्धि नहीं की गई है और यह कि यह क्षमता केवल घरेलू नहीं बल्कि वैश्विक बाजार के लिए भी है। मुद्दा यह है कि क्या निर्यात पाटित कीमतों पर किए गए थे। इसके अलावा घरेलू उद्योग के विचारों के विपरीत कथित क्षति के बावजूद आईआईपीएल द्वारा एलबीआर इकाई की खरीद वैश्विक बाजार पर छा जाने की आईआईपीएल की उत्सुकता को दर्शाती है। इस तर्क को जारी रखते हुए केकेपीसी ने अनुरोध किया है कि वैश्विक समग्र बेसी क्षमता का संदर्भ देने के बावजूद घरेलू उद्योग के पास स्वयं वृद्धि की गई क्षमता है जिस वृद्धि को घरेलू उद्योग ने मांग के प्रतिक्रिया स्वरूप करने का दावा किया है।
107. केकेपीसी ने आगे यह कहा है कि पाटन की संभावना और उसकी पुनरावृत्ति संबंधी विश्लेषण की जांच और निर्धारण प्रत्येक सहयोगी निर्यातक/उत्पादक के लिए अलग से किया जाना चाहिए और यह देश-द्वार आंकड़ों पर आधारित नहीं हो सकता है। तत्पश्चात क्षति की पुनरावृत्ति की जांच की जाने की जरूरत है। पिछले तीन वर्षों से मौजूद पाटनरोधी शुल्क ने यह सुनिश्चित किया है कि कीमत संबंधी सभी विकृतियां सीमाशुल्क की सीमा पर समाप्त कर दी जाती हैं अतः घरेलू उद्योग को जारी क्षति का अर्थ यह है कि इसके लिए अन्य कारक जिम्मेदार है। यदि घरेलू उद्योग अपनी स्थिति

में सुधार नहीं करता है तो इससे उनकी अक्षमता का स्तर पता लगता है। केकेपीसी ने इस तर्क का खंडन किया है कि आर्थिक मापदंडों द्वारा किसी विकृति का संकेत नहीं मिलने पर भी शुल्क जारी रहा है। इसी प्रकार एलजीसी ने यह माना है कि जिस निर्यातक को पाटन करते हुए नहीं पाया गया है उसे किसी जांच में चाहे वह नई हो या समीक्षा हो, पाटनरोधी शुल्क के अधीन नहीं रखा जा सकता है।

108. प्रकटन विवरण के बाद केकेपीसी ने यह बताया है कि हितबद्ध पक्षकारों के विचारों को पुनः प्रस्तुत करते हुए एक विवरण पत्र पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.9 का खुला उल्लंघन है जिसमें प्राधिकारी से यह अपेक्षा की गई है कि यह विचाराधीन अनिवार्य तथ्यों जो ऐसे किसी निर्णय का आधार हैं कि क्या निश्चयात्मक उपाय लागू किए जाएं और क्या इससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होता है, के बारे में हितबद्ध पक्षकारों को सूचित करें। इसी प्रकार घरेलू उद्योग ने आक्षेप लगाया है कि प्रकटन विवरण से पाटन एवं क्षति की संभावना के बारे में तथ्यों के प्रकटन के संबंध में प्राधिकारी की वर्तमान प्रक्रिया की पुष्टि नहीं होती है। तथापि प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष सभी तथ्यों का प्रकटन किया है और केवल तथ्यों के विश्लेषण की सूचना नहीं दी गई है।

ज.2 प्राधिकारी द्वारा जांच

109. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न तर्कों के आलोक में पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। यह देखा गया था कि वर्तमान परिदृश्य में संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में जांच अवधि में भारी उछाल आया है। जिससे जांच अवधि में घरेलू उद्योग के हिस्से में पर्याप्त कटौती हुई है। दूसरी ओर प्राधिकारी ने यह भी नोट किया कि घरेलू उद्योग की क्षमता घरेलू मांग के केवल लगभग आधी है। इसी कारण कमी को पूरा करने के लिए आयातों की अत्यधिक जरूरत है। जहां तक संबद्ध देशों से आयातों के कीमत पर प्रभाव का संबंध है, जांच अवधि में कीमत कटौती और कीमत मंदीकरण तथा कम कीमत पर बिक्री 9% तक रही है जो क्षति रहित कीमत की गणना हेतु सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों पर आधारित है।

110. संभावित परिदृश्य के आकलन में आयात आंकड़ों और दरों के देशवार विश्लेषण से निम्नलिखित मुख्य-मुख्य बातें प्रदर्शित होती हैं:

- कोरिया के मामले में प्राधिकारी नोट करते हैं कि संगत निर्यातक का वर्तमान पाटन मार्जिन ऋणात्मक या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में निर्धारित एकल देश के विशिष्ट सामान्य मूल्य के आधार पर ऋणात्मक या नगण्य निर्धारित किया गया है। उपर्युक्त आधार पर निर्धारण अवशिष्ट पाटन मार्जिन अधिक हैं इसी प्रकार जर्मनी के लिए वर्तमान पाटन मार्जिन ऋणात्मक है।

- भारतीय आयात आंकड़ों के अनुसार 2003-06 की अवधि के लिए कोरिया गणराज्य से हुए आयातों में 27% की वृद्धि दर्ज हुई है और यह वृद्धि दर डब्ल्यूटीए में कोरिया के निर्यात आंकड़ों के अनुसार 15% है। इसी अवधि के लिए डब्ल्यूटीए ने भारतीय आयात आंकड़ों के अनुसार जर्मनी से आयातों की वृद्धि दर 13% थी जिसकी तुलना में भारत को एनबीआर के ईयू के निर्यातों में वृद्धि की दर 2% थी। दोनों देशों में आयातों में कटौती के बजाए वृद्धि के साक्ष्य हैं।
 - दूसरी ओर उत्पाद की प्रति मी. टन दर में वृद्धि जर्मनी के लिए भारतीय आयात आंकड़ों के अनुसार केवल 1% रही थी जबकि ईयू के निर्यात आंकड़ों के लिए यह 4% है और जबकि 2003-06 के लिए कोरिया गणराज्य के लिए यह 10 और 30% रही थी।
 - इस प्रकार दोनों देशों से आयातों की मात्रा बढ़ने की पूरी संभावना है, जबकि भारत को इकाई निर्यात दरें अन्य देशों को निर्यात दरों की तुलना में कम बनी रही हैं।
111. कोरिया गणराज्य से आयातों के जारी रहने की संभावना की जांच भी निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आलोक में की गई है।
- क्षमता और उसके उपयोग के स्तरों को देखते हुए यह नोट किया जाता है कि यदि केकेपीसी और एलजीसी का क्षमता उपयोग 2006 में 100% से अधिक होता है तो निर्यात मात्राओं में वृद्धि को देखते हुए क्षमता में विस्तार की संभावना है। प्रेस में एलजीसी और केकेपीसी के योजनाबद्ध क्षमता विस्तार की रिपोर्टें भी आई हैं।
 - विशेष रूप से जांच अवधि में कुल बिक्रियां उत्पादन स्तरों के आसपास या उनसे अधिक रही हैं, जिससे पुनः क्षमता में विस्तार की संभावना का संकेत मिलता है।
112. एक तथ्य यह भी है कि 10 वर्षों से पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद कोरिया से आयातों में कोई गिरावट नहीं आई है। इसके विपरीत जैसा कि केकेपीसी ने स्वयं स्वीकार किया है, भारत को उनके द्वारा निर्यातित मात्राएं देश में कुल मांग के लगभग 30% के स्तर पर निरंतर विद्यमान रही हैं। क्षति अवधि के दौरान मांग में स्वयं तेजी से वृद्धि हुई है।
113. जर्मनी से आयातों के संबंध में यद्यपि मात्राएं कम हैं, परंतु ऐसा पाटनरोधी शुल्क पहले से लागू होने के कारण हो सकता है। पाटनरोधी शुल्क न केवल उस देश से आयातों पर लगाया गया है बल्कि संपूर्ण ईयू क्षेत्र से होने वाले आयातों पर लागू है।
114. अर्थव्यवस्था की अपेक्षाकृत उच्च वृद्धि दरों के मद्देनजर भारतीय बाजारों की आकर्षक स्थिति आटो और फुटवियर क्षेत्रों की उच्च वृद्धि दर से विशेष रूप से यदि इसे घरेलू

बिक्री कीमत की तुलना में अपेक्षाकृत थोड़ी कम इकाई आयात दर से जोड़ दिया जाता है तो इनमें से किसी भी देश के लिए उत्पाद की किसी बेशी उपलब्धता के लिए यह एक चुम्बक के रूप में कार्य करेगा । अतः प्राधिकारी यह महसूस करते हैं कि कोरिया गणराज्य पर से पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने से भारी मात्रा में आयात होंगे ।

115. घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने के संबंध में प्राधिकारी ने उस कीमत स्तर पर विचार किया है जिस पर शुल्क लागू होने के बावजूद ये वस्तुएं संबद्ध देशों से भारतीय बाजार में प्रवेश कर रही हैं । कोरियाई निर्यातकों द्वारा भारी कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री की जा रही है जबकि जर्मनी से आयातों के मामले में यह ऋणात्मक है । अतः प्राधिकारी का यह निष्कर्ष कि यदि शुल्क हटाया जाता है तो कोरिया से आयात के कारण वर्तमान स्थिति और बदतर हो जाएगी ।

दूसरी ओर जर्मनी के आयातों का मात्रात्मक और कीमत प्रभाव या तो नगण्य है या नकारात्मक है । यह भी देखा जाता है कि जर्मनी की क्षमता कम है और वे पाटनरोधी शुल्क लागू होने की अवधि के दौरान कम मात्रा का निर्यात कर रहे हैं । जर्मनी घरेलू बिक्री कीमत से अधिक कीमत पर निर्यात कर रहा है । इसके मद्देनजर जर्मनी से निर्यातकों के व्यवहार से प्राधिकारी को भारत में पाटित कीमतों पर विचाराधीन उत्पादों के निर्यात किए जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है । यह भी देखा जाता है कि जांच अवधि में पाटन और भारत को जर्मनी से एनबीआर के निर्यातों के कारण क्षति मार्जिन नकारात्मक रहा है ।

झ. निष्कर्ष

116. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों और किए गए अनुरोधों तथा हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के जरिए या अन्यथा उपर्युक्त निष्कर्षों में रिकार्ड किए गए तथ्यों द्वारा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों की जांच करने के बाद और वर्तमान पाटन तथा क्षति की स्थिति और पाटन तथा क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि :

- जर्मनी: पैरा 115 में दर्शायी गई स्थिति के मद्देनजर प्राधिकारी भारत में जर्मनी से एनबीआर के निर्यातों पर मौजूदा पाटनरोधी उपाय को जारी रखने का कोई कारण नहीं देखते हैं ।
- कोरिया गणराज्य: प्राधिकारी नोट करते हैं कि केकेपीसी और एलजी दोनों पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के दौरान भी भारत को एनबीआर का भारी मात्रा में निर्यात कर रहे हैं और निकट भविष्य में उनका काफी अतिरिक्त क्षमता के

सृजन का भी प्रस्ताव है। केकेपीसी और एलजी दोनों की प्रस्तावित अतिरिक्त क्षमताओं के मद्देनजर प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि पाटित कीमतों पर भारत में निर्यात जारी रहने की काफी संभावना है जिससे घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होगी। यदि शुल्क हटाए जाते हैं अथवा कोरिया से होने वाले आयातों के संबंध में कम किए जाते हैं, तो घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

- घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कीमत प्रभाव और अपना बाजार हिस्सा गंवाए जाने के कारण कम प्रति इकाई प्राप्ति की वजह से वास्तविक क्षति होना जारी है।

ट. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

117. पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य सामान्यतः पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल की जा सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपायों को जारी रखने से किसी भी तरह से संबद्ध देश से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए इनसे उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ठ. सिफारिशें

118. इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि घरेलू उद्योग को कोरिया गणराज्य से पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति होना जारी है और यदि शुल्क हटाया जाता है तो कोरिया गणराज्य से होने वाले आयातों के कारण पाटन और क्षति के जारी रहने की संभावना है, प्राधिकारी की यह राय है कि कोरिया से होने वाले आयातों के विरुद्ध इस उपाय को जारी रखना अपेक्षित है। अतः प्राधिकारी दिनांक 1.9.2005 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 78/2005-सी.शु. द्वारा यथाअधिसूचित और दिनांक 31.1.2007 की अधिसूचना सं. 11/2007-सी.शु. द्वारा यथासंशोधित मौजूदा शुल्क को कोरिया गणराज्य से सहयोगी और असहयोगी निर्यातकों, दोनों के संबंध में यथा लागू शुल्क को जारी रखने की सिफारिश करते हैं। चूंकि एलजी ने भी निर्णायक समीक्षा जांच में सहयोग किया है, इसलिए उन्हें सहयोगी निर्यातक अर्थात् केकेपीसी के समतुल्य माना जाएगा। तदनुसार सहयोगी निर्यातकों अर्थात् केकेपीसी और एल जी के लिए अनुशंसित शुल्क 38.73 डॉलर प्रति मी.टन है और कोरिया गणराज्य के असहयोगी निर्यातकों के लिए यह शुल्क 362.75 अमरीकी डॉलर प्रति मी.टन है।

ड. आगे की प्रक्रिया

119. इस आदेश के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

120. प्राधिकारी अधिनियम के संगत प्रावधानों और समय-समय पर इस संबंध में जारी सार्वजनिक सूचनाओं के अनुसार आवधिक रूप से यहां यथा अनुशंसित निश्चयात्मक उपायों को जारी रखने, उनमें संशोधन करने या उन्हें समाप्त करने की जरूरत की समीक्षा कर सकते हैं। ऐसी किसी समीक्षा हेतु कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा, यदि यह अनुरोध हितबद्ध पक्षकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ निर्धारित समय-सीमा के भीतर नहीं किया जाता है।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2008

Final Findings

Subject : Sunset Review (2) of anti-dumping duty imposed on imports of Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR) originating in/exported from Germany and Korea RP

No. 15/6/2007-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules (hereinafter also referred as Rules), 1995, thereof;

A. BACKGROUND

2. WHEREAS, having regard to above Rules, the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) conducted a sunset review of the antidumping duty in force against import of Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR) (hereinafter referred to as subject product/goods) into India from Korea RP and Germany (hereinafter referred to as subject countries), vide initiation notification dated 1st Oct. 2001 on the basis of an application filed by the M/s Apar Industries Ltd, Mumbai, the domestic producer in India.

3. AND WHEREAS, vide Notification No. 50/1/2001 dated 21st September 2002, the Authority, concluded that the cessation of antidumping duty on NBR from Korea RP and Germany will lead to continuation or recurrence of dumping and injury and recommended continued imposition of definitive antidumping duty on imports of the subject goods. Definitive antidumping duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification No. 111/2002-Customs dated 10th October 2002, (superseded by Notifications No. 78/2005- Customs of 1st Sept 2005 and No. 11/2007-Customs of 31st January 2007), for a further period of 5 years from the date of this notification.

4. WHEREAS on the basis of a duly substantiated application filed by M/s. Apar Industries Ltd, Mumbai, the Authority initiated the second sunset review of the anti dumping duty on imports of the subject product originating from the subject countries vide notification dated 8th October 2007 under section 9A (5) of the Act, to examine whether the expiry of the duty would lead to continuation or recurrence of dumping and

5. AND WHEREAS, vide Notification No: 109/2007- Customs dated 9th October 2007, the definitive duties were extended by the Central Government under Section 9A (5) for a period of one year up to 9th October 2008.

B. PROCEDURE

6. The procedure described below has been followed with regard to this investigation:

- i. After initiation of the review, the Authority sent questionnaires, along-with the initiation notification, to all known exporters/producers in the subject countries, and domestic industry in India in accordance with the Rule 6(4), to elicit relevant information;
- ii. The Embassies / Representatives of the subject countries in New Delhi were informed about the initiation of the investigation, in accordance with Rule 6(2), with a request to advise the exporters/producers in their respective countries to respond to the questionnaire within the prescribed time;
- iii. Questionnaires were sent to known importers and consumers of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4);
- iv. Investigation was carried out for the period starting from 01.04.2006 to 31.03.2007 (POI). However, injury examination was conducted for a period from 2003-04 to the POI (inclusive);
- v. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigations;
- vi. Response to the initiation notification was received from two exporters from Korea RP, viz.,
 - a) Korea Kumho Petrochemicals Co: Ltd (hereinafter referred to as KKPC);
 - b) LG Chem Ltd (hereinafter referred to as LGC or LG).

There was no response from any German exporter;

- vii. All India Rubber Industries Association (hereinafter referred to as AIRIA) and All India Federation of Footwear Manufacturers also filed their responses to the initiation notification as interested parties;
- viii. The Authority has considered all views expressed and submissions made by various interested parties to the extent they are relevant for the present investigation;
- ix. The Authority verified the information furnished by the domestic industry to the extent possible to examine the injury suffered and to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of

Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and the information furnished by the applicant so as to ascertain if Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to Domestic Industry;

- x. The Authority held a public hearing on 17.06.2008 to hear the interested parties orally, which hearing was attended by representatives of the domestic industry, exporters of the subject goods from the subject countries and other interested parties. The parties attending the public hearing were requested to file written submissions of views expressed orally. The written submissions received from interested parties have been considered by Designated Authority in this finding;
- xi. The essential facts of the case were disclosed to all interested parties in the form of confidential and general disclosures. Comments of the interested parties on the disclosure statement, to the extent they are relevant and supported by evidence, have been considered by the Authority;
- xii. The Authority kept available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file maintained by the Authority and kept open for inspection by the interested parties. **** in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules on merits.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND "LIKE" ARTICLE.

7. The product involved in the said original investigation was Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR) also known as Nitrile Rubber falling under heading No. 40025900 in Chapter 40 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act and ITC HS Classification. NBR is used in the manufacture of various rubber articles where resistance to oil, abrasion and heat applications are involved, such as oil seals, hoses, automotive products, gaskets, rice de-husking rolls, printers, fabrics, oilfield products, etc. The major raw materials required for NBR are Acrylonitrile and Butadiene. Different grades of NBR are defined in terms of mooney viscosity and acrylonitrile content. However, though there are several grades, the Authority had noted in the original investigation that it would not be appropriate to exclude any grade from the scope of the investigation. This being a sunset review investigation, the scope of the investigation is limited to the product already identified in the original investigation. This classification is however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation. No interested party has extended any argument in the current investigation on the issue of the product under consideration and like article. The subject goods produced by domestic industry are used interchangeably with those imported from the subject countries. Therefore, the Authority holds that the subject goods produced by the domestic industry is "like article" within the meaning of the Rules.

D. STANDING OF THE DOMESTIC INDUSTRY

8. The sunset review has been initiated on the basis of a duly substantiated request submitted by M/s. Apar Industries Ltd, Mumbai, the sole domestic producer of the like article, on behalf of the domestic industry. At the time of filing for review, the production facilities were owned by Apar Industries. In February 2008, M/s Eliokem India Pvt. Ltd. (hereinafter referred to as EIPL) acquired the Synthetic Rubber Plants Polymer unit of Apar Industries by purchase of the production facilities on a going concern basis and assumed responsible for management of production and sale of NBR produced therein.

E. VIEWS OF INTERESTED PARTIES

a) On initiation

9. The domestic industry has claimed that they constitute domestic industry within the meaning of the Rules even if the production facility owned by Apar Industries at the time of filing for review has been acquired by EIPL w.e.f. Feb 2008. KKPC has opined that the acquisition required detailed examination by the Authority and appeared to have been made for leveraging the benefits of anti-dumping duty existing for all NBR supply sources to India. Further, that the high valuation for the NBR business has raised doubts about the veracity of injury claims made by Apar - Eliokem in the sunset review and EIPL should furnish details of valuation, due diligence report, documents filed with SEBI, sale- purchase agreement and any other document relating to the acquisition for examination by the Authority. The domestic industry has contended that acquisitions and mergers are based on the business plans of the acquiring company and have nothing to do with antidumping investigation, which relate to factual information prevailing during the POI. If NBR operations had been profitable, the polymer units would not have been sold by Apar Industries.

10. KKPC has further stated that the injury parameters of the NBR segment of Apar Industries would not hold good for EIPL which was not in existence during the POI of the review. As a new entity came into being using the assets of the old one, the injury parameters of the old entity could not be adopted for the new. Hence, the current review investigation is required to be terminated. Besides, as Apar's petition on which the review was initiated has become infructuous upon sale of assets, the review cannot be continued on a non-existing petition. AIRIA took the view that the review petition was originally filed by Apar Industries, who was no longer the beneficiary and hence the review may be closed and duty withdrawn. The domestic industry has responded that under the Rules, injury was to be analysed for the subject product, not the whole company and for the injury period. Since consequent to EIPL's acquisition of Apar Industries polymer unit, all assets, liabilities, rights, contracts and records has also been adopted by EIPL, the injury parameters relating to NBR would also apply. Further, an investigation once initiated can only be terminated under Rule 14 of the AD Rules only if the Authority received such a request from the domestic industry or was convinced of the absence of evidence of dumping and injury to justify its continuation or the margin of

dumping was less than 2% of the export price or the volume of dumped imports from subject countries accounted individually for less than 3% of the imports of the product.

b) On confidentiality

11. The domestic industry has submitted that the two Korean exporters have provided only selective extracts from the annual reports and has not provided certain appendices on indexed basis. In response, both KKPC and LGC have argued that the domestic industry should first provide a proper non-confidential version of the petition for comments. Since the industry had claimed excessive confidentiality, they could not raise this issue. The appendices mentioned by the domestic industry relate to costing information of the companies, regarding which the domestic industry itself has not filed the non-confidential version of its own costing information. All rules and procedures should apply uniformly to all the parties to the investigation, not just to the exporter. KKPC has stated that they have provided all the publicly available information regarding annual accounts, and did not furnish only the detailed financial statements which were not in public domain.

c) On fixation of duty

12. The domestic industry has submitted that both KKPC as producer-exporter and KKPC as producer in combination with any other exporter attract the same rate of duty, which was incorrect as KKPC with any other exporter should attract the residual rate of duty. However, KKPC has argued that (i) the dumping margin was calculated at the ex-factory level and all transactions to India, whether directly or through any other party, were taken into consideration, so that the rate determined for KKPC should apply to all its transactions, as per the practice of the U.S. Department of Commerce. (ii) As KKPC was aware at the time of sale that the goods are meant for export to India as they move directly to India and only the invoice is raised on the trader, the selling prices represent the export price to India. Hence, KKPC's rate should be applied irrespective of the trader involved.

d) On import statistics

13. KKPC has desired that DGCIS transaction-wise import data may be placed in the public file. In response, the domestic industry has stated that they had no objection, if the Authority wanted to place such data in the public domain and DGCIS had no reservations, but there was no reason why the exporter should want such information as they had their own information on the export price. The Authority communicated willingness to forward a request from the exporter to DGCIS for the information, but no request was received from KKPC.

13.1. Post-disclosure, KKPC has stated that despite no objection by the domestic industry, DGCIS data has not been made public, that KKPC only required that data

furnished by the domestic industry to the Authority which formed the basis for decision should be available in the public file. However, the Authority has not relied on the data provided the domestic industry for making its decisions, but has obtained it from DGCIS after investigations were initiated and all data has been indicated under the volume effect.

c) Non-response in earlier investigations

14. The domestic industry has held that LGC should state the reasons for failure to respond in the past investigations. While disputing the domestic industry's right to ask this, LGC has declared that NBR production started only after the acquisition of LG Daesan Petrochemicals Ltd in January 2005 and its subsequent merger in January 2006. Neither LGC nor its related party owned NBR prior to the acquisition..

e) On the impact on downstream products

15. AIRIA has submitted that the items being manufactured out of NBR are mostly used by the masses and manufactured largely by SSI units. The total direct and indirect employment of the Indian rubber industry is approximately 2 million. Imposing anti-dumping duty to protect a single foreign company at the cost of 2 million workers and the common masses would be a travesty of justice and would fuel further price increase of products meant for the masses and go against the Government's avowed policy to check inflation. Further, rubber products being exported on marginal costing basis, the industry had to have a viable domestic market to sustain its export pricing. With high prices of all oil based products, the industry is already reeling under high input cost and imposition of anti-dumping duty would severely handicap its export prospects. Additionally, the Indian manufacturer did not manufacture all grades of nitrile rubber required by rubber industry, which needed it for manufacture of rubber auto components, the tremendous growth potential of which sector would be jeopardized if its major raw materials are subjected to duties, thereby increasing its input costs.

g) On trade agreements

16. AIRIA has stated that India was in the process of finalizing Asian Pacific Trade Agreement (APTA), seeking preferential tariff on trade with these countries including South Korea on the one hand, while on the other, India sought to impose additional duties on imports of NBR from the same country even though the item is covered under APTA.

Post disclosure comments

(a) On change of name

17. KKPC has requested the Authority to note the correct name of their company as Kumho Petrochemicals Ltd. and use that name in the final findings to avoid creating practical difficulties. However, the Authority noted that it had asked the company in June 2008 to provide a copy of the certificate of incorporation of the new company, the operating structure before and after the change and the pattern of shareholdings, to

facilitate the examination of the change. As these were not furnished, the Authority is constrained to retain the same name as in the response filed by the exporter.

(b) Other aspects

18. Comments of the All India Federation of Rubber Footwear Manufacturers have been disregarded as they were not in relation to the facts contained in the statement.

E.2 Examination by the Authority

19. The Authority has carefully examined various submissions made by the interested parties in connection with the initiation of this review investigation and the documents relating to the change of ownership of the NBR production facility. Since all assets and liabilities of Apar Industries Polymers unit have been acquired by EIPL, the Authority holds that EIPL constitutes the domestic industry for the purpose of the current investigation. In addition, all other arguments raised during the investigation and in submissions by interested parties have also been examined by the Authority to the extent they are relevant to the investigation and analysed at appropriate places in the findings.

F. DUMPING DETERMINATION

20. Section 9A (5) read with Rule 23 of the Anti Dumping Rules provides that the Designated Authority shall, from time to time, review the need for continued imposition of anti dumping duty and if it is satisfied on the basis of information received by it that there is no justification for the continued imposition of such duty, shall recommend to the Central Govt. for its withdrawal. Hence, the issues before the Authority are to examine

- ❖ Whether dumping is likely to continue or recur, if definitive duties are removed or allowed to expire;
- ❖ Whether injury to the domestic industry is likely to continue or recur, if definitive duties are allowed to expire or are removed.

The issues have been examined in the ensuing paragraphs.

F.1 Views of interested parties

a) On costs of production

21. The domestic industry has submitted that the exporter, KKPC undertook significant production and purchase of butadiene. 50% of its butadiene requirement is purchased, while the rest is captive production. The transfer price of captive butadiene should not be at the cost of production but at the market price to avoid shifting profits of butadiene to downstream products, as per the Supreme Court Judgement in the RIL case. But KKPC has disputed the applicability of the RIL judgement to the price of the raw material on the ground that (i) the judgement applied to the determination of non-

injurious price (NIP) and not normal value and that AD Rules lay down that the cost element in normal value should be determined based on the records of the exporter/producer if these records are in line with the accepted accounting principles of the exporting countries. Further, that valuation of raw materials has been on the basis of moving average and records were in accordance with Korean GAAP. LGC has also stated that in past investigations, DGAD has adopted the cost of production as transfer price in case of captive produced raw materials and as there was no reference to fair market value under the Rules and the domestic industry's interpretation could not be applied to the costs of the exporters.

22. The domestic industry has held that KKPC has wrongly claimed interest cost apportioned to the product with a view to understate cost of production and impact normal value and that interest income cannot be reduced from interest cost. KKPC has denied such set-offs.

23. The domestic industry has charged that KKPC traditionally claimed inland freight without identifying it with individual sales transactions and packing cost not based on actual expenses incurred. KKPC has averred that inland freight claims have been based on actual freight expenses incurred and packing cost calculated on the basis of actual cost incurred.

24. The domestic industry has submitted that (a) KKPC's cost of production should be critically examined in terms of costs of all raw materials, consumption norms, cost of utility, conversion cost, interest costs; (b) that domestic sales should be in the ordinary course of trade; c) that price adjustments should be linked with individual transactions and the cost of production and selling price must be determined net of packing cost in view of past disputes on packing; (d) that the profit-centres approach followed could result in understated cost of production. KKPC has dismissed these arguments as baseless and verifiable by the DA.

25. The domestic industry has claimed that LGC has claimed interest and SOA cost based on actuals as well turnover but they should allocated only on turnover basis. LGC has joined issue stating that their SAP system identified all the costs directly attributable to the product first and apportioned those not identifiable with a product on turnover basis, in line with the fundamental principle of computing product costs.

b) On adjustments

26. The domestic industry has claimed that the normal value for both the Korean exporters should be the same as per Supreme Court judgement in the RIL case, but KKPC has argued that after computing a weighted average normal value for Korea, necessary adjustments may be made to the export price to make it comparable. The domestic industry has counter-argued that comparison of weighted average normal value in Korea at ex-factory level with actual export prices of individual exporters constitutes

fair comparison and KKPC needed to identify all factors affecting price comparability and to quantify the adjustments required to be made on their account to demonstrate the fairness or unfairness of the comparison, which can then be verified by the Authority.

27. The domestic industry has stated that in view of the past history of the exporter, their adjustments claims should be verified before adopting them. KKPC offered to subject these adjustments for verification.

28. The domestic industry has pointed out that in the questionnaire response (i) duty drawback claims should be verified; (ii) common expenses have not been charged to NBR; (iii) details of captive raw material(s) should be separately provided; (iv) pre-FOB adjustment were excessive while those on exports appeared understated. KKPC has countered these arguments as being without merit and has declared that all information furnished was true; that the nature and operating procedures of Indian DEPB and Advance License schemes were different from the drawback schemes of India or Korea and other countries granted adjustments to such claims of drawback made. LGC has supported this argument, holding that it has been a consistent practice of DGAD to grant such adjustments when established to be linked to imports of raw materials and export of the product.

29. The domestic industry has claimed that the Korean exporters have continued to export to India at dumped prices. KKPC has refuted the claim, holding that the verification of their accounts would establish no dumping or any likelihood of dumping. However, the domestic industry has stated that in all investigations conducted, KKPC had claimed no dumping, but the Authority had found dumping above de-minimis. Besides, in spite of imposition of duty, KKPC was the largest supplier to India.

F.2 Republic of Korea

30. Two producer(s)-exporter(s) from Korea RP, viz., Korea Kumho Petrochemicals (KKPC) and LG Chem (LG) had filed their questionnaire response after initiation of the review. The costing data submitted by these co-operating exporters were examined in accordance with the Rules and reports of the examination were made available to the exporters for their comments. The dumping margins in respect of these exporters have been worked out based on the data submitted by the exporters.

31. The Authority notes that the Hon'ble Supreme Court of India, in the Civil Appeal No. 1294 of 2001, M/s RIL Vs Designated Authority & Others, has held that normal value is not exporter-specific but exporting country-specific. In pursuance of the Supreme Court Judgment in the afore mentioned case the normal value of the subject goods for the subject countries have been determined, first for the individual co-operating exporters and then based on the individual normal values, a single weighted average normal value has been worked out for the product under consideration for the exporting country as a whole.

F.2.1 Korea Kumho Petrochemicals Co (KKPC), Korea RP**Normal Value:**

32. KKPC is a limited liability company, a member of the *** Group, established in *** under the Korean Commercial Law. The company is engaged in the manufacture and sale of petrochemical products like synthetic rubber and latex. KKPC merged with *** in *** and acquired the chemical business segment of *** in ***. KKPC's stocks have been listed on the Korean Stock Exchange since 1988. Its corporate office is located in Seoul and its factory producing NBR at Ulsan.

33. The production process involved reacting the two primary raw materials, acrylonitrile and butadiene to produce a liquid polymer, which is then coagulated, dried and packed as NBR bale. Butadiene is produced in-house and purchased locally as well as imported, while acrylonitrile is purchased locally.

34. Cost verification of KKPC and their sales transactions, including various adjustments claimed, were carried out from the data submitted. Accounts are maintained as per the calendar year in the Korean won in line with the Korean accounting system. For NBR, KKPC follows the process cost accounting system. Conversion costs are based on the actuals and added to the raw material costs to calculate actual manufacturing costs. The cost of production has been readjusted due to an error in the manufacturing cost, consideration of selling, general and administrative expenses on turnover basis, disallowance of set-off of interest expenses and its allocation on turnover basis. Following these adjustments, the cost of production worked out US\$ *** per MT.

Post-disclosure comments on costs

34.1 KKPC has accepted the correction to the manufacturing overheads in respect of KNB35L and regretted the error. But they have claimed that the Authority has allocated the total expenses for the company to the product concerned based on turnover. In the absence of reasons for rejection of their cost data, KKPC has been unable to furnish effective comments on the methodology adopted, but considered the changes unwarranted; that the derivation of the unit cost of SGA and financial expenses for domestic NBR sales by dividing the totals by the quantity sold was incorrect and crude and the Authority should follow a three-step process of allocating the amount determined for NBR as a whole to domestic sales based on turnover, re-allocate it to various NBR grades based on grade-wise turnover in the domestic market and derive the unit cost by dividing the grade-wise allocation by the quantity sold. However, the Authority examined the financial expenses and SGA expenses incurred by KKPC, as per data furnished, up to the ex-factory level and observed such expenses to be equally applicable to the subject product irrespective of whether they are meant for domestic or export sales. As only expenses up to the ex-factory level has been considered, the Authority holds the methodology adopted to be correct.

34.2 The domestic industry has reiterated their submission that captive butadiene must be considered at market price, import-export prices of acrylonitrile from Korea compared with the price reported by KKPC, that costs of other raw materials claimed by the exporter in the past were grossly understated. They have stated that the disclosure statement did not comment on the reasonableness of KKPC's information or on the consumption factors claimed by KKPC. However, the Authority has considered their submissions, but in absence of any prima facie and case-specific evidence contrary to it, KKPC's claim has not been rejected. As regards the consumption factor, these have been adjusted for the raw material requirements for a given grade of NBR, wherever the claim of exporter has not been found reasonable.

34.3 Referring to the conversion costs being based on "actuals", the domestic industry has held that since KKPC produced number of products at one location, conversion costs are shared and that KKPC could not reasonably have provided "actual" costs. However, the Authority has examined the response of the exporters that they accumulate the costs at various cost centres and departments, corresponding to the actual production processes or are indirect cost centres that support multiple production processes. Costs incurred in indirect cost centres are allocated to the process cost centres and the cumulated costs are allocated to the products of the particular process. Each month, KKPC calculates the actual cost of raw materials that are used for NBR production. Further, the conversion costs are recorded separately on an actual basis in the cost system. By adding up the raw material and conversion costs of separate components, KKPC calculates the actual cost of manufacturing various products.

34.4 Responding to other issues raised by the domestic industry, the Authority notes that interest income has not been reduced from the interest cost or otherwise for working out cost of production and sales of subject goods, that all SGA expenses upto ex-factory level expenses have been considered and allocated based on turnover for consideration in cost of sales, that packing expenses have not been considered in working out cost of production and sales since these are required to be shown as adjustments for working out ex-factory net selling price for domestic sales as well as export sales and 5% profit on cost of sales (excluding interest) is considered as reasonable profit.

35. KKPC had substantial domestic sales of NBR of **** MT during the period of investigation, meeting the test of sufficiency, both overall as well as grade-wise. Application of the ordinary course of trade test showed that total profit making transactions were only little above *** % of the transactions and did not satisfy the 80-20 test and the Authority had constructed the normal value on the basis of the cost of production plus a reasonable margin of profit.

35.1 In the post-disclosure comments, the domestic industry has indicated that the determination of the dumping margin for the Korean producers did not appear to be correct and desired a review, as the dumping margin had been above de-minimis in the previous investigation, despite subsequent modification by CESTAT and though the raw material prices increased in the current POI relative to the earlier investigation, the export

price had not increased proportionately. Therefore, the dumping margin should have increased.

36. Accordingly, the Authority revisited the calculations and recomputed the normal value, taking into account only the profitable domestic transactions of the grades exported to India.

	Domestic Sales (MT)
Total	***
Grades exported to India	***
Profitable transactions of grades exported	***
(i) as % of total	***
(ii) as % of grades exported	***

The average selling price of these transactions comes to US\$ *** /MT. The adjustments on domestic sales claimed towards inland freight, credit cost and packing charges have been allowed as claimed. Net of adjustments, the weighted average ex factory normal value comes to US\$ *** PMT, as below:

	Domestic Sales	Unit selling price	Adjustments	Ex-factory Normal value
	MT	\$ PMT	\$ PMT	\$ PMT
Profitable transactions	***	***	***	***

Export price

37. During the POI, KKPC has exported *** MT of NBR to India.

The quantity of all sales has been as follows:

NBR Sales (%)	2005	2006	POI
a) Domestic	26	22	20
b) Exports to India	15	14	14
c) Other countries	59	64	65
Total	100	100	100

38. Exports to India have been both direct to the customer or commission agent and indirect, through a trading company, M/s Daewoo International, prices being negotiated for each customer. Inland transportation charges through trucks have been calculated by weighting total charges for all grades sold by the quantity sold to the customer. The product is packed in bags of 35 kgs PB or boxes of 1.05 MT for all sales, costs being computed based on the unit cost of the packing material and the conversion factors for them. The credit terms provided to India include letter of credit as local LC, LC at sight, LC 30 days, LC 60 days and LC 90 days. LC 90 days are the maximum. Also, indirect export sales through Daewoo International reported to be an unrelated trading company,

was ***% of total export sales to India and the net export rates have been lower since certain adjustments like overseas insurance and credit expenses are not incurred.

39. Based on the actual CIF price of exports to India, net export price at the ex-factory level have been worked out after adjustment for ocean freight and insurance, inland freight, commission, customs fees, credit costs and packing as claimed by the company. The average net ex-factory export price has been determined at \$ *** per MT.

Sales	Export price	Adjustments	Ex-factory EP
(in MT)	\$ PMT	\$ PMT	\$ PMT
***	***	***	***

F.2.2 LGChem (LGC), Korea RP

Normal Value:

40. LGC is a corporation, a member of the **** Group, established under the Korean Commercial Law in ***, after being hived off from ****. It merged with LG Daesan Petrochemical Ltd in January 2006, which company in turn was spun off from Hyundai Petrochemical Co: Ltd in January 2005. LGC has been listed in the stock exchange since 2001. It is engaged in the business of petrochemicals and other industrial materials. The main corporate office of LGC is at Seoul and NBR is produced at its Daesan plant.

41. Cost verification of LGC, their domestic sales transactions, including various adjustments claimed, were carried out from the data submitted. The Authority noted that there was a discrepancy in the computation of raw material cost as the actual consumption in the various grades fell below the consumption norms. Therefore, the Authority adjusted the cost of raw materials as per the consumption norms, allowed the conversion costs as indicated by the company and reallocated the general, administrative and interest expenses on turnover basis. Consequently the average cost of production of LGC worked out to \$ *** per MT.

Post-disclosure comments on costs

41.1 LGC has raised strong objection to the rejection/modification of their information by adopting some hypothetical consumption norms in respect of consumption of two main raw materials and has held the re-computation of their production cost of NBR in gross violation of the principle of natural justice and against the past precedence of DGAD. They have stated that it was unclear if DGAD proposed to work out normative cost for LGC or actual cost incurred and that as per Annexure 1(1) of the AD Rules, DGAD was bound to determine normal value based on the records kept by the co-operating exporter/producer, and can use facts available as per Rule 6(8) of the AD rules only in the event of non-co-operation by an interested party. Further, DGAD has violated the provisions of AD Agreement which provides for calculation of actual cost to arrive at normal value and not normative cost based on hypothetical assumptions and that DGAD

has not provided the basis or logic for the consumption norms adopted in calculating the revised cost of raw materials.

41.2 However, as conveyed earlier, the Authority reiterates that the consumption norms adopted are not hypothetical, but are most conservatively adjusted based on the facts available. That both Annexure 1(1) to the AD Rules and Article 2.2.1.1 of the WTO AD Agreement provide for the determination of the cost elements in the context of normal value normally "on the basis of records kept by the producer or exporter... if such records reasonably reflect the cost associated with production and sale of the articles under consideration." If not, the Authority was justified in correcting any distortion in input costs, arising from understated consumption norms or prices, to ascertain the reasonable cost of production or sales. In LGC's case, the Authority has, *prima facie*, found the consumption of major raw materials (ACN & BD) to be understated as (i) actual ACN consumption was lower than the prescribed content for all NBR grades, except one, as seen from LGC's own statement of grade-wise ACN content; (ii) Where similar grades are produced by both LGC and KKPC, the reported consumption levels of LGC are lower than those of KKPC by about ***% in case of ACN and ***% in case of BD; (iii) Though there is no prescribed level for BD content, it is observed from the consumption levels of KKPC and the domestic industry as well as the SION norms, that for a kilogram of NBR, ACN would be as per prescribed norms, the rest being BD, so that total consumption for both inputs would be 2-3 % higher than the output. Therefore, the Authority has held that the understated consumption has distorted raw material costs of NBR produced and has made a conservative adjustment by (a) assuming the grade-wise ACN level indicated by LGC where no comparable grade was available, while the BD consumption was proportionately increased in line with ACN consumption, resulting in an increase in ACN & BD consumption by about ***%, whereas the understatement in BD is upto ***%. (b) adopting the actual consumption of raw materials based on the same grades produced by KKPC, where comparable grades are available.

41.3 LGC has also claimed that their system can handle data for each product group level. All those expenses which can be directly identified to the product concerned have been booked as such to the product, whereas other common overheads are apportioned to the product on turnover basis. The Authority had examined the data furnished and found that the basis of allocation for general and administrative overheads was actual and turnover. It was noted that LGC was a multi-product company and the sales turnover of the subject product constituted just *** % of the total co. turnover. Being generic in nature, general and administration expenses are normally allocated on the basis of turnover, even in determining non-injurious price for the domestic industry. The Authority has adhered to this rule to work out the cost to make and sell.

41.4 LGC has held that interest expenses are included in SGA and had already reported the financial expenses in type-wise costing, that there has been an error in computing the SGA expenses and financial expenses have been double counted in DGAD's calculation. However, the Authority has dealt with interest expenses and SGA

costs separately and has not included interest expenses in SGA costs. There was no error in re-computation of SGA expenses and financial expenses have not been double counted, but shown separate from SGA expenses.

42. Post-disclosure, LGC has expressed surprise that

- Despite plans for on the-spot verification, the Authority decided to conclude the investigation based on table study without a visit
- In spite of all co-operation, LGC has been denied the opportunity to show that the information submitted by them was based on facts and not on incorrect assumptions;
- In the past, DGAD had verified the information of fully cooperating exporter, but in LGC's case, no intimation for modification of consumption norms was given earlier.

However, it is the Authority's prerogative to conduct on-site or table verification of data/information provided by the exporter and satisfy itself as to the accuracy of the information supplied by co-operating interested parties. Besides, the Authority had provided LGC an opportunity to offer comments on the re-computed costs and deny that there has been any violation of the principle of natural justice.

43. LGC had substantial domestic sales of *** MT including various grades of NBR during the period of investigation. On the basis of the cost of production so determined, the ordinary course of trade test conducted on their domestic sales transactions showed that *** % of domestic sales fell below the cost of production. Therefore, the Authority had constructed the normal value on the basis of the cost of production, with a reasonable margin for profits.

	Domestic Sales
	MT
Total	***
Grades exported to India	****
Profitable transactions of grades exported	***
(i) as % of total	***
(ii) as % of grades exported	***

*: Excluding sub-standard goods

43.1 Post disclosure, the domestic industry has queried if off-grade NBR had been excluded for determining normal value or export price or both and if such exclusion had been demanded by the exporters and the reasons for the exclusion.

44. The Authority re-computed the dumping margin, taking account of only the profitable domestic transactions. The average selling price of these transactions comes to US\$ *** /MT. The adjustments on domestic sales claimed towards inland freight, credit cost and packing charges have been allowed. Net of adjustments, the weighted average ex factory normal value comes to US\$ *** PMT, as below:

Profitable transactions	Domestic Sales	Unit price	selling	Adjustments	Ex-factory Normal value
	MT	\$ PMT		\$ PMT	\$ PMT
	***		***	***	***

Export Price

45. During the POI LGC had exported *** MT of NBR to India..

Quantity-wise sales in all markets are as follows:

NBR sales (MT)	2005	2006	POI
a) Domestic	24	23	21
b) Exports to India	1	1	1
c) Other countries	75	76	78
Total	100	100	100

46. Based on the actual CIF price of exports to India, net ex-works export price to India has been worked out after adjusting the CIF export price for ocean freight and insurance, inland freight, commission, credit costs and packing, as claimed by the company. Based on the above weighted average net ex-works export price has been determined as US\$ *** per MT

Sales	Export price	Adjustments	Ex-factory EP
(in MT)	\$ PMT	\$ PMT	\$ PMT
***	***	***	***

F.2.3 Normal value for Korea RP

47. The Authority noted that though there are various grades of NBR being exported by KKPC and LGC, this being a sunset review, the scope of the product remains same as was defined in the original investigation, where all grades were treated as a single product. Therefore, a single average normal value has been computed for both companies and then weighted to arrive at the country-specific normal value, in pursuance of the apex court's ruling in CA No. 1294/2001. This normal value has been compared with the export price for the individual exporters to determine individual dumping margins of the exporters. The normal value so determined is \$ *** per MT.

In \$ per MT	KKPC	LGC	Weighted average
Normal Value	***	***	***

F.2.4 All other exporters from Korea RP

Normal Value

48. As no other exporter from Korea RP made any submission before the Authority in response to this review investigation, in view of the apex court ruling in CA No:

1294/2001, the Authority has used the weighted average normal value at US\$ *** PMT for all other exporters from Korea.

Export price

49. The net export price has been determined based on the lowest export transaction value from Korea of the co-operating exporter after allowing for due adjustment towards transportation, ocean freight commission etc. Net export price works out to US\$ *** per MT.

F.3 Germany

F.3.1 Normal value for Germany

50. As no exporter from Germany responded to the initiation of the review investigation, the Authority has determined the normal value of the subject goods in Germany on the basis of facts available in terms of Rule 6.8 of the Antidumping Rules. The constructed normal value has been based on the cost of production, conversion costs and selling, general & administrative expenses of the domestic industry in India, the prices of the major raw materials based on their export prices from Germany to the rest of the world and on the actual purchase prices of the domestic industry for other raw materials and process chemicals, together with a reasonable margin of profit. Accordingly, the normal value for all exporters from Germany has been determined as US\$ *** per MT.

F 3.2 Export Price for Germany

51. The export price from Germany has been determined based on the weighted average export price reported by DGCI&S during the POI after allowing for admissible adjustments towards ocean freight, insurance, inland freight, and commission on the facts available basis. Accordingly, net ex-works export price for all exporters from Germany has been determined as US\$ *** per MT.

F.4 Dumping Margin

52. The Authority has worked out the dumping margin by making a comparison between the weighted average normal value and export prices at ex-factory level. The dumping margins for the subject countries as follows:

F.4.1 Dumping margin for Korea

53. For the co-operating exporters, the dumping margin has been determined as the difference between the weighted average normal value and the ex-factory export price. For others, the dumping margin has been determined as the difference between the

weighted average *normal* value and the lowest export price of the *co-operating exporter* after adjustments.

F.4.2 Dumping margin for Germany

54. The Authority has worked out the dumping margin by making a comparison between the normal value and export prices at ex-factory level, based on the constructed normal value and the weighted average export price determined for the product as per DGCIS data.

F.5 Dumping margin : Summary

Exporters		Weighted average export price		Weighted average normal value
		US\$ per tonne		US\$ per tonne
KKPC	***	***	***	1.69
LGC		***	***	0.05
All others		***	***	13.42
Germany	***	***	***	-11.01

55. Dumping margins during the POI are negligible or negative, except in the case of other exporters from Korea RP. However, the Authority noted that in a sunset review, current dumping margin is not a material fact and what is required to be examined is the likelihood of recurrence in the event of no dumping during the POI.

Post-disclosure comments

56. KKPC has stated that

- The comparison of the weighted average normal value with their individual export price was inconsistent with the relevant legal provision;
- They had already pointed out the fallacy in the Authority's interpretation of the Reliance judgement and the remedy provided in the Rules to correct the distortion arising thereof;
- The Authority has to harmoniously interpret the statutory provisions (of the Indian AD Law) with the Court decision by considering all available evidence on the costs based on the actual data pertaining to production and sales in the ordinary course of trade by the exporter/producer or the actual amount incurred and realised by the exporter in producing and selling in the domestic market. The weighted average of the actual amounts incurred and realised by the other producers or exporters being investigated can be considered only in the event of non-cooperation.
- Annexure 1.6(i) to the AD Rules mandates a fair comparison between normal value and export price with due allowance for differences which affects price

comparability, which cannot be made unless individual normal values are computed for individual exporters.

- The Court judgement did not require the Authority to determine a single normal single value for the country as a whole and in doing so, the Authority has erred.
- Fair comparison rules have not been followed in arriving at the dumping margin. A WTO panel had held that the principle of fair comparison is applicable only at the time of comparing the export price with the normal value. Adjustments are to be made to either at that time, irrespective of methodology of determining the normal value.
- The use of the word “its” in Section 9(A)(1) in “any article exported from any country at less than its normal value” implied that the normal value should be for the goods for which the dumping margin is being determined, not with a weighted average normal value. A weighted average normal value can be arrived at only when the cost of production of the producers are the same; otherwise differences in cost of production can be taken into account by making suitable adjustment to the export price. Hence, the ex-factory export price arrived at by the Authority has to be adjusted by an amount equal to the difference between the normal value for KKPC and weighted average normal value determined for Korea RP.
- The Authority has to determine the “actual” margin of dumping based on the exporter’s normal value, which is a function of his cost, SGA and profit. Using the costs of some other competing entity is not within the meaning of “actual” cost and the Authority erred in arriving at a single weighted average normal value.
- The weighted average normal value computed has changed the negative dumping margin of KKPC into a positive dumping margin and vis-à-vis for LGC. Rule 18 (2) of the AD Rules contains a proviso that when arriving at weighted average dumping margin the Authority ignore negative or de-minimis dumping margin to ensure that non-sampled companies do not get the benefit of the de-minimis rates, which principle should be a guide in arriving at a weighted average for KKPC and LGC when KKPC has a negative dumping margin.

57. LGC has stated that they had no comments on the disclosure, since even with the application of the cost adjustments related to raw materials and SGA, their dumping margin was negative. But they would like their cost information to be accepted by DGAD.

58. The Authority recomputed the dumping margin, taking cognizance of only the profitable transactions of the two producer-exporter(s) in the grades exported to India. Both exporters have positive, though de-minimis dumping margins.

G. INJURY DETERMINATION

59. Annexure II to the Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of both (a) the volume of the dumped imports and the effect of the

dumped imports on prices in the domestic market for like article and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. Annexure-II (ii) and (iv) provides as under:-

(ii). "While examining the volume of dumped imports, the said Authority shall consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to the effect of the dumped imports on prices ...the designated authority shall consider whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred, to a significant degree.

"(iv). The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments."

G.1.1 Views of the interested parties

60. The domestic industry has submitted that since the subject goods are already attracting antidumping duty, the various economic parameters relating to injury to the domestic industry need not show injury. Nevertheless, they claim that the volume and price effects of dumped imports are substantial, that increased production and capacity in line with the increase in demand only led to increase in inventories, under utilization of capacity and resultant curtailment of production in the POI, that current exports are at dumping prices and that no consumer would import NBR if it was available at lower prices from the domestic producer. Besides, though their conversion costs had declined over the years, intensified dumping from some sources and fresh dumping from new sources have caused injury.

61. The exporters and other interested parties have claimed that the domestic industry did not suffer material injury. KKPC has pointed to the discrepancies in the import statistics given in the petition and Proforma IVA, despite raising this issue at the public hearing. They have indicated their export volumes stagnating at below 30% of total imports in the past eight years, while LGC have declared that they are neither dumping nor undercutting. KKPC has also claimed that the domestic industry had itself admitted that though the demand increased only by 7%, capacity increase was over 20% and that it was the disproportionate increase in capacity which has led to higher fixed cost, inflated NIP and so-called losses in balance sheet. Price undercutting of 1-10% could be due to differences in level of trade. Despite 10 years of protectionist measures, the claim that the domestic industry has not recovered was erroneous and warranted careful scrutiny of

their data. In addition, the whole injury analysis presented by domestic industry was flawed and duties have been in force on imports from other sources, viz., against EU (excluding Germany), Brazil, Mexico from 2005 and against Chinese Taipei from 2000. By domestic industry's own admission, injury was caused by imports from other countries and not subject countries.

62. KKPC has also charged the domestic industry as providing different data sets relating to profits in different investigations, viz., in the final findings of the mid-term review of imports from Korea RP dt. 6.6.2005, from EU, Mexico and Brazil dt. 5.10.2005 and from Chinese Taipei dt. 27.02.2006 and that the data need to be examined in the light of this fact.

63. AIRIA has submitted that as per 2006-07 financial results, Apar Industries was a dividend paying company and had assessed the outlook of the NBR business as positive, in view of growing demand linked to the growth of automobile industry and profitability margins as improving. Besides, the fact that a French company acquired the polymer division of Apar Industries at a substantial price implied the high profit potential of the company. The company has enjoyed protection of anti-dumping duty, and indulged in frequent increases in the domestic price of NBR, taking advantage of their monopoly position. They have also exported NBR to China at lower rates than the import price in India, completely nullifying any argument on continuation of anti-dumping duty. Further, as against the licensed capacity of 15000 MT, annual production was only about 8000 MT, so that they could not cater to the demand of over 20,000 MT. The industry had to face global competition without leaning on protection from the Government.

64. LGC argued that domestic industry was suffering due to its location disadvantage, having to incur heavy expenses to transport raw materials to its factory and that they were operating at an uneconomical capacity, both of which would result in high cost compared to imported product. Besides, the domestic industry could not improve its performance in spite of AD duty in place for ten years.

G.2 Examination by the Authority

65. The Authority has taken note of various arguments raised by various parties in their submissions and the issue of continuation of injury to the domestic industry has been examined in the light of these arguments made before the Authority. Besides, the Authority noted that this was a sunset review of the measure already in force and examined the issue of cumulative assessment of injury to the domestic industry on account of simultaneous dumping from the subject countries, in terms of Annexure II (iii) of the AD Rules and holds that the conditions specified in the said Rules are satisfied in this case for cumulative assessment.

66. The Authority observed that the original duty was imposed on reference price basis and altered to fixed duty in the sunset review. The injury suffered by the domestic

industry and the causal link between the dumped imports and injury to the domestic industry has been examined. It was noted that imports of the subject goods are simultaneously entering the Indian market from several countries apart from the subject countries, including the European Union (excluding Germany), Brazil, Mexico and Chinese Taipei, which have already been treated as dumped imports. Therefore, dumped imports from all such sources have been cumulated for the purpose of examination of the impacts of dumped imports on the domestic industry.

(A) Volume Effect of dumped imports and Impact on domestic Industry

67. Transaction-wise data from DGCIS show that the subject product imports has been reported under customs classifications 40025900. Since the product description is only indicative, all imports of subject goods irrespective of their classification have been included for the purpose of determination of volume, value and average import price. As the exporters from Korea have provided data on their exports to India, which are higher in volume and value as compared to DGCIS data, this data has been adopted for the POI. The details of exports from Korea as shown in the World Trade Atlas are also indicated below. Data on Germany related to NBR exports is not available in the WTA and instead a picture of EU exports to India in the relevant period is shown merely to study the trend.

68. In the analysis that follows, DGCIS transaction data is utilised to assess volume of imports and domestic demand except for the POI, where exporters' data has been used. The effects of the volume of dumped imports from the subject countries as well as imports from other countries have been examined as follows:

i) Import statistics: Volume of Imports

Quantity in MT				
Country	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
Germany	50	56	43	154
Korea RP	2051	2931	2944	3744
Subject countries	2100	2987	2988	3898
Brazil	365	713	380	334
EU (barring Germany)	2230	2849	1114	2178
Chinese Taipei	88	343	120	128
Others dumping	2684	3905	1614	2640
Total dumped imports	4784	6892	4602	6538
Those not dumping	802	797	878	1889
Total	5587	7689	5480	8427

Percentage Share				
Country	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
Germany	0.89	0.73	0.79	1.82
Korea RP	36.70	38.12	53.73	44.43
Subject countries	37.60	38.84	54.52	46.26

Brazil	6.54	9.28	6.94	3.96
EU (barring Germany)	39.92	37.05	20.34	25.84
Chinese Taipei	1.58	4.46	2.19	1.52
Others dumping	48.04	50.79	29.46	31.32
Total dumped imports	85.64	89.63	83.98	77.58
Those not dumping	14.36	10.37	16.02	22.42
Total	100	100	100	100

Trends in quantity of imports

Country	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
Germany	100	112	87	308
Korea RP	100	143	144	183
Subject countries	100	142	142	186
Brazil	100	195	104	91
EU (barring Germany)	100	128	50	98
Chinese Taipei	100	388	136	145
Others dumping	100	146	60	98
Total dumped imports	100	144	96	137
Those not dumping	100	99	109	235
Total	100	138	98	151

69. The Authority noted that NBR imports from Germany have considerably increased in the POI compared to the earlier years of the injury period, while Korean NBR imports which have always been high, has increased even more in the POI. Hence, total subject countries' imports rose from 2100 MT to about 3900 MT. NBR imports from other European Union countries, Brazil, Mexico and Chinese Taipei, have been tabulated separately, but there were no imports from Mexico in the injury period. Though these dumped imports are seen to register a fluctuating trend, they have remained relatively stable at about 2600-2700 MT over the injury period. Cumulated dumped imports thus recorded an increase from about 4800 MT to over 6500 MT. Other country exports of NBR to India have also increased in volume, with a pronounced jump in the POI.

70. The computations also show that NBR exports from Germany to India have been below 2% every year of the injury period while Korean NBR exports rose from 38% of total product imports in 2003-04 to 54% in 2005-06 and fell to 44% in 2006-07. Cumulatively, however, dumped imports from the subject countries increased from 37.6% to 46% of total imports over the injury period. The share of imports from other countries indulging in dumping fell from 48% in 2003-04 to 31% in 2006-07, while imports from non-dumping countries grew from 14% in 2003-04 to 22% in 2006-07. Thus, the decrease in the share of other countries dumping has been appropriated by the increased share of subject countries and countries not dumping. The overall share of cumulated imports fell from 86% in the base year to 78% in the POI.

71. The trend in import volumes indicate that German imports recorded the maximum increase from 100 in the base year to 300 in the POI, but the base figure of imports was just 50 MT. Korean imports grew from 100 in the base year to 183 in the POI from a base of over 2000 MT. Cumulatively, subject countries imports have risen by a factor of 85 and total dumped imports by a factor of 37, relative to the base year. The trend of imports from both Brazil and other EU countries show a fall over the injury period, while those from Chinese Taipei as also from non-dumping countries have increased in volume. Overall imports grew by 50% from the base year.

72. For a counter check, the Authority examined the data from the World Trade Atlas (WTA).

NBR exports from EU and Korea RP as per WTA data

	2003	2004	2005	2006	2007
EU-25 NBR exports to India					
Qty (MT)	652	1034	982	712	999
Rs lacs	338.83	698.96	559.33	440.41	718.07
Rate in Rs/MT	51968	67597	56958	61855	71879
South Korea - Exports					
Qty (MT)	3778	3822	6209	6518	9736
Rs lacs	1780.36	2232.70	4655.94	5004.76	7375.78
Rate in Rs/MT	47124	58410	74986	76789	75758

The export data recorded in the WTA from Korea RP and the European Union, (since German exports of NBR are not separately available), showed that Korean exports contained in the WTA are fairly close to what has been reported by the exporters.

Variation in DGCIS and WTA data on Korean NBR trade

	2003	2004	2005	2006
Qty (MT)				
DGCIS *	2051	2931	2944	3744
WTA	3778	3822	6209	6518
Variation	-1727	-892	-3265	-2773
Rate/ MT				
DGCIS *	53841	70468	85769	90066
WTA	47124	58410	74986	76789
Variation	6717	12058	10783	13277

*: On financial year basis.

73. The variation in volumes in the two data sets, viz., DGCIS and WTA is seen in the two tables, though the time periods differ. WTA data is on calendar year basis versus financial year basis in DGCIS. The EU exports data gives an idea of the trend in volume of exports to India. Though showing a roller coaster movement in the 5-year period, there seems to be a downtrend during the injury period. On the other hand, in the case of

Korean imports, the trend is distinctly an uptrend, particularly marked in 2005. The Authority has noted that the higher export volumes from Korea RP have not been captured in the official statistics, hinting at the possibility of considerable under-reporting of quantities imported. Post-disclosure, KKPC has commented that incorrect reporting of quantity could imply that DGCIS has not properly collated the data or had left out certain shipments. The rate per MT, as per WTA data, is lower than DGCIS data.

Value of imports

(In Rs lakhs)

Country	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
Germany	44.14	33.08	41.78	187.37
Korea RP	1104.03	2065.21	2525.2	3372.45
Subject countries	1148.17	2098.29	2566.97	3559.82
Brazil	212.04	491.91	326.14	299.88
EU (barring Germany)	1639.88	2190.53	1323.91	2219.49
Chinese Taipei	50.91	264.83	119.12	136.88
Others dumping	1902.83	2947.26	1769.16	2656.25
Total dumped imports	3051.00	5045.55	4336.13	6216.07
Those not dumping	929.33	893.5	1122.77	2275.04
Total	3980.32	5939.05	5458.91	8491.12

74. The unit rate of German imports shows a fluctuating trend, but in the last two years of the injury period, there has been a marked increase. Compared with the unit rate from non-dumping countries, the lower rate is evident in all years barring the POI. In the case of Korea, the unit price has been consistently lower than those from non-dumping countries, while that of Brazil is still lower than the Korean rate in 2004-05 and in the POI, though the volume is barely a tenth of Korean volumes.

Rate per MT (Rs)

Country	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
Germany	88475	59283	96401	121962
Korea RP	53841	70468	85769	90066
Subject countries	54663	70259	85923	91323
Brazil	58066	68947	85817	89768
EU (barring Germany)	73531	76891	118808	101916
Chinese Taipei	57636	77181	99267	107189
Others dumping	70904	75465	109588	100633
Total dumped imports	63774	73209	94225	95082
Those not dumping	115806	112114	127883	120410
Total	71248	77242	99618	100761

75. For calculating the domestic consumption/demand of the subject goods, the sales volume of the domestic industry has been added to the total imports into India.

Assessment of Demand

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	POI II
Subject countries	2100	2987	2988	3898	7367
Indexed	100	142	142	186	351
Others dumping	2684	3905	1614	2640	2640
Indexed	100	146	60	98	
Total dumped imports	4784	6892	4602	6538	10007
Indexed	100	144	96	137	209
Those not dumping	802	797	878	1889	1889
Indexed	100	99	109	235	
Total	5587	7689	5480	8427	11896
Indexed	100	138	98	151	213
Domestic industry sales	***	***	***	***	***
Indexed	100	120	108	107	
Captive consumption	***	***	***	***	***
Indexed	100	122	166	181	
Demand	***	***	***	***	***
Indexed	100	128	106	131	159
Domestic production	***	***	***	***	***
Indexed	100	122	116	124	

POI II: data reported by exporters.

Market share in demand

% share of (indexed)	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	POI II
Subject countries	100	111	134	142	221
Others dumping	100	114	57	75	62
Total dumped imports	100	112	91	105	132
Those not dumping	100	77	103	180	148
Total	100	107	92	116	134
Domestic industry sales	100	94	101	82	67
Captive consumption	100	95	156	138	114
Dumped imports as %					
Domestic industry sales	100	120	89	128	196
Domestic production	100	118	83	110	169
Subj country imports as %					
Domestic industry sales	100	118	132	174	329
Domestic production	100	116	123	150	283

POI II: data reported by exporters.

76. The Authority observed that the share of NBR imports from the subject countries in demand as based on the exporters' data were 13% higher than DGCIS data. Cumulated

dumped imports constituted share of 51% in demand. Total product imports rose from 45% to 61% in the injury period, while concurrently, the share of domestic industry fell from 49% to 33% in the same period. The share of captive consumption remained fairly stable. Computing the share of cumulated dumped imports to domestic industry sales, the percentages rose from 79% to 154% in the injury period and from 69% to 116% relative to domestic industry production. Post-disclosure, KKPC has held that imports from countries not subject to the current investigation cannot be clubbed together with the current subject country and the Authority is mandated to assess the effect of only imports from countries subjected to the current investigation and not of others. Taking due note, the share of subject country imports relative to domestic industry sales and production is seen to rise over the injury period from 34% to 114% in the first case and from 30% to 85% in the second case. The volume effect of dumped imports is quite substantial.

B. Price effect of dumped imports

77. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

78. For the purpose of this analysis, the weighted average cost of production, weighted average Net Sales Realisation (NSR) and the Non-Injurious Price (NIP) of the domestic industry have been compared with the landed price of imports from the subject countries to examine whether there has been significant price under-cutting or under-selling by the dumped imports compared with the price of the like product in India or whether such imports have depressed the prices or prevented price increases that otherwise would have occurred to a significant degree. Landed value of imports has been calculated by adding 1% handling charge and applicable basic customs duty to the value reported in the DGCIS data of import prices from the subject countries.

79. Price under-cutting has been determined by comparing the landed value of dumped imports, with the weighted average ex-factory NSR of the domestic industry, where the rebates, discounts, commissions offered and the excise duties paid have been excluded. For price under-selling analysis, the

landed value of dumped imports was compared with the NIP of the subject goods, determined by taking into account verified cost and SGA expenses of the industry, together with a reasonable profit margin. To examine the price suppression and depression effects, the trend of NSR of the domestic industry has been compared with the cost of sales.

Price under-cutting and under-selling

(in Rs/ MT)

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	POI II
Customs duty %	25	20	15	12.5	12.5
Landed value					
Germany	111699	71851	111969	138579	
Korea	67974	85407	99621	102338	99647
Subject countries	69012	85154	99800	103766	100459
All dumping countries	73308	83564	99677	101999	
NSR	***	***	***	***	***
Price under-cutting	***	***	***	***	***
Germany	***	***	***	***	***
Korea	***	***	***	***	***
Subject countries	***	***	***	***	***
All dumping countries	***	***	***	***	***
Price under-cutting %					
Germany	(25-30)%	20-25%	(8-13)%	(25-30)%	
Korea	12-17%	3-8%	1-5%	1-5%	5-10%
Subject countries	10-15%	2-7%	1-3%	1-5%	3-8%
All dumping countries	5-10%	5-10%	1-3%	3-8%	
NIP				***	***
Price under-selling					
Germany				(***)	
Korea				***	***
Subject countries				***	***
All dumping countries				***	
Price under-selling %					
Germany				(18-23)%	
Korea				2-8%	8-13%
Subject countries				3-8%	5-10%
All dumping countries				5-10%	

80. There is positive price undercutting in the case of subject countries and total dumped imports. However, the percentage of under-cutting has shown about 8% decline when considering only subject countries imports and by 3% for cumulated imports. The respective price under-selling percentages in the POI were 9% and 7% for subject countries and cumulated imports.

81. Price depression is said to exist when the industry's prices are lower than the level of the previous period, while price suppression occurs when dumping prevents price increases that would otherwise take place due to increase in costs, except where cost savings have been made. From the table below, it is evident that price suppression exists, as the domestic industry has not able to increase its prices in proportion with the increase in cost, which increase has been due to the higher input prices in the second half of the injury period. There is no price depression.

Price suppression

Domestic sales parameters		2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	126	142
Selling price	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	114	128	138

Post-disclosure comments

82. KKPC has held the whole injury analysis as flawed, as price under-cutting, under-selling, depression and suppression has been determined for the total volume of goods from the subject countries rather than for each country separately. However, the conditions as per Annexure II (iii) of the AD Rules for cumulative assessment have been met and KKPC's contention is incorrect. Nevertheless, country-wise analysis has also been done.

83. The domestic industry has pointed out huge differences in the volumes and value of exports and imports as per Korean export data and DGCIS import data and expressed inability to understand the calculations of weighted average landed price of imports and reach the landed price of imports determined by the Authority. Here, it is pointed out that the import volumes and values adopted by the Authority for assessing demand and computing the volume and price effects have been based on the exporter's data and are much higher than what the domestic industry had indicated in its petition.

G.3 Examination of other Injury Parameters

84. The Authority has examined the other mandatory economic factors and indices having bearing on the state of the industry as follows:

Other physical parameters of the domestic industry

Capacity utilisation and output

Parameter		2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
Capacity	MT	8500	9300	9300	10575
	Trend	100	109	109	124

Output/ Production	MT	***	***	***	***
	Trend	100	122	116	124
Capacity utilisation	%	***	***	***	***
	Trend	100	112	106	99

85. The production data of the domestic industry during the injury period reveals that there has been substantial capacity addition, due to de-bottlenecking of the existing capacity and addition of equipment. The production has increased over the injury period in line with the increase in capacity. The domestic industry has submitted that the enhanced capacity was in consonance with the increase in demand but they had been unable to increase production proportionately, in view of inability to increase its sales despite higher demand. Resultantly, the capacity utilization of the company has more or less remained constant over the injury period. However, in the interim period, despite capacity increase, the utilisation percentage improved, but it declined marginally during the POI as compared to previous three accounting years.

Employment and productivity

Parameters		2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
Production	MT	***	***	***	***
No. of employees	Nos.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	95	112	78
Productivity / employee	MT	***	***	***	***
Wages	Rs/Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	112	117	114
Wages/ unit of production	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	92	103	92

86. The productivity per employee has increased over the injury period but more in the POI than in the earlier years. However, improved productivity has not resulted in profitability to the company. Overall however, relative productivity appears to be low. Further, the employment level has declined marginally, but the expenses on account of salary and wages have increased about a factor of 14 due to increase in production. However, the wage cost per unit of production has come down by 8%.

Inventories

Parameter	Unit	2003-04	2004-05	2005-06	POI
Average stock	Mt	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	121	144	221
Average stock in terms of No. of days sales	Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	101	134	207

87. Average stock of finished products with the domestic industry showed increase over the injury period and particularly in the POI.

Financial parameters

Profit/loss of the domestic industry

(In Rs.lacs)

Total domestic sales	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
Sales Value	***	***	***	***
Trend (Indexed)	100	137	138	148
Cost of Sales	***	***	***	***
Trend (Indexed)	100	130	136	152
Profit/(Loss)	***	***	***	***
Trend (Indexed)	(100)	59	(71)	(268)
Interest	***	***	***	***
Profit before Interest & Taxes	***	***	***	***
Trend (Indexed)	100	209	160	95

Profit /(Loss) per MT

Cost of Sales	***	***	***	***
Trend (Indexed)	100	108	126	142
Selling price	***	***	***	***
Trend (Indexed)	100	114	128	138
Profit/(Loss)	***	***	***	***
Trend (Indexed)	(100)	49	(66)	(251)
Interest	***	***	***	***
Profit before Interest & Taxes	***	***	***	***
Trend (Indexed)	100	174	149	89

88. The examination of these tables reveals that though the sales revenue of the domestic industry from its domestic operations of the product under consideration has improved due to increase in domestic production and sales, the domestic industry continued to suffer loss from its domestic operations except in 2004-05, as the net sales realisation has not gone up in proportion to the increase in cost of sales. Whereas the cost of sales has gone up by 42%, the net sales realisation has gone up only by 38%. The profit before interest and taxes though positive, has declined over the injury period.

Return on investments and ability to raise capital investment

Particulars	Unit	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
Profit before interest & tax	Rs/Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	209	160	95

Capital Employed (NFA)	Rs./Lacs	***	***	***	***
Return on capital employed	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	177	131	62

89. The return on capital employed has declined in the POI compared to the base year and previous years and as a result, the ability of the company to raise capital investment has also come down.

Cash Flow

		2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
Sales - Domestic	MT	***	***	***	***
Profit/ (Loss)	Rs./Lacs	***	***	***	***
Depreciation	Rs./Lacs	***	***	***	***
Cash Profit	Rs./Lacs	***	***	***	***
Trend	Index	100	939	249	(728)

90. The cash profits have declined significantly during POI as compared to last three years.

Growth

91. It is noted from the examination of the economic parameters that company has shown improvement in production and sales volume as a result of increase in capacity. Both selling price as well as cost of sales has also shown increase over the injury period but increase in selling prices were less than the increase in costs and that have resulted in Price suppression. Profits, cash flow and return on investment have shown a negative growth during POI.

vi) Magnitude of Dumping

92. Magnitude of dumping as an indicator of the extent to which the dumped imports can injure the domestic industry has been presented in para 48.

vii) Factors affecting domestic prices

93. Change in cost structure if any, competition in the domestic industry and prices of competing substitutes have been examined for analyzing the factors other than dumped imports that might be affecting the prices in the domestic market. The Authority notes that landed value of imported material from subject countries is below the selling price of the domestic industry, causing price undercutting in the Indian market. The Authority also notes that there is no viable substitute to this product and the erstwhile Apar Industries was the sole producer of the subject good in India and therefore, domestic competition does not affect the prices.

94. The Authority also notes that dumped imports from several sources competing with each other and with the domestic products are simultaneously affecting the domestic market for which cumulative injury analysis has been done. It is also noted that there is a healthy demand of the product in the domestic market.

95. Acrylonitrile and Butadiene are two principal monomers for production of NBR. Prices of both have increased worldwide, resulting in increase in the cost of production for the domestic industry over the injury period. However, the selling prices of the domestic industry did not increase to the extent of the increase in cost.

G.4 OTHER KNOWN FACTORS AND CAUSAL LINK

96. The exporter have argued that since imports are taking place from several countries already attracting duty, the effect of these imports should be examined and injury should not be attributed to the imports from Korea. The Authority has cumulatively examined the volume and price effects of all dumped imports for the purpose of injury analysis as the dumped imports are simultaneously entering the Indian market from several sources and the non-attribution factors as per the Agreement as follows:

i) Volume and prices of imports from other sources

97. During the POI, other than the subject countries, imports have taken place from several other countries, including Chinese Taipei, European Union (excluding Germany), Brazil and Mexico against which antidumping duty is in force. The data shows dumping from these countries too. Therefore, imports from all dumped sources have been examined cumulatively to analyse the effect of dumped imports on the domestic industry.

ii) Contraction in demand and / or change in pattern of consumption

98. Total domestic demand of the product under consideration has shown a very significant increase by about 60% during the POI compared to the base year. There is no significant change in consumption pattern of the product in the domestic market, which can be attributed to the injury to the domestic industry.

iii) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

99. The subject goods are freely importable and there are no trade restrictive practices in the domestic market, as there has been only one domestic producer. Imports of the subject goods take place from several countries, which compete with the domestic producer, a major portion of the imports having been determined as dumped imports. Therefore, the Authority notes that the domestic producer is facing unfair competition from several countries including the subject countries and the current injury to the

domestic industry cannot therefore, be attributed to trade restrictive practices or fair competition between foreign and domestic producers.

iv) Development of technology and export performance

100. Development of technology or inefficient method of production of the domestic industry cannot be treated as a cause of injury to the domestic industry. Further, the Authority also notes that the domestic industry has small export turnover of the subject product though it shows steady growth during the POI. The insignificant export performance does not impact the domestic industry's performance very much.

v) Productivity of the Domestic Industry

101. Productivity of the domestic industry in terms of labour output has shown substantial improvement and hence is not a factor, which can be attributed to the injury of the domestic industry.

G.5 MAGNITUDE OF INJURY AND INJURY MARGIN

102. The non-injurious price determined by the Authority has been compared with the landed value of the exports for determination of injury margin. The weighted average landed price of the exports from the subject countries and the injury margins have been found to be significant.

Non-Injurious price		Landed value	Injury Margin	IM %
***	Germany	138579	(***)	(15-25)%
	Korea			
	KKPC	***	***	8-13%
	LGC	***	***	5-10%
	Others	***	***	20-25%
	Total	99647	***	8-13%

H. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

103. Section 9A of the Act requires the Designated Authority, in an expiry review, to examine whether cessation of the duty would lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

H.1 Views of the interested parties

104. The domestic industry has stated that the likelihood of continuation or recurrence of dumping in a sunset review investigation can be established by considering the evidence of dumping by exporters in third country markets, continued dumping from the subject countries, dumping margins determined in previous investigations, freely disposable present surplus and potential capacity expansions undertaken by foreign

producers, actual and potential volume of exports. Various indicators to analyse the likelihood of dumping have been listed, as well as decisions of the CESTAT. The critical question was whether export price from Korea to other third countries were lower than normal value, because if so, the exporter would shift those volumes to India if AD duties are revoked. KKPC argued that third country export price may not be an indicator, as every market is different and can not be compared merely based on FOB prices. Moreover, such analysis was required to be done separately for each third country and not on the basis of a weighted average of third country exports. There should be separate recurrence analysis for individual cooperating exporter/producer and not for exporting country as a whole. LGC has held that they had exported the subject material to other countries at almost similar prices as to India.

105. KKPC has also asserted that despite AD duty, Indian customers were willing to pay for their product, so that there was no likelihood of fall in the export price, even if the duty was removed. The domestic industry has dubbed this as fallacious, as the volume of current exports are restricted due to the duty and would increase substantially if duty was removed, so that the Korean product would become cheaper. Therefore, (a) the domestic industry reduces its prices proportionately, or (b) KKPC increases its export sales volumes due to the price difference, either option leading to intensified injury to the domestic industry.

106. KKPC has declared that their capacity utilization has been over 90% and hence there was no question of surplus capacity. The domestic industry has referred to the information published by the International Institute of Synthetic Rubber Products (IISRP), showing that combined capacity of 80,000 MT in Korea from 50,000 MT in 2005. KKPC has enhanced capacity from 30,000 MT to 50,000 MT, which the industry attributes to the company's eagerness to capture the global market. Despite global installed capacities being in excess of current demand, KKPC has enhanced capacity and also had significant exports to third countries, which would find place in the Indian market if duties are revoked. But KKPC has stated that there has been no increase in their capacity during POI and the preceding two years and that capacity was not meant only for the domestic, but also for the global market. The issue was whether the exports were made at dumped prices. Besides, contrary to the domestic industry's assertion, the acquisition of the NBR unit by EIPL despite alleged injury indicated EIPL's eagerness to dominate the global market. Continuing the argument, KKPC has submitted that despite the reference to global overall surplus capacity, the domestic industry itself has increased capacity, which enhancement, the industry has claimed, was in response to demand.

107. KKPC has further stated that the likelihood analysis and recurrence of dumping should be examined and established separately for every cooperating exporter/producer and cannot be based on country-wide data. Thereafter, recurrence of injury needs to be examined. The AD duty in existence for the past 10 years has ensured that all price distortions are removed at the customs border. Therefore continued injury suffered by the domestic industry implied that there are other factors responsible for the same. If the

domestic industry has not improved their condition, it highlighted their level of inefficiency. KKPC refuted the argument that even when the economic parameters do not show any deterioration, duties can be continued. Similarly, LGC has held that the exporter found not to be dumping cannot be put to AD duty in any investigation whether fresh or review.

108. Post-disclosure, KKPC has stated that a disclosure statement containing a reproduction of the views of the interested parties was a gross violation of Article 6.9 of the AD Agreement requiring the Authority to inform all interested parties of the essential facts under consideration which form the basis for a decision on whether to apply definitive measures as well as violative of the principles of natural justice. Similarly, the domestic industry has alleged that the disclosure statement did not conform to the present practice of the Authority with regard to disclosure of facts in respect of likelihood of dumping and injury. However, the Authority has disclosed all the facts to the interested parties and only the analysis of the facts have not been communicated.

H.2 Examination by the Authority

109. The Authority analysed the data on likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in the light of the various arguments presented by the interested parties. It was observed that in the current scenario, the volume of the imports from the subject countries recorded a very significant jump in the POI, substantially cutting into the share of the domestic industry in the POI. On the other hand, the Authority also noted that the domestic industry capacity is just about half the domestic demand, so that imports are inevitably required to meet the shortfall. As regards the effect of subject country imports on prices, there is price under-cutting and price suppression, as well as price under selling of 9% in the POI, based on the Supreme Court orders for computing NIP.

110. In assessing the likely scenario, country-wise analysis of import data and rates shows the following highlights:

- ◆ In the case of Korea, the Authority notes that the current dumping margin of the cooperating exporters have been determined to be positive on the basis of a single country specific normal value determined in pursuance to Supreme Court Judgment. Similarly, the current dumping margin for Germany is negative.
- ◆ Imports from Korea RP registered a growth rate of 27% for the period 2003-06 as per Indian import data and 15% as per Korean export data in the WTA. The rate of growth of imports from Germany as per the Indian import data in the WTA for the same period was 13% vis-à-vis a 2% rate of growth in EU exports of NBR to India. In both countries there is evidence of growing imports, not of reduction.

- ❖ On the other hand, the growth in the rate per MT of the product was merely 1% as per Indian import data for Germany compared to 4% for EU export data while that for Korea RP was 10 & 30% respectively for 2003-06.
- ❖ Thus, the import volumes from Korea RP are set to grow while the unit export rates to India have consistently remained lower than the export rate to other countries.

111. The possibility of continued imports from Korea RP has also been examined in the light of the data provided by the exporters.

- ❖ Looking at the capacity and its utilization levels, it is noted that in the case of both KKPC and LGC capacity utilization have been higher than 100% in 2006, implying the possibility of capacity expansion given the rising export volumes. There are also reports of LGC's and KKPC's planned capacity expansion in the press.
- ❖ Total sales have remained close to production levels or exceeded them, particularly in the POI, which again supports the possibility of capacity expansion.

112. It is also a fact that despite antidumping duty in place for 10 years, the imports from Korea have not shown any decline. On the contrary, as KKPC has itself admitted, the quantities exported by them to India have consistently remained at about 30% of total demand in the country. Demand itself has been growing rapidly during the injury period.

113. As regards imports from Germany although the volumes are small, this could be on account of antidumping duty already in place. Antidumping duty has been levied not only on import from that country but also on imports from the entire EU region.

114. The attractiveness of the Indian market in view of the relatively high growth rates of the economy, the high growth rate of the auto and footwear sectors, would serve as a magnet for any excess availability of the product in any of these countries, particularly if combined with marginally lower unit import rate vis-à-vis the domestic selling price. Therefore, the Authority feels that revoking antidumping duty from Korea RP would lead to large scale imports.

115. As regards the continuation or recurrence of injury to the domestic industry the Authority has considered the price level at which the goods are entering the Indian market from the subject countries in spite of the duty in place. There is significant price under-cutting and price under-selling by the Korean exporters, while these are negative in the case of imports from Germany. Therefore, the Authority concludes that the present situation would change for the worse if the duty is revoked from Korea.

On the other hand, the volume and price effect of German imports is either negligible or negative. It is also seen that capacity of Germany is low and they have been exporting small quantity during the period when anti dumping duty was imposed. Germany has also been exporting at a price higher than the domestic selling price. In view of this behaviour by the exporters from Germany, the Authority does not see a likelihood of exports of the product under consideration taking place at dumped prices into India. It is also seen that in the POI there is negative dumping and injury margins on account of exports of NBR from Germany to India.

I. CONCLUSIONS

116. After examining the issues raised and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority through the submission of interested parties or otherwise as recorded in the above findings and on the basis of the above analysis of the state of current dumping and injury and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury, the Authority concludes that:

- ◆ **Germany:** In view of the position indicated in Para 115, the Authority does not see any reason for continuation of existing anti dumping measures on exports of NBR from Germany into India.
- ◆ **Korea RP:** The Authority notes that both KKPC and LG have been exporting substantial quantities of NBR to India even during the existence of anti dumping duty and have proposals to create reasonably high additional capacities in the near future. In view of the proposed additional capacities of both KKPC and LG, the authority concludes that there is a strong likelihood of exports into India continuing at dumped prices leading to consequential injury to the domestic industry. Injury to domestic industry is likely to continue or recur if the duties are either revoked or reduced in respect of imports from Korea.
- ◆ The domestic industry continues to suffer material injury on account of low per unit realization due to the price effect of dumped imports and erosion of its market share;

J. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

117. The purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Continuation of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

K. RECOMMENDATIONS

118. Having concluded that the domestic industry continues to suffer material injury on account of dumped imports from Korea RP and there is likelihood of continuation of dumping and injury on account of imports from Korea RP if the duties are revoked, the Authority is of the opinion that continuation of the measure is required against imports from Korea. The Authority therefore recommends continuation of the existing duty (as notified vide customs Notification no. 78/2005- Customs dated 01.09.2005 and as amended vide notification no. 11/2007- Customs dated 31.01.2007) in respect of both cooperative and non cooperative exporters from Korea RP as is in place as on date. As LG has also cooperated in the sunset review proceedings, they will be treated at par with another cooperating exporter namely KKPC. Accordingly, the duty recommended is US \$ 38.73 per MT for cooperating exporters namely KKPC and LG and US\$ 362.75 per MT for other non cooperating exporters of Korea RP.

L. FURTHER PROCEDURES

119. An appeal against this order shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

120. The Authority may review the need for continuation, modification or termination of the definitive measure as recommended herein from time to time as per the relevant provisions of the Act and public notices issued in this respect from time to time. No request for such a review shall be entertained by the Authority unless the same is filed by an interested party within the time limit stipulated for this purpose.

R. GOPALAN, Designated Authority